चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

06 जुलाई –12 जुलाई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

फ़र्ज़ी जाति प्रमाण-पत्र पर सीआरपीएफ, बीएसएफ में भर्तियां

हेकड़ी में यादव नौकरी में दलित

ग़ैर दलित जाति के लोग खुद को दलित बताकर बीएसएफ एवं सीआरपीएफ जैसे अर्द्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी महकमों में भर्ती हो रहे हैं. अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र बनवा कर बीएसएफ एवं सीआरपीएफ में नौकरी कर रहे लोगों में अधिकांश यादव जाति के हैं. उत्तर प्रदेश में एक तरफ़ दलित-हित के नाम पर सियासी भाषणबाजी और दुकानदारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ़ दलितों का हक़ छीनने का गोरखधंधा चल रहा है. सरकारी महकमों में अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रमाण-पत्र पर भर्ती का गोरखधंधा अंधाधुंध जारी है.

प्रभात रंजन दीन

दिल्ली सरकार का एक मंत्री फर्जी डिग्री के मामले में जेल में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फर्जी प्रमाण-पत्र पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएनएल और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में धड़ल्ले से भर्तियां हो रही हैं, इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है. जिन्हें ध्यान देना है, वे सब धंधेबाजी में लिप्त हैं. ग़ैर दलित जाति के लोग खुद को दलित बताकर बीएसएफ एवं सीआरपीएफ जैसे अर्द्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी महकमों में भर्ती हो रहे हैं. अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र बनवा कर बीएसएफ एवं सीआरपीएफ में नौकरी कर रहे लोगों में अधिकांश यादव जाति के हैं. उत्तर प्रदेश में एक तरफ़ दलित-हित के नाम पर सियासी भाषणबाजी और दुकानदारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ़ दलितों का हक़ छीनने का गोरखधंधा चल रहा है. सरकारी महकमों में अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रमाण-पत्र पर भर्ती का गोरखधंधा अंधाधुंध जारी है. सीआरपीएफ ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश के 25 युवकों ने फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है. इनमें से 12 युवकों को नौकरी से निकाले जाने की आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन अन्य 13 लोगों का कोई पता ही नहीं चल रहा है कि वे सीआरपीएफ की किस इकाई में और किस स्थान पर तैनात हैं. इस तरह के सैकड़ों युवक हैं, जो बीएसएफ एवं सीआरपीएफ समेत अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ, बीएसएनएल और अन्य विभाग इस मसले पर कन्नी काट रहे हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर इस फर्जीवाड़े की पुष्टि हो चुकी है. बीएसएफ ने ऐसा केवल एक मामला पकड़ने का दावा किया है, जबकि सीआरपीएफ ने पारदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए जिन 12 युवकों को बर्खास्त किए जाने की आधिकारिक पुष्टि की है, उनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश के एटा व अलीगंज के रहने वाले हैं और ज़्यादातर यादव एवं अहीर जाति के हैं, जो दलित बनकर नौकरी कर रहे थे. बीएसएफ ने फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर भर्ती हुए अशोक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जबकि सीआरपीएफ ने अमर सिंह को न केवल नौकरी से निकाला, बल्कि जालसाजी के आरोप में उसे गिरफ्तार भी किया.

सीआरपीएफ से बर्खास्त किए गए युवकों में सतीश चंद (फोर्स नंबर: 980460027), मुकेश चंद (फोर्स नंबर: 961400529), अशोक कुमार (फोर्स नंबर: 971400177), रवींद्र सिंह (फोर्स नंबर: 041727822), अशोक कुमार (फोर्स नंबर: 045268359), यशपाल सिंह (फोर्स नंबर: 971180712), ब्रजेश कुमार (फोर्स नंबर: 045181689), यदुवीर सिंह (फोर्स नंबर: 031310963), वीरपाल सिंह (फोर्स नंबर: 980030814), नीरज कुमार (फोर्स नंबर: 005263491), अमर सिंह (फोर्स नंबर: 951360181) और यतेंद्र सिंह (फोर्स नंबर: 991150431) शामिल हैं. यह सीआरपीएफ की आधिकारिक (ऑफिशियल) सूचना है. बीएसएफ एवं सीआरपीएफ जैसे महत्वपूर्ण अर्द्धसैनिक बलों और बीएसएनएल जैसे केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान में अनुसूचित जाति के कोटे पर पिछड़ी जाति के लोगों की भर्ती के जो आंकड़े उजागर हो पाए हैं या जिनके बारे में आधिकारिक पुष्टि हुई है, वे तो महज कुछ उदाहरण हैं. वह भी उत्तर प्रदेश के दो-तीन ज़िलों का ही फर्जीवाड़ा अभी आधिकारिक तौर पर पकड़ में आया है. एक सरकारी मुलाजिम ने ही बताया कि अकेले एटा से छह सौ से भी अधिक फर्जी जाति प्रमाण-पत्र जारी हुए. यह धंधा प्रदेश भर में चल रहा है. असलियत यह है कि पिछड़ी जातियों के लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति का फर्जी प्रमाण-पत्र हासिल कर हज़ारों की तादाद में बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएनएल और अन्य सरकारी विभागों में भर्ती हो रहे हैं.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दलित बनकर नौकरी कर रहे पिछड़ों की आधिकारिक सूची

1. शिवनंदन पुत्र कश्मीर सिंह-कठिंगरा-अहीर-सीआरपीएफ
2. मुकेश चंद पुत्र कृपाल सिंह-टिकाथर-यादव-बीएसएफ
3. अशोक कुमार पुत्र बृजराज सिंह-जालिम धुमरी-अहीर-बीएसएफ
4. कृष्णवीर सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह-मुकटीखेड़ा-अहीर-बीएसएफ
5. पुष्पेंद्र कुमार पुत्र पुत्तू सिंह-शेखपुरा-यादव-सीआरपीएफ
6. नरेंद्र सिंह पुत्र राम निवास-जैथरा-अहीर-सीआरपीएफ
7. सुशील कुमार उर्फ ब्रजेश पुत्र बदन सिंह-परौली, सुहागपुर-अहीर-बीएसएफ
8. रवींद्र सिंह पुत्र तारा चंद-परौली, सुहागपुर-अहीर-सीआरपीएफ
9. यदुवीर सिंह पुत्र अच्छे लाल-कठिंगरा-अहीर-सीआरपीएफ
10. जसवीर सिंह पुत्र चंद्रपाल-गढ़िया अहिरान तरंगवा-अहीर-बीएसएफ
11. अशोक कुमार पुत्र अमर सिंह-तरंगवा-अहीर-बीएसएफ
12. ध्यान सिंह पुत्र राम चंद्र-तरंगवा-अहीर-बीएसएफ
13. अशोक पुत्र अनार सिंह-तरंगवा-अहीर-बीएसएफ
14. सुभाष चंद्र पुत्र सूरज पाल सिंह-भाऊपुर-अहीर-बीएसएफ
15. नीरज कुमार पुत्र हाकिम सिंह-लाडमपुर कटारा-अहीर-सीआरपीएफ
16. देशराज पुत्र हाकिम सिंह-भलौल-अहीर-सीआरपीएफ
17. अमर सिंह पुत्र हर नारायण सिंह-एटा-अहीर-सीआरपीएफ
18. यतेंद्र सिंह पुत्र शेषपाल सिंह-एटा-अहीर-सीआरपीएफ
19. राम वृक्ष यादव पुत्र राजवीर सिंह यादव-एटा-यादव-सीआरपीएफ
20. महेश पाल पुत्र रघुनाथ सिंह-फगनौल-गड़रिया-सीआरपीएफ
21. सतीश चंद्र पुत्र दफेदार-परौली, सुहागपुर-गड़रिया- सीआरपीएफ
22. राम करन पुत्र राम औतार-फगनौल-गड़रिया-सीआरपीएफ
23. यशपाल पुत्र सूरज पाल-फगनौल-गड़रिया-सीआरपीएफ
24. वीरपाल सिंह पुत्र खेतपाल सिंह-फगनौल-गड़रिया-सीआरपीएफ
25. सतीश चंद्र पुत्र राम लड़ैते-फगनौल-गड़रिया-सीआरपीएफ
26. गिरीश चंद्र पुत्र राम लड़ैते-फगनौल-गड़रिया-सीआरपीएफ
27. उमेश चंद्र पुत्र राम औतार-फगनौल-गड़रिया-सीआरपीएफ
28. प्रवेश कुमार पुत्र बलराम-फगनौल-गड़रिया-सीआरपीएफ
29. सुशील कुमार पुत्र धर्मपाल-भदुइया मठ-गड़रिया-बीएसएनएल
30. संग्राम सिंह पुत्र सौदान सिंह-उमेद-शाक्य-बीएसएनएल
31. देवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र राम रछपाल सिंह-रामनगर-नाई-सीआरपीएफ

वीपी सिंह का जन्मदिवस किसान दिवस घोषित हो | P-3

ललित मोदी प्रकरण : भाजपा के अंदर मचे शीत युद्ध का नतीजा है | P-4

व्यापमं के बाद अब डीमेट घोटाला... | P-7

फर्जी जाति प्रमाणपत्र पर सीआरपीएफ, बीएसएफ में भर्तियां

हेकड़ी में यादव, नौकरी में दलित

पृष्ठ 1 का शेष

इस गोरखधंधे में प्रदेश सरकार से लेकर अर्द्धसैनिक बल और केंद्रीय सरकारी विभागों के अधिकारियों तक की मिलीभगत है. उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारी इसे सख्ती से ऊपर इसलिए नहीं बढ़ाते, क्योंकि इसमें प्रशासन के ही अधिकारी फंस जाएंगे. ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें संबंधित ज़िला प्रशासन ने छानबीन की, फर्जी प्रमाण–पत्रों पर की गईं नियुक्तियां पकड़ीं, उनके बारे में संबंधित विभागों को सूचित भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. प्रशासन कहता है कि सीआरपीएफ एवं बीएसएफ के महानिदेशकों को इस बारे में लिख दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद फर्जी लोग बाकायदा नौकरी कर रहे हैं. सवाल यह भी उठा कि जब ज़िला प्रशासन की छानबीन में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी आधिकारिक सूचना मिल गई, तो फिर केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालयों को इस बारे में सूचित क्यों नहीं किया गया? सैकड़ों ऐसे लोगों के नाम मिले हैं, जो अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण–पत्र लेकर बीएसएफ एवं सीआरपीएफ में भर्ती हो गए हैं. 34 लोगों के बारे में संबंधित ज़िला प्रशासन द्वारा की गई छानबीन की रिपोर्ट चौथी दुनिया के पास है. इनमें से 31 के बारे में आधिकारिक पुष्टि हो गई है. इनमें 19 लोग यादव या अहीर जाति के हैं और अनुसूचित जाति के नाम पर बीएसएफ एवं सीआरपीएफ में नौकरी कर रहे हैं. बाकी 12 लोग भी पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं. इनमें से दो लोग बीएसएनएल में हैं. यानी प्रशासन की जांच में आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि हुई कि पिछड़ा वर्ग से आने वाले इन 31 लोगों ने तहसील से अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण–पत्र प्राप्त किया और उसके आधार पर अर्द्धसैनिक बलों में नौकरी हासिल कर ली. सरकारी जांच में पाया गया कि अलीगंज और एटा की तहसील से फर्जी प्रमाण–पत्र जारी हुए थे, लेकिन फर्जी प्रमाण–पत्र जारी करने वाले सरकारी अधिकारियों–कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. ज़िला प्रशासन कहता है कि बीएसएफ एवं सीआरपीएफ के महानिदेशकों को इस बारे में इत्तिला कर दी गई है. बीएसएनएल में हुई नियुक्तियों के बारे में तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा.

सीआरपीएफ ने जिस अशोक कुमार पुत्र चंद्रपाल सिंह को बर्खास्त किए जाने की बात कही है, उसका नाम ज़िला प्रशासन की तरफ़ से कन्फर्म की गई सूची में नहीं है. इसी तरह बर्खास्तगी वाली सूची में शामिल रवींद्र सिंह एवं यदुवीर सिंह, दोनों के पिता का नाम सूची में नहीं है. ब्रजेश कुमार पुत्र रछपाल सिंह का नाम सीआरपीएफ की सूची में है, लेकिन ज़िला प्रशासन की सूची में नहीं है. सीआरपीएफ महानिदेशालय की तरफ़ से ऑल इंडिया एससी–एसटी इम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हरपाल सिंह को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सीआरपीएफ एवं बीएसएफ में फर्जी जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर भर्ती हुए लोगों में उत्तर प्रदेश के 34 लोगों के नाम आए हैं. इनके बारे में औपचारिक जांच–पड़ताल करके संबंधित ज़िला प्रशासन ने सूची जारी की है, लेकिन इनमें से सीआरपीएफ में भर्ती 12 लोगों का ही पता चल पाया है, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है. सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन में तैनात प्रवेश कुमार पुत्र बलराम के जाति प्रमाण–पत्र की जांच की जा रही है. इसके लिए एटा के ज़िलाधिकारी से भी अनुरोध किया गया है. लिहाजा, यह मामला अभी लंबित है.

सीआरपीएफ महानिदेशालय ने कहा है कि उसकी विभिन्न बटालियनों में भर्ती शिवनंदन पुत्र कश्मीर सिंह (कठिंगरा), महेश पाल पुत्र रघुनाथ सिंह (फगनौल), पुष्पेंद्र कुमार पुत्र पंत सिंह (शेखपुरा), नरेंद्र सिंह पुत्र राम निवास (जैथरा), राम करण पुत्र राम अवतार (सुहागपुर), वीरेंद्र सिंह पुत्र मैकू लाल (पहाड़पुर), सतीश चंद पुत्र राम लड़ैत (फगनौल), गिरीश चंद पुत्र राम लड़ैत (फगनौल), उमेश चंद पुत्र राम औतार (फगनौल), मिट्ठू लाल पुत्र मधुरी लाल (गणपतिपुर, बड़ापुर), देवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र राम लछपाल सिंह (रामनगर हलवानपुर), देशराज पुत्र हाकिम सिंह (भलोल) और राम बख्श पुत्र राजवीर सिंह यादव (एटा) के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है. सीआरपीएफ ने उत्तर प्रदेश शासन से इस सिलसिले में विस्तृत छानबीन करने को कहा है. सीआरपीएफ में ही भर्ती ब्रजेश कुमार पुत्र रछपाल (बलदेव, फगनौल) का भी अता–पता नहीं चल पा रहा है. एसोसिएशन से भी इस सिलसिले में मदद मांगी गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

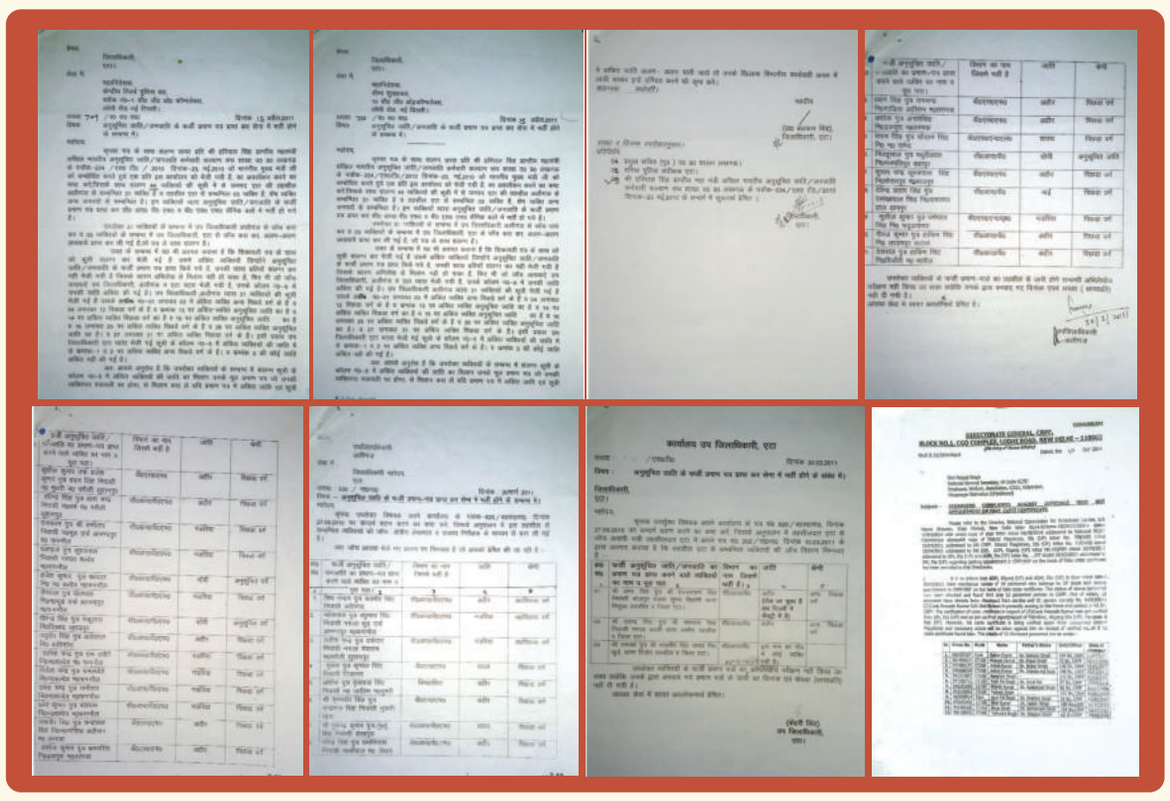

चौकीदार को अफसर बना दिया!

फर्जी तरीके से नौकरी पाने और ऐसे लोगों को विभाग की तरफ़ से संरक्षण देने का यह बेजोड़ मामला है. सिंचाई विभाग के लखनऊ खंड शारदा नहर में तैनात राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय को 18 साल के बजाय 16 साल में ही नौकरी मिल गई थी. किसी भी अधिकारी ने कभी यह नहीं पूछा कि उन्हें 16 वर्ष, छह महीने, 25 दिन की उम्र में ही नौकरी किस क़ानून के तहत मिल गई? क़ानूनी प्रावधान के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती. बहरहाल, फर्जी तरीके से नियुक्ति भी हो गई और तमाम तरक्कियां भी होती रहीं. आख़िरकार मामला जब शीर्ष स्तर पर पहुंचा, तो राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय को सीधे डिमोट करके चौकीदार बना दिया गया. चौकीदार बनाए जाने के ख़िलाफ़ राजेंद्र हाईकोर्ट चले गए. हाईकोर्ट ने भी राजेंद्र की याचिका खारिज कर दी. यानी चौकीदार के पद पर पदावनति को अदालत ने भी सही ठहरा दिया. लेकिन, इसके बाद सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों की धृष्टता और दुस्साहस देखिए कि विभागीय आदेश और अदालत के फ़ैसले को ताक पर रखते हुए उन्होंने राजेंद्र उपाध्याय को सीधे प्रशासनिक अधिकारी (एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर) के पद पर स्थापित कर दिया. प्रशासनिक अधिकारी का सृजित पद न होते हुए भी दूसरी जगह का पद अटैच कर राजेंद्र को यहां आसीन किया गया. ऐसे ग़ैर-अनुशासनिक और ग़ैर-क़ानूनी कृत्य पर शासन की निगाह नहीं जाती. राजेंद्र उपाध्याय पर वित्तीय अनियमितताओं के भी कई मामले हैं. हाउसिंग समिति के नाम पर वित्तीय गड़बड़ी करने के अलावा उस पर अपने बेटे को विभाग का ठेकेदार बनाकर फ़ायदा पहुंचाने, पराग बूथ के आवंटन में हेराफेरी करने, सरकारी कॉलोनी में ग़ैर-क़ानूनी निर्माण कराने जैसे तमाम आरोप हैं, लेकिन सिंचाई विभाग पर यूपी की अंधेर नगरी का पूरा असर है. उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग में 16 साल की उम्र में नौकरी पाने के और भी कई मामले हैं. विभाग के ड्राफ्टमैन विष्णु स्वरूप त्रिवेदी को भी 16 साल, सात महीने, चार दिन की उम्र में नौकरी मिल गई थी. त्रिवेदी की नियुक्ति को लेकर जांच और प्रति-जांच का सिलसिला चलता रहा, वह रिटायर होकर चले गए और अब पेंशन भी खा रहे हैं. जांच आज तक चल रही है. नौकरी पाने के पहले ही उनके लिए छुट्टियां मंजूर कर दिए जाने का मामला भी ऐसे रोचक किस्सों में शामिल है. ■

पिछड़ी जाति के दलित इंजीनियर!

उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में भी फर्जी जाति प्रमाण–पत्र पर नियुक्ति पाने का गोरखधंधा लंबे अर्से से चल रहा है. सिंचाई विभाग खास तौर पर ऐसी नियुक्तियों का केंद्र बना हुआ है. इस विभाग में सामान्य कर्मचारियों से लेकर इंजीनियर तक फर्जी जाति प्रमाण–पत्र पर नौकरी पाए हुए हैं. सिंचाई विभाग में सोनभद्र स्थित रॉबर्ट्सगंज में तैनात सहायक अभियंता अरविंद कुमार मूल रूप से पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र पर नौकरी कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि इस सहायक अभियंता के कई रिश्तेदार भी अनुसूचित जाति का बनकर सिंचाई विभाग में नौकरी कर रहे हैं. अरविंद कुमार मूल रूप से मल्लाह (पिछड़ी जाति) हैं, लेकिन जाति प्रमाण–पत्र मझवार (अनुसूचित जाति) का बनवा रखा है. अरविंद कुमार की नियुक्ति अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र पर हुई और दलित होने के आधार पर ही उनकी तरक्की भी हो गई, जबकि फर्जी जाति प्रमाण–पत्र की जानकारी विभाग के सारे आला अधिकारियों को हो गई थी. विडंबना यह है कि अरविंद कुमार का फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर किए जाने का आदेश भी जारी हो गया था, लेकिन उस आदेश को दबा दिया गया. फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मामले में उन पर क़ानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी तरह सिंचाई विभाग, देवरिया में तैनात कन्हैया प्रसाद पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन अनुसूचित जाति का बनकर नौकरी कर रहे हैं. कन्हैया प्रसाद के तीन नाम हैं, कन्हैया, कन्हैया प्रसाद और कन्हैया प्रसाद गोंड. जहां जैसी सुविधा देखी, वैसा नाम इस्तेमाल कर लिया. कन्हैया प्रसाद मूल रूप से पिछड़े वर्ग की कहार जाति से आते हैं, लेकिन जाति प्रमाण–पत्र में वह अनुसूचित जाति के गोंड बने हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं. खूबी यह है कि कन्हैया प्रसाद के सर्विस रिकॉर्ड में भी जाति के कॉलम में कहार लिखकर उसे काटा हुआ है और गोंड लिख दिया गया है. सर्विस रिकॉर्ड में नाम कन्हैया प्रसाद लिखा है, जबकि जाति प्रमाण–पत्र पर कन्हैया प्रसाद गोंड लिखा हुआ है. जाति प्रमाण–पत्र पर पता (एड्रेस) सिंचाई विभाग, गोमती बैराज, लखनऊ लिखा हुआ है. यह प्रमाण–पत्र प्रथम द्रष्टया ही फर्जी साबित होता है, क्योंकि जाति प्रमाण–पत्र पर उस विभाग का पता नहीं दर्ज होता, जहां धारक नौकरी कर रहा है. लेकिन, इस भीषण भूल (ब्लंडर) पर अधिकारियों की निगाह नहीं जाती. इसी तरह सिंचाई विभाग, सीतापुर के नलकूप खंड–2 में फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र के आधार पर नौकरी पाए राम आसरे का मामला भी सरकारी पेंच में फंसा हुआ है. इस व्यक्ति पर सिंचाई विभाग के प्लैट पर अवैध रूप से कब्जा करने का भी आरोप है. राम आसरे सरकारी काम करने के बजाय राजनीतिक दल की पार्टी गतिविधियों में सक्रिय रहता है, लेकिन विभाग कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 18
दिल्ली, 06 जुलाई –12 जुलाई 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सिन्हा बन पाएंगे सेठ

दिलीप चेरियन

पी. के.सिन्हा ने अजित सेठ से कैबिनेट सचिव का पदभार संभाल लिया है. देश की शीर्ष बाबू के रूप में सेठ के कार्यकाल की जैसी प्रशंसा हुई कुछ वैसे ही कार्यकास की इच्छा सिन्हा भी कर सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेठ के चार साल के विस्तारित कार्यकाल के अंत में उनकी जबरदत्स प्रशंसा की है. मोदी ने तीन ट्वीट करके सेठ की तारीफ की है और उन्हें भविष्य के जीवन के लिए शुभकामनायें दी हैं. जब मोदी पिछले साल मई में सत्ता में आए थे तो कोई भी यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि कि सेठ अपने पद पर बने रहेंगे. उन्हें दो बार छह–छह महीने का सेवा विस्तार मिला. इससे पता चला कि मोदी न सिर्फ उनके साथ काम करने के इच्छुक थे, बल्कि उन्हें अपने आसपास भी रखना चाहते थे. सेठ के उत्तराधिकारी के रूप में सिन्हा निश्चित रूप से चाह रहे होंगे कि सेठ का कुछ जादू उनके भी काम आ जाये. ■

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुखिया कौन

पिछले कुछ सप्ताह में मोदी सरकार ने केवी चौधरी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और विजय शर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के महानिदेशक का रिक्त पद भी अब एस क्रिस्टोफर की नियुक्ति के साथ भर गया है. लेकिन, आश्चर्य की बात है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), अध्यक्ष आरपी सिंह के पिछले महीने जाने के बाद से पूर्णकालिक मुखिया की तलाश कर रहा है. यह पद अभी भी रिक्त है. सिंह के उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया जनवरी में शुरू हुई और फरवरी में इसके लिए आवेदन प्राप्त हुए थे. अध्यक्ष पद की दौड़ में सूचना एवं प्रसारण सचिव बिमल जुल्का, संस्कृति सचिव रविंदर सिंह और कई पूर्व सचिव शामिल हैं. सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं बनाई है. सड़क परिवहन सचिव विजय छिब्बर को एनएचएआई के अध्यक्ष का अस्थायी प्रभार दिया है. ■

नो एक्शन!

पांच वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ राज्य लोकायुक्त और राज्य आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की सख्त कार्रवाई की सिफारिश को कर्नाटक सरकार ने ठुकरा दिया है. राज्य मंत्रिमंडल ने बाबुओं के खिलाफ पुख्ता सबूतों की कमी का हवाला देते हुए अनुरोध को ठुकरा दिया है. बाबुओं में राज्य प्रशासनिक सेवा (केएएस) अधिकारी शशिधर बागली, एसएस सोमनल और सिदप्पा हुलोली, आईएफएस शेखर और आईएएस अधिकारी और कर्नाटक लोक सेवा आयोग के पूर्व सचिव के आर सुंदर शामिल हैं. कर्नाटक एडमिनिसट्रेटिव सर्विस(केएएस) के तीन बाबुओं पर उनके संबंधित क्षेत्रों में अवैध रेत खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगा था, जबकि सुंदर पर अधिकारियों की भर्ती में अनियमितता बरतने के आरोप लगे थे. ■

dilipcherian@gmail.com

राजपथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए योग दिवस के आयोजन में एक साथ दो गिनीज रिकॉर्ड्स की स्थापना हुई. 35,985 लोगों के साथ सबसे बड़ी योग क्लास और चौरासी देशों के लोगों द्वारा इस आयोजन में एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड भी इस कार्यक्रम के दौरान बना. 35 मिनट तक चले कार्यक्रम में 21 योग मुद्राओं का लोगों ने अभ्यास किया. अर्नेस्ट एंड यंग ने पूरे कार्यक्रम का ऑडिट किया. कार्यक्रम के बाद गिनीज बुक रिकॉर्ड आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने ग्रहण किया.

वीपी सिंह का जन्मदिवस किसान दिवस घोषित हो

चौथी दुनिया ब्यूरो

आ जीवन गरीबों, वंचितों और किसानों के हक के लिए लड़ने वाले वीपी सिंह अपनी अंतिम सांसों तक आम लोगों की आवाज उठाते रहे. वीपी सिंह को लोग आज भी गरीबों का मसीहा मानते हैं. इस साल 25 जून, 2015 को लखनऊ में किसान मंच ने अपने संस्थापक स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप मे मनाई. इस मौके पर किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने घोषणा की कि किसान मंच हर वर्ष 21 जून को योग दिवस को किसान सम्मान दिवस के रूप मे मनाता रहेगा. उनका मानना था कि मंच को योग से कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक तरफ जहां फसलों का भारी नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ केन्द्र सरकार योग पर वाहवाही लूटने के लिये अरबों रुपये केन्द्र के खजाने से योग दिवस मनाने में खर्च कर रही है. किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि राजा साहब ने पिछड़ों के लिये जो कार्य किया, वह किसी नेता ने नहीं किया. उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके पिछड़ों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया. कार्यक्रम में प्रमुख लोगों में राजद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह, निरंजन मिश्र (पूर्व विधायक, लखीमपुर), वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय, ए जेड जेड खान, स्वामी विद्या चैतन्य जी, संजीव श्रीवास्तव, संजय द्विवेदी-प्रवक्ता किसान मंच, वसीम खान, मध्य प्रदेश के किसान नेता उमेश तिवारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे.

विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म डैया रियासत में 25 जून, 1931 को हुआ था. उनका लालन-पालन यहीं हुआ, लेकिन अपने मूल पिता के परिवार में बालक विश्वनाथ का रहना पांच वर्ष तक ही हुआ. डैया के बगल की रियासत मांडा के राजा थे राजा बहादुर राम गोपाल सिंह. वह नि:संतान थे. अपनी राज परंपरा चलाने के लिए उन्होंने बालक विश्वनाथ को माता-पिता की सहमति से गोद ले लिया. फिर तो

विश्वनाथ ने पीछे नहीं देखा और गंभीरता से पठन-पाठन में जुट गए. परिणामस्वरूप उन्हें हाईस्कूल तक कई विषयों में उत्कृष्ठता मिली. बाद में वह बनारस के उदय प्रताप सिंह कॉलेज में पढ़ने आए. वहां विश्वनाथ अच्छे छात्रों की पंक्ति में थे. प्रिंसिपल ने उन्हें प्रिफेक्ट बनाया. तब तक भारत को आज़ादी मिल चुकी थी. विश्वनाथ ने छात्रसंघ गठित करने की मांग रखी. अध्यक्ष पद के लिए प्रिंसिपल का एक लाड़ला छात्र खड़ा हुआ. उसे गुमान था कि वह प्रिंसिपल का उम्मीदवार है. प्रतिरोध व्यवस्था में पक्षपात के ख़िलाफ़ विश्वनाथ के कान खड़े हुए. आजीवन इस्तीफों से मूल्यों को खड़ा करने और गलत का प्रतिरोध करने वाले भावी वी पी सिंह का यही उदय था. बस क्या था, प्रिफेक्ट पद से इस्तीफा दे दिया. यह उनकी ज़िंदगी का पहला इस्तीफा था. समान विचारों के छात्रों ने संघ के अध्यक्ष पद के लिए उन्हें खड़ा कर दिया. युवा कांग्रेस का आग्रह टालकर वह स्वतंत्र उम्मीदवार बने और प्रिंसिपल के उम्मीदवार को हराकर जीत गए. वोट को आकृष्ट करने की क्षमता का यही बुनियादी अनुभव बना वी पी सिंह का. राजनीति इसी अंतराल में उनका विषय बनी. 1955 में 24 साल की उम्र में वे कांग्रेस के चवन्निया सदस्य बने. तत्कालीन परिस्थितियों में उन्हें 1971 का लोकसभा चुनाव फूलपुर क्षेत्र से लड़ना पड़ा. इसमें उन्होंने जनेश्वर मिश्र जैसे तपे-तपाए समाजवादी नेता को पछाड़ा था. 10 अक्टूबर, 1976 को इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में व्यापार के उपमंत्री बना दिए गए. इंदिरा गांधी की असामयिक मौत के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने. उन्होंने भी वीपी को वित्त मंत्री बनाया. वीपी ने महसूस किया कि इस व्यवस्था में केवल धनपतियों की चलती है. उन्होंने पूंजीवादी, काले धनपतियों और कर चोरों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंक दिया. वह वित्त से रक्षा मंत्री बना दिए गए. बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने बोफोर्स सौदे में दलाली के मुद्दे को उठाया और सत्ता के चरित्र का पर्दाफाश कर दिया. 19 जुलाई, 1987 को वीपी कांग्रेस से निकाल दिए गए. वीपी ने जनमोर्चा का गठन किया. सात प्रमुख विपक्षी दलों को मिलाकर एक राष्ट्रीय मोर्चा तैयार हुआ. 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा पूर्ण बहुमत में आया. और उन्होंने भारते के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. उन्होंने सात अगस्त, 1990 को मंडल कमीशन की सिफ़ारिशों को लागू करने की घोषणा की थी. वीपी का यह निर्णय भारतीय इतिहास में वंचितों के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ.

हालांकि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद भी वी पी सिंह के क़दम नहीं रुके. वह पूरे देश में घूम-घूमकर आम जनता के हितों के लिए संघर्ष करते रहे. इस दौरान जनता दल कई बार टूटा और टूटता ही रहा. धीरे-धीरे दलगत राजनीति से वी पी सिंह का मोहभंग होता गया और जुलाई 1993 में उन्होंने जनता दल संसदीय दल के नेता पद से त्यागपत्र दे दिया. इसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ दी. दलगत राजनीति से बाहर आए तो जन चेतना मंच के ज़रिए जनसंघर्ष की शुरुआत की. दिल्ली की 30 हज़ार आबादी वाली वजीरपुर झुग्गी बस्ती को उजाड़ने के लिए सरकार ने बुलडोज़र चलाने की कोशिश की तो वह यह कहते हुए बुलडोज़र के सामने खड़े हो गए कि अगर सरकार सभी अनधिकृत फॉर्म हाउसों को भी ढहा दे तो हम इस झुग्गी बस्ती को उजाड़ने से नहीं रोकेंगे. बाध्य होकर सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा. इस प्रकार झुग्गी-झोपड़ी वालों की समस्या को वी पी सिंह ने एक राष्ट्रीय परिघटना बना दिया. दादरी के किसानों की भूमि के अधिग्रहण के विरोध में बीमार वी पी सिंह ने जो लड़ाई लड़ी, वह आज के आंदोलनकारियों के लिए किसी सीख से कम नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राजनीतिक रस्साकशी के बीच मना

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

चौथी दुनिया ब्यूरो

किसी साधारण आयोजन को एक ग्रैंड आयोजन में कैसे तब्दील किया जाता है यह हुनर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बेहतर और कोई नहीं जानता. पिछले साल अमेरिका यात्रा के दौरान 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था. नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर 27 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्य देशों ने सहमति जताई और 21 जून(उत्तरी गोलार्ध के सबसे लंबे दिन) को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रुप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया. प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जून को अंतरराष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है. 21 योग दिवस घोषित किए जाने के बाद श्री श्री रविशंकर ने कहा था कि किसी भी दर्शन, धर्म या संस्कृति के लिए राज्य के संरक्षण के बिना जीवित रहना बहुत मुश्किल है. योग लगभग एक अनाथ की तरह अब तक अस्तित्व में था. अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिली आधिकारिक मान्यता योग के लाभ को विश्वभर में फैलाएगी.

नरेंद्र मोदी भारत के गौरव को विश्व स्तर बढ़ाने के लिए हाथ आए इस मौके को खाली कैसे जाने देते. देश में 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गईं. हर जगह विज्ञापनों और होर्डिंग्स में योग के फायदे दिखाई देने लेग. लेकिन इसके साथ ही योग को लेकर धार्मिक आस्था के सवाल भी उठने लगे. भाजपा और उसके सहयोगी दल इसे नरेंद्र मोदी की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने लगे. धार्मिक और राजनीतिक कारणों से अपने ही देश में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन विवादों में घिरता जा रहा था. मुस्लिम और इसाई संगठन योग को अनिवार्य बनाने को योग अपने मौलिक अधिकारों का हनन मान रहे थे. विपक्षी दल किसी भी कीमत पर योग के नाम पर नरेंद्र मोदी को राजनीतिक खेल में अंक बटोरने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे.

राजपथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए योग दिवस के आयोजन में एक साथ दो गिनीज रिकॉर्ड्स की स्थापना हुई. 35,985 लोगों के साथ सबसे बड़ी योग क्लास और चौरासी देशों के लोगों द्वारा इस आयोजन में एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड भी इस कार्यक्रम के दौरान बना. 35 मिनट तक चले कार्यक्रम में 21 योग मुद्राओं का लोगों ने अभ्यास किया. अर्नेस्ट एंड यंग ने पूरे कार्यक्रम का ऑडिट किया. कार्यक्रम के बाद गिनीज बुक रिकॉर्ड आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने ग्रहण किया. इसके बाद उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि भारत ने एक ही दिन योग के दो रिकॉर्ड कायम किए. इससे पहले सबसे बड़ी योग क्लास का गिनीज बुक रिकॉर्ड ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय स्थित विवेकानंद केंद्र के नाम था. 19 नवंबर,2005 को 362 स्कूलों के 29,973 बच्चों ने 18 मिनट तक एक साथ यौगिक क्रियाएं और सूर्य नमस्कार करने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में हुए आधिकारिक कार्यक्रमों में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाग लिया. योग दिवस पर भारतीय मिशनों और योग केंद्रों द्वारा 192 देशों में भी योग संबंधी कार्यक्रम आयोजित हुए. पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की.

लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के योग कार्यक्रम को दिखावा करार दिया. लालू प्रसाद यादव ने योग दिवस को अंतरराष्ट्रीय तोंद डे कहा. लालू यादव ने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि योग जैसे व्यक्तिगत मसले को प्रचार-प्रसार की मदद से मोदी सरकार अपना पीआर बनाने में जुटी है. ये शरीर को स्वस्थ बनाने का नहीं राजनीति का योग है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हमारे देश में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं. रिक्शा चलाने वाले को योग की क्या जरूरत? मजदूर को योग की क्या जरुरत जो दिन भर शारीरिक श्रम करता है. जो सुख प्राप्ति का जीवन जी रहा है, पूंजीपतियों को गरीबों का खून चुसवा रहा है, किसानों की ज़मीन निगल रहा है वह योग करेगा और करवाएगा. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि योग करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए योग का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए.

वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सवाल किया कि, क्या पीएम मोदी स्वयं योग करते हैं? पुतिन ने कहा कि आखिर हर कोई यह क्यों करेगा? उन्होंने हैरानी जताई कि क्या जो व्यक्ति दुनियाभर में योग का प्रसार करना चाहता है, वह स्वयं योग करता है? वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबोट ने योग के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कहा कि हजारों सालों से योग ने अनुयायियों को मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद की है. पाकिस्तान में श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा योग कार्यक्रम आयोजित करने जा रही थी लेकिन कट्टरपंथियों और आतंकवादियों की धमकी के बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया. ब्रिटेन में योग दिवस मनाने के लिए सैकड़ों लोग विभिन्न शहरों में एकत्रित हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने संदेश में कहा कि ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करके प्रसन्नता महसूस कर रहा है. हम उन 177 देशों में से एक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था. जिस उत्साह से इसे ब्रिटेन और पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है उसे देखकर हम बहुत खुश हैं. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने न्यूयार्क में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ अपनी मुलाकात के दौरान प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अपना उत्साह व्यक्त किया और कहा कि इस दिन पूरे विश्व में अभूतपूर्व जोश देखने को मिला है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ में योग दिवस के विरोध पर किसान मंच पर लाठीचार्ज

उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान मंच ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विरोध किया. लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह योग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे. जहां किसानों ने योग दिवस के विरोध में नारेबाजी की. पुलिस अधिकारियों ने किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष शेखर दीक्षित सहित अन्य पदाधिकारियों को स्टेडियम में नहीं जाने दिया गया. किसान मंच के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे. तभी पुलिस ने अचानक से उन पर लाठी चार्ज कर दिया. लाठीचार्ज में 5 लोग घायल हो गए जिन्हें बाद में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. किसान मंच का कहना है कि क्या योग दिवस के नाम पर सारे चैनलों पर मोदी और रामदेव की मार्केटिंग करने से देश की प्रमुख समस्याएं गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निरक्षरता सब ख़त्म हो जाएंगी? जहां किसान भूख से मर रहा है वहां योग के तमाशे की क्या जरूरत है. जब किसान और गरीब के पेट में अन्न ही नहीं है तो वह योग कैसे करेगा. किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष शेखर दीक्षित का कहना है कि मोदी सरकार ने योग को भी धर्म और मजहब में बांट दिया है. योग के प्रचार के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए गए. लेकिन जब बात किसानों को बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की आती है तो सरकार के पास फंड की कमी हो जाती है. ■

ललित मोदी प्रकरण

भाजपा के अंदर मचे शीतयुद्ध का नतीजा है

ललित मोदी प्रकरण से मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हुई है. यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ललित मोदी पर इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) को लेकर कई आरोप हैं. उन पर पैसों की हेराफेरी करने का आरोप है. यह बात भी छिपी नहीं है कि कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियों के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते ललित मोदी के साथ रहे हैं. ललित मोदी के ख़िलाफ जो आरोप लगे वो कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए थे. साल 2010 में जब ललित मोदी पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्डरिंग का आरोप लगा था, तब वह देश से भाग कर लंदन चले गए. यह बात भी सही है कि तब हाईकोर्ट ने ललित मोदी के पक्ष में निर्णय दिया था लेकिन हैरानी इस बात की है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई. एक बार फिर इस मामले को मीडिया में उठाया गया है. इस मसले भूतपूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर विश्वबंधु गुप्ता ने चौथी दुनिया के साथ एक्सक्लूजिव बातचीत में एक हैरतअंगेज खुलासा किया है.

मनीष कुमार

विश्वबंधु गुप्ता का दावा है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने उनकी मुलाक़ात ललित मोदी के पिता के के मोदी से करवाई थी. उस नेता ने के के मोदी को उनसे यह कहकर मिलवाया था कि विश्वबंधु की वित्त मंत्रालय में गहरी पैठ है. इस मुलाकात के दौरान के के मोदी ने कहा कि ललित मोदी को भारत लाना है. उनका सीधा मतलब था कि ललित पर लगे सारे आरोपों को कैसे खत्म किया जाए. विश्वबंधु गुप्ता को यह भली-भांति पता था कि ललित मोदी ने आईपीएल में क्या-क्या किया है. विश्वबंधु पहले भी क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की जांच कर चुके थे. उन्होंने के के मोदी से कहा कि यदि आपको कोई राहत चाहिए तो वह आपको सिर्फ इस देश की अदालतें दे सकती हैं. इस मामले में और कुछ नहीं हो सकता. विश्वबंधु गुप्ता से के के मोदी ने साफ-साफ कहा कि वह कोर्ट जाने में यकीन नहीं रखते हैं. कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि ढाई-तीन सौ करोड़ रुपये देकर मामली निपट जाये. मतलब यह कि के के मोदी ने विश्वबंधु गुप्ता को ललित मोदी मामले को खत्म करने के लिए तीन सौ करोड़ रुपये की पेशकश की थी. विश्वबंधु गुप्ता कहते हैं कि के के मोदी शायद देश के पहले बिजनेसमैन हैं जो तीन सौ करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में देने लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह मामला तीन सौ करोड़ रुपये का है.

कांग्रेस सरकार और आईपीएल से जुड़े लोगों को ललित मोदी के बारे में सबकुछ मालूम था, कि वह क्या कर रहे हैं. लेकिन कांग्रेस सरकार ने ललित मोदी के खिलाफ एक भी निर्णय नहीं लिया. लेकिन यह मामला बीजेपी में नंबर दो का नेता बनने की होड़ में एक हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ. इसका इस्तेमाल एनडीए की एक वरिष्ठ महिला केंद्रीय मंत्री के लिए किया गया था. लेकिन जिस बड़े नेता ने इस खेल को अंजाम दिया उन्हें यह नहीं पता था कि जितना बड़ा पलीता वो लगा रहे हैं उससे पूरी सरकार और भाजपा के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी. दरअसल, ललित मोदी पर जितनी भी रिपोर्टिंग हुई, वह खबर किसी ने सीधे या किसी बिचौलिये के जरिए वित्त मंत्रालय से मीडिया तक पहुंचाई. प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ललित मोदी पर बहुत पहले से नज़र रखे हुए था. बीजेपी के ये जो नेता हैं उनका प्रेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव है. वे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो 150 से 200 पत्रकारों को अपने घर पर बुला लेते हैं. वो अखबार वालों को बड़ी लजीज़ दावतें देते हैं. बड़े-बड़े न्यूज चैनलों और अखबारों के संपादकों से उनकी दोस्ती है. भारतीय जनता पार्टी में मीडिया के साथ उस नेता की नजदीकी भी एक चिंता का विषय है. बीजेपी की आंतरिक कलह की जड़ में नंबर दो नेता बनने की होड़ है. इस होड़ में सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और अब अमित शाह शामिल हो गए हैं. ललित मोदी प्रकरण का निशाना विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं लेकिन अब यह आग बढ़कर राजस्थान तक पहुंच गई है.

हकीकत यह है कि सुषमा स्वराज से इस्तीफा नैतिकता के आधार पर मांगा जा रहा है. सुषमा स्वराज ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे अपराध की श्रेणी में गिना जा सके. लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि मीडिया में यह बात फैलाई जा रही है कि ललित मोदी एक भगोड़ा हैं यह गलत है. न ही ललित मोदी के खिलाफ कोई अपराधिक मामला दर्ज है और न ही वो भगोड़ा हैं. इस प्रकरण के दौरान ऐसी कई बातें हुई हैं जो अनावश्यक थीं. जैसे कि सुषमा स्वराज के परिवार के सदस्यों को मामले में घसीटने या फिर वसुंधरा के बेटे की कंपनी को घसीटने का मतलब साफ है कि बीजेपी की अंदर की लड़ाई ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां लोगों ने मर्यादा को भी ताक पर रख दिया है. सुषमा स्वराज के खिलाफ जब स्टोरी आई तो बीजेपी में एक तरह की खामोशी थी. सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ(आरएसएस) ने सुषमा का समर्थन किया.

कांग्रेस सरकार और आईपीएल से जुड़े लोगों को ललित मोदी के बारे में सबकुछ मालूम था, कि वह क्या कर रहे हैं. लेकिन कांग्रेस सरकार ने ललित मोदी के खिलाफ एक भी निर्णय नहीं लिया. लेकिन यह मामला बीजेपी में नंबर दो का नेता बनने की होड़ में एक हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ. इसका इस्तेमाल एनडीए की एक वरिष्ठ महिला केंद्रीय मंत्री के लिए किया गया था. लेकिन जिस बड़े नेता ने इस खेल को अंजाम दिया उन्हें यह नहीं पता था कि जितना बड़ा पलीता वो लगा रहे हैं उससे पूरी सरकार और भाजपा के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी.

इसके बाद अमित शाह और राजनाथ सिंह सुषमा के बचाव में सामने आए. लेकिन जिन्हें सामने आना था, वे इस पूरे प्रकरण के दौरान पार्टी या सरकार को बचाने टीवी पर नहीं आए और न ही प्रधानमंत्री ने इस मामले में कोई बयान दिया. सुषमा स्वराज के खिलाफ जितने भी आरोप हैं वो पूरी तरह से नैतिक ही हैं. यहां यह समझना भी जरूरी है कि यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है. शायद विदेश मंत्री और विदेश मंत्री के परिवार से जुड़े और किस्से बाहर आएंगे. यह भी समझना जरूरी है कि पहली बार मीडिया और विपक्ष ने किसी मंत्री का इस्तीफा सिर्फ इस बात पर मांगा है क्योंकि उनके परिवार के सदस्य किसी आरोपी के वकील हैं. पलीता लगाने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता को शायद यह लगा था कि नरेंद्र मोदी अपनी और सरकार की छवि को बचाने के लिए एक्शन लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की खामोशी ने सुषमा स्वराज और उनके समर्थकों को एक जुट होने का मौका दे दिया. सुषमा स्वराज के जो समर्थक हैं उनमें राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और आरएसएस शामिल है. उन्होंने बोल दिया कि सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री के पद से नहीं हटाया जा सकता है. ऐसे नाजुक मोड़ पर आडवाणी जी का इंटरव्यू भी सामने आ गया कि दिशाहीन और कमजोर नेतृत्व की वजह से भविष्य में आपातकाल की आशंका को टाला नहीं जा सकता है. मतलब यह कि पार्टी के अंदर शीत युद्ध(कोल्डवार) शुरु हो गया है. ऐसी स्थिति में नरेंन्द्र मोदी के हाथ पूरी तरह बंध गए हैं.

इसके बाद यह मसला राजस्थान पहुंच गया. वसुंधरा राजे की हैसियत भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक क्षत्रप की है. पार्टी का कोई भी नेता राजस्थान के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है. चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, दिल्ली के वरिष्ठ नेता हों या फिर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हों. जब राजस्थान में भाजपा विपक्ष में थी. तब भी वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की पहल हुई थी, लेकिन केंद्रीय नेताओं को घुटने टेकने पड़े. लेकिन, ललित मोदी प्रकरण में वसुंधरा राजे का नाम घसीटने को भी पार्टी के अंदर चल रही कोल्ड वार के चश्मे से देखा जा सकता है. यहां भी मीडिया को सारे कागजात प्रवर्तन निदेशालय(ईडी)की तरफ से सीधे या किसी बिचौलिये के जरिए से मुहैया कराये जाने की बात हो रही है. जिस तरह सुषमा स्वराज के परिवार के सदस्यों को इस मामले में घसीटा गया उसी तरह वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत को भी घसीटा जा रहा है. खुलासा यह हुआ है कि ललित मोदी ने दुष्यंत की कंपनी में पैसा लगाया था. जिस कंपनी के जरिए ललित मोदी ने पैसा भिजवाया वह मॉरीशस की एक फेक कंपनी है. यह खुलासा भी हुआ कि दुष्यंत की कंपनी में वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे की बहु के शेयर भी हैं. अभी और भी किस्से राजस्थान से आएंगे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या यह है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के पद से इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि उन्होंने साफ-साफ यह संदेश दिल्ली पहुंचा दिया है कि यदि उन्हें हटाया गया तो राजस्थान में पार्टी टूट जाएगी. ज्यादातर विधायक वसुंधरा के साथ हैं. ललित मोदी प्रकरण नरेंद्र मोदी के लिए सरकार, पार्टी और खुद की साख बचाने की चुनौती बन गया है.

पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी के चार नेताओं पर आरोप लगे हैं. सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे और पंकजा मुंडे. इन सभी पर आरोप मीडिया ने लगाये हैं. ज्यादातर आरोप नैतिकता के आधार लगे हैं. क़ानून की नज़र में भले ही ये कोई अपराध न हो, लेकिन राजनीति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. राजनीति साख पर चलती है. राजनीति नैतिक आधार पर चलती है न कि कोर्ट के फैसले पर. बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी को कभी कोई सजा नहीं मिली. वीपी सिंह के पास राजीव गांधी के खिलाफ क्या सबूत था? लेकिन 1989 में वी पी सिंह बोफोर्स के आधार पर प्रधानमंत्री बन गए. नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले कहा था कि न गलत काम करूंगा और न ही करने दूंगा. न खाऊंगा न खाने दूंगा. लेकिन पिछले एक महीने से लगातार हो रहे हमले से सरकार की छवि पर असर पड़ा है. नरेंद्र मोदी चुप हैं और पार्टी के अंदर घमासान चल रह है. लाल कृष्ण आडवाणी नाराज हैं. मुरली मनोहर जोशी नाराज हैं. अरुण शौरी नाराज हैं. सुब्रामन्यम स्वामी नाराज हैं. यशवंत सिन्हा नाराज हैं. बाबा रामदेव नाराज हैं. कई मंत्री नाराज हैं. आरएसएस नाराज है. ललित मोदी प्रकरण की वजह से जहां पार्टी में मोदी विरोधी गुट को बल मिल रहा है वहीं आम जनता के बीच सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है. किसी भी सरकार के लिए खराब छवि कैंसर की तरह होती है. समय पर इलाज न हो तो सरकार, पार्टी और नेताओं का इकबाल खत्म हो जाता है. नरेंद्र मोदी जितना चुप रहेंगे क्षति उतनी ज्यादा होगी. ■

manishbph244@gmail.com

श्रद्धांजलि

अलविदा प्रफुल्ल बिदवई!

चौथी दुनिया ब्यूरो

जाने-माने स्तंभकार, पत्रकार, शिक्षाविद और एक्टिविस्ट प्रफुल्ल बिदवई (1949-23 जून, 2015) का दिल का दौरा पड़ने की वजह से वर्ष 66 वर्ष की आयु में हॉलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में निधन हो गया. वे वहां एक कांफ्रेंस में हिस्सा लेने गये थे. उनके देहांत से चार दशकों से सक्रिय भारतीय मीडिया जगत का एक जगमगाता सितारा डूब गया. हालांकि छात्र जीवन के बाद वह कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे लेकिन उनके लेख वामपंथी विचार धारा से प्रेरित थे. इसलिए उनके निधन से देश में कमज़ोर पड़ चुकी वामपंथी राजनीति को भी गहरा झटका लगा है. 1970 के दशक में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, मुंबई की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वह पत्रकारिता के मैदान में आए बिदवई राजनितिक, सामाजिक और पर्यावरण के विषयों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अख़बारों और पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे. वामपंथी राजनीति पर उनकी द्वारा लिखी गयी किताब हाल ही में प्रकाशित होने वाली है. उन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली चुनावों में जीत को वामदलों के लिए आशा की किरण बताया था.

प्रफुल्ल बिदवई एक पत्रकार होने के साथ-साथ एक एक्टिविस्ट भी थे. उन्होंने वर्ष 1998 में भारत केपरमाणु परीक्षण का न केवल विरोध किया बल्कि तत्कालीन वाजपेयी सरकार को इस परीक्षण का पूरा श्रेय भी नहीं लेने दिया. उन्होंने परमाणु युद्ध और रेडिएशन के खतरों को अपने लेखों में बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया.

प्रफुल्ल बिदवई एक पत्रकार होने के साथ-साथ एक एक्टिविस्ट भी थे. उन्होंने वर्ष 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण का न केवल विरोध किया बल्कि तत्कालीन वाजपेयी सरकार को इस परीक्षण का पूरा श्रेय भी नहीं लेने दिया. उन्होंने परमाणु युद्ध और रेडिएशन के खतरों को अपने लेखों में बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया. साल 2014 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक लीक

रिपोर्ट में भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रख्यात विरोधियों की सूची में उनका नाम भी शामिल था. वे दक्षिण एशिया में शांति अभियान के बड़े समर्थक थे. वह परमाणु निःशस्त्रीकरण और शांति गठबंधन (कोएलिशन फॉर न्यूक्लिअर डिसआर्मामेंट एन्ड पीस) के संस्थापक सदस्य थे. विश्व शांति के लिए इस संगठन की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी. जेनेवा स्थित इंटरनेशनल पीस ब्यूरो की तरफ से उन्हें वर्ष 2000 में शीन मैकब्राइड अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इसके साथ ही उन्हें एम्स्टर्डम के ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूट का फेलो चुना गया था.

प्रफुल्ल कहा करते थे कि एक पत्रकार का काम भावी भविष्य को देखना होता है, भावी युद्ध, जलवायु परिवर्तन, सैन्यवाद, बढ़ती दौलत और भोगविलास, भयावह गरीबी, अन्याय, फासीवाद से मुक़ाबला करने के लिए पीस एक्टिविस्टों, नागरिक समूहों, वामदलों, महिला संगठनों, समाजवादियों और पर्यावरण आंदोलनों को एक छत के नीचे आना चाहिए. जिससे उम्मीदों की एक नई राजनीति की शुरूआत हो. आज देश जिन राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रहा है उस वक्त ऐसे दूरदृष्टा पत्रकार और लोकहितवादी व्यक्तित्व की कमी भारत को हमेशा खलेगी. ■

बिहार विधानसभा चुनाव

हरसिद्धि सुरक्षित क्षेत्र में एक अनार सौ बीमार

राकेश कुमार

जगजीवन पासवान

कृष्णनंदन पासवान

मनोज पासवान

एमडी कासिम

राजेंद्र राम

रामजनम पासवान

विजय कुमार राम

पूर्वी चम्पारण जिला के बारह विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए सुरक्षित है. 13 हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र. हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में तुरकौलिया प्रखण्ड का 16 पंचायत एवं हरसिद्धि प्रखण्ड का 19 पंचायत समाहित है. कुशवाहा बहुल इस क्षेत्र से वर्तमान में भाजपा-जदयू गठबंधन से भाजपा के कृष्णनन्दन पासवान विधायक हैं. इसके पूर्व 2005 में श्री पासवान पीपरा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. 2010 में पीपरा को सामान्य क्षेत्र एवं हरसिद्धि को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया और श्री पासवान विधायक चुने गये.

हरसिद्धि सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियों के नेता तैयारी में जुटे हैं. भावी उम्मीदवार टिकट की जुगत में राजधानी पटना और दिल्ली की दौड़ लगाने लगे हैं. सभी पार्टी के भावी उम्मीदवार इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इस सीट को जदयू के लिए ज्यादा महफूज मान रहे हैं. हरसिद्धि के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा. 1980 से 1990 तक तीन बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा. बैरिस्टर मो. हिदायतुल्लाह खां विधायक बनते रहे. 1995 के चुनाव में बदलाव आया. जनता दल के टिकट पर अवधेश कुशवाहा चुनाव जीते थे. 2000 का चुनाव समता पार्टी के महेश्वर सिंह ने जीता. 2005 के फरवरी में अवधेष कुशवाहा ने लोजपा से जीत दर्ज की. 2005 अक्टूबर में लोजपा के टिकट पर फिर एक बार महेश्वर सिंह चुनाव जीते. 2010 में जदयू और भाजपा गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी कृष्ण नन्दन पासवान ने जीत दर्ज की. पार्टी संगठन के दृष्टिकोण से हरसिद्धि विस में जदयू एवं भाजपा मजबूत दिखाई देती है. राजद का संगठन तो है, लेकिन निष्क्रिय. हालांकि 2010 के चुनाव में राजद के सुरेन्द्र कुमार चन्द्र उर्फ सतीश पासवान दूसरे स्थान पर थे. वर्तमान में कांग्रेस यहां हासिये पर है. हरसिद्धि सुरक्षित क्षेत्र में जदयू, कांग्रेस एवं राजद के गठबंधन के बाद जातीय समीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जदयू गठबंधन मजबूत नजर आता है. भाजपा के साथ मांझी का हम पार्टी और रामविलास पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी है, लेकिन सुरक्षित क्षेत्र होने के कारण सभी प्रत्याशी एक ही वर्ग के होंगे. ऐसे में दर्ज़ी-महादलित की दुहाई देने वाले इन नेताओं की कितनी चलेगी, कहना जल्दबाजी होगी.

हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र का कोई सरकारी जातीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. एक आंकलन के अनुसार जातीय आंकड़ा निम्न है.

कुल वोटरों की संख्या-2,20,000
मुसलमान-35,000 लगभग
कोइरी -27,000 लगभग
कानू, बनिया, तेली -24,000 लगभग
अनु. जाति -26,000 लगभग
यादव -17,000 लगभग
मल्लाह - 16,000 लगभग
राजपूत -10,000 लगभग
धोबी - 4,000 लगभग
नुनिया -5,000 लगभग
तत्वा -4,000 लगभग
भूमिहार -12,000 लगभग
ब्राह्मण -12,000 लगभग
कायस्थ - 5,000 लगभग
लोहार, हजाम- 5,000 लगभग
अन्य -13,000 लगभग

चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सजग हैं. वर्तमान विधायक कृष्ण नन्दन पासवान सिटिंग-गेटिंग के आधार पर पार्टी टिकट के लेकर आश्वस्त हैं. वहीं वे क्षेत्र में किए गये कार्यों के बल पर जनता से सहयोग और समर्थन की उम्मीद रखते हैं. भाजपा की सभाएं भी शुरू हो गई है. सोमवार को क्षेत्र के गायघाट में आयोजित सभा को भाजपा के राष्ट्रीय नेता शाहनवाज हुसैन ने संबोधित किया. जहां उन्होंने नीतीश और लालू पर निशाना साधते हुए भाजपा को मुसलमानों का हितैषी होने का संदेश दिया गया. दूसरी ओर भाजपा के विरोधी दल वर्तमान विधायक पर क्षेत्र का विकास नहीं करने का आरोप लगाते हैं.

हरसिद्धि विस क्षेत्र से भावी उम्मीदवरों की लम्बी फेहरिस्त है. जदयू से मनोज पासवान, रामजनम पासवान, अवधेश राम, राम जुलुम पासवान दावेदार हैं. राजद के टिकट के दावेदार सुरेन्द्र कुमार चन्द्र उर्फ सतीश पासवान हैं. श्री पासवान की पहुंच राजद के बड़े नेताओं तक है. 2000 में श्री पासवान पीपरा से विधायक चुने गये थे. 2010 में हरसिद्धि सुरक्षित सीट हो गया और जहां वे दूसरे स्थान पर रहे. राजद के एक प्रबल दावेदार हैं राजेन्द्र कुमार राम. इनकी पत्नी सुशीला देवी जिला पार्षद हैं. श्री राम क्रांतिकारी नेता रहे हैं. ऊंची जाति में गहरी पैठ और रविदास वोटरों के बल पर श्री राम को चुनावी जंग जीतने का विश्वास है. जमीनी नेता के रूप में वे क्षेत्र से जुड़े रहे हैं.

कांग्रेस से पूर्व में चुनाव लड़ चुके विजय राम चुनाव मैदान में उतरने के लिए ताल ठोंक रहे हैं. विजय राम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं. सहज एवं शांत स्वभाव के श्री राम कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित लोकसभा के युवा अध्यक्ष थे. वर्तमान में प्रदेश सचिव हैं. गठबंधन में यह सीट कांग्रेस को मिलने का आसार नहीं दिखता. ऐसे में श्री राम किसी दूसरे दल का दामन थाम सकते हैं. बकौल श्री राम का अपनी जाति के साथ सभी वर्गों में पैठ है. खासकर बुद्धिजीवी वर्ग पर इनकी विशेष पकड़ है. कांग्रेस के एक दावेदार पूर्व सैनिक रामजीवन पासवान भी हैं. श्री पासवान की पत्नी तुरकौलिया के सपही पंचायत की मुखिया रही हैं और जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं. श्री पासवान प्रखर वक्ता एवं ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं. वे कांग्रेस के अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. पार्टी टिकट नहीं मिलने की स्थिति में वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे. जदयू के टिकट के दावेदारों की संख्या अधिक है. तुरकौलिया के प्रखंड प्रमुख अवधेश राम भी दावेदार हैं. वहीं राम जुलुम पासवान जदयू के टिकट के लिए प्रयासरत बताये जाते हैं. हरसिद्धि के विधानसभा प्रभारी जदयू नेता मनोज पासवान टिकट के प्रबल दावेदार हैं. बकौल श्री पासवान हरसिद्धि सीट गठबंधन के तहत जदयू को हीं मिलेगा, क्योंकि यह कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और कुशवाहा वोट जदयू का परंपरागत वोट है. बिहार सरकार के मंत्री अवधेश कुशवाहा हरसिद्धि के ही हैं और मनोज को इनका वरदहस्त प्राप्त है. 2013 में जदयू में शामिल हुए श्री पासवान लगातार क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और जनता के सुख-दुख में बराबर के भागीदार रहे हैं. क्षेत्र में निरंतर पार्टी गतिविधियों के कारण आम लोगों में पहचान बनाने वाले मनोज की मुस्लिम वर्ग पर भी अच्छी पकड़ है. हरसिद्धि के प्रखंड प्रमुख मोहम्मद कासिम के अनुसार मनोज पासवान को मुसलमानों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि 2010 के चुनाव के बाद से मनोज पासवान को छोड़कर कोई भी नेता क्षेत्र से जुड़ा नहीं रहा. इधर, जदयू के जिला उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के जिलाध्यक्ष राम जनम पासवान भी टिकट के दावेदार हैं. टिकट नहीं मिलने की स्थिति में श्री पासवान एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह कार्य करते रहेंगे. भ्रष्टाचार के विरोध में वे अक्सर आवाज उठाते रहे हैं.

भाजपा गठबंधन के घटक दल लोजपा से तुरकौलिया के धर्मनाथ पासवान दावेदार हैं. इन्हें विश्वास है कि हरसिद्धि सीट लोजपा के पाले में आनी चाक्शि, क्योंकि यहां से दो बार लोजपा चुनाव जीत चुकी है. धर्मनाथ पासवान जमीनी नेता हैं और क्षेत्र से जुड़े रहे हैं. इधर, कभी क्षेत्र में अच्छा जनाधार रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विद्यासागर राम आर्य चुनावी समर में उतरना चाहते हैं. श्री आर्य सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और सेवानिवृत्ति के बाद से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं. एक ईमानदार और जुझारू छवि के कारण समाज में श्री आर्य की अच्छी पहचान है.

बहरहाल, सभी दावेदार पार्टी के फैसले के इन्तजार में हैं. सूचना है कि कई भावी प्रत्याशी अन्य दलों से भी सम्पर्क में हैं, ताकि अंतिम समय में दूसरे प्लेटफॉर्म पर जगह मिल सके. भाजपा गठबंधन और जदयू गठबंधन एक-दूसरे को मात देने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है. आज भी क्षेत्र में सड़क, बिजली की समस्या बरकरार है. लगभग 50 प्रतिशत गांव में बिजली नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम-अवाम को नहीं मिल रहा है. ऐसे में रोजमर्रा की समस्याओं से परेशान जनता नेताओं के वादों और दावों का आंकलन कर रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

समस्तीपुर : कौन बनेगा चुनावी अखाड़े का जिला केसरी

हरि नारायण चौधरी

सुनीता सिंह

राजीव रंजन कुमार

अमृता कुमारी

विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव की तिथि अब करीब है. जिले में पंचायतों तक प्रत्याशियों का काफिला पहुंच रहा है. हर कोई सामाजिक विकास के लिए अपने-अपने पक्ष में मतदान की अपील पंचायत प्रतिनिधियों से कर रहे है, लेकिन इस बार मतदाताओं की मंशा क्या है? आम लोगों को समझ नहीं आ रहा है. मतदाता चुपचाप प्रत्याशियों के राजनीतिक पैंतरा को पढ़ने में मशगूल है. कोई विकास के पैमाने पर प्रत्याशी का आंकलन कर रहा है तो कोई उसकी आर्थिक क्षमता का अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहा है. चुनाव के दिन कौन अपना मत किसकी झोली में डालेगा, इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है. प्रत्याशियों को लेकर चुनावी चौपालों पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है. भाजपा समर्थित हरिनारायण चौधरी, राजद गठबंधन की रोमा भारती के अलावा भाजपा के बागी राजीव रंजन कुमार व सुनीता सिंह की दावेदारी ने फिलहाल मतदाताओं को खामोशी की चादर ओढ़ा दी है.

चुनावी चर्चाओं में भाजपा समर्थित प्रत्याशी हरिनारायण चौधरी को मतदाता कांग्रेस से आयात किये गये प्रत्याशी करार दे रहे हैं. वह कहते हैं कि पूर्व में कांग्रेस की ओर से उन्होंने प्रतिनिधित्व का कमान थामा था, लेकिन जिले में विकास कोई खास नजर नहीं आ सका. ऐसे में उनकी पुन: दावेदारी राजनीतिक दल की मजबूरी हो सकती है, पंचायत प्रतिनिधियों की नहीं, जबकि प्रत्याशी समर्थक का मानना है कि देश में चल रही नमो आंधी की रफ्तार अभी थमी नहीं है. भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत तय है. राजद गठबंधन से निवर्तमान विधान पार्षद रोमा भारती चुनाव मैदान में खड़ी हैं. इनको लेकर चर्चा चल रही है कि वह महिला होने के बाद भी सक्रिय रही हैं. जहां तक विकास का सवाल है तो अपनी क्षमता के बल पर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है. उनके समर्थकों का दावा है कि बिहार में नये राजनीतिक समीकरण का फायदा होना तय है.

अब इन दो निर्दलीय प्रत्याशी का जिक्र भी करना मुनासिब है, जो भाजपा के प्रति समर्पित होकर भी चुनावी समर में आने से खुद को नहीं रोक पाये हैं. इनमें एक तो राजीव रंजन कुमार हैं, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के फरमान को सर आंखों पर लेते हुए जिले के तीन अलग-अलग गावों को गोद लेकर विकास कराने का संकल्प लिया है. साथ ही संकल्प को साकार करने की दिशा में सार्थक पहल भी की है. सफाई अभियान को प्राथमिकता के आधार पर अपनाने वाले राजीव की सेवा भाव का आलम यह है कि राजधानी पटना से जिला को जोड़ने वाली पथ में वरुणा पुल के समीप एक डायवर्जन का निर्माण भी अपने कोष से कराने का काम किया है. बताया जाता है कि सामाजिक सरोकार की कई योजनाएं अब भी राजीव के जेहन में दस्तक दे रही हैं. जिस पर चुनाव बाद विचार कर बात को आगे बढ़ायी जायेगी. चुनाव में उनकी दावेदारी का कारण पार्टी का वादाखिलाफी बताया जाता है. राजीव का दावा है कि इस बार मतदाता को नये चेहरे की दरकार है. वहीं जिला भाजपा उपाध्यक्ष सुनीता सिंह भी चुनाव मैदान में आ डटी हैं. उनका दावा है कि जिले के पंचायत प्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. जिले में विकास का नया उदय होने से कोई रोक नहीं सकता है. अब इन दावों के बीच चुनावी समर में कौन बाजी मारेगा, इस पर लोगों की नजरें टिकी हैं. चर्चा है कि विधान परिषद चुनाव में पैसे का खेल ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करता रहा है. जिसकी तिजोरी में ताकत होती है, जीत का माला उसके गले में झूम जाता है. इस बार चुनावी अखाड़े के जिला केसरी का ताज किसके सर चढ़ेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी : दलगत और निर्दलीय में टक्कर के आसार

वाल्मीकि कुमार

अमिताभ गुंजन

दिलीप राय

देवेंद्र साह

विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव अब दहलीज पर दस्तक दे रहा है. लंबे अर्से से राजनीति में प्रवेश का सपना संजोने वाले प्रत्याशियों का अमन-चैन हराम हो गया है. दिन की चिलचिलाती धूप हो अथवा रात की सूनसान सड़कें, इनके चुनावी अभियान की गति लगातार जोर पकड़ती जा रही है. सीतामढ़ी जिले के 17 और शिवहर जिले के 5 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले प्रतिनिधियों के दरवाजे पर दलगत समर्थित से लेकर निर्दलीय प्रत्याशी तक किसी भी वक्त दस्तक देने से बाज नहीं आ रहे हैं. तकरीबन साढ़े 5 हजार मतदाताओं का चौखट चूमने का साहस नहीं करने वाले प्रत्याशी अपने टारगेट के मतदाताओं पर ही खास तौर से निशाना लगाने में लगे हैं. सोच है कि जीत के लिए इतना ही मत काफी है. वहीं दूसरी ओर कुछ प्रत्याशी जाति व पार्टी का झंडा लेकर अपना चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में लगे हैं. प्रत्याशियों के चुनावी कदमताल पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. प्रतिमा पैनी नजर रख रही हैं. चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में निष्पक्ष व भयमुक्त मतदान कराने को लेकर हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. अब चुनावी समर में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों को लेकर चल रही चर्चाओं पर गौर करने की जरूरत है. सीतामढ़ी से स्थानीय निकाय के विधान परिषद चुनाव में भाजपा गठबंधन समर्थित प्रत्याशी के रूप में डुमरा प्रखंड प्रमुख देवेंद्र साह अपनी जीत सुनिश्चित कराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं. जहां तक क्षेत्र में मतदाताओं के बीच पकड़ का सवाल है तो इस मामले में इनको काफी पीछे माना जा रहा है. कारण कि चुनाव को लेकर नामांकन से महज एक दिन पूर्व आनन-फानन में इनका बुलावा पार्टी नेताओं की ओर से हुआ और अगले ही दिन इनका नामांकन भी दाखिल किया गया. दूसरी ओर जिले के पार्टी समर्थित पंचायत प्रतिनिधियों के बीच यह चर्चा आम हो गयी है कि पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं की भावना की अनदेखी कर जल्दबाजी में प्रत्याशी देने का काम किया है. इसलिए निर्णय सोच-समझ कर ही किया जायेगा.

राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन से प्रदेश युवा राजद के उपाध्यक्ष दिलीप राय को पहली बार चुनावी समर में भाग्य आजमाने का मौका मिला है. बताया जाता है कि पिछले तकरीबन डेढ़ दशक से पार्टी नेताओं की गणेश परिक्रमा करने के बाद इनको यह दिन देखने को मिला है. बिहार की राजनीति के नये समीकरण व अपनी मेहनत के भरोसे इन्हें जीत मिलने का भरोसा है. ये कहते हैं कि गठबंधन को लेकर मतदाताओं में एकजुटता है. इसका लाभ हर हाल में मिलेगा. पंचायत प्रतिनिधियों के मान और सम्मान की रक्षा के साथ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास का संकल्प पहली प्राथमिकता है. सामाजिक एकता के बल पर इन्हें चुनाव में बहुमत की पूरी उम्मीद है. वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि जिले के स्वजातीय राजनीतिक नेताओं के अलावा पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं एवं गठबंधन दल के नेता व कार्यकर्ताओं के सहयोग से इनका चुनावी राह आसान दिख रहा है. वैसे महीनों पूर्व से जारी खुद का चुनावी अभियान भी इनके पक्ष में होने की बात की जा रही है.

अब एक नजर निर्दलीय प्रत्याशी अमिताभ गुंजन पर डालना आवश्यक है. आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज का सुपुत्र अमिताभ तीसरी बार चुनावी समर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. बताया जाता है कि साल 2000 में बेलसंड विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद 2001 के स्थानीय निकाय चुनाव में भी इन्होंने चुनावी समर में हाथ-पांव मारा था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी. उक्त दोनों चुनाव के बाद यह तीसरा चुनाव है, जब अमिताभ बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ही चुनावी अखाड़ा में ताल ठोंक रहे हैं. पूर्व युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके अमिताभ का कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि समाज सेवा दल में रह कर ही किया जाये. माहौल में बदलाव आया है, सभी अब केवल विकास चाहते हैं. इनको जिले के पंचायत प्रतिनिधियों पर भरोसा है. इनके अलावा चौथा देवेंद्र साह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा समर्थित प्रत्याशी के लिए मुसीबत बन कर चुनाव मैदान में डटा है. चर्चा है कि इस निर्दलीय प्रत्याशी के आ जाने से प्रमुख देवेंद्र साह को अपने नाम के सामने डुमरा जोड़ने का आग्रह चुनाव आयोग से करना पड़ा है.

वैसे प्रत्याशियों की दावेदारी में कितना दम है, यह सच्चाई सामने आने में अब महज चंद दिन ही शेष है, लेकिन अब तक जो बातें सामने आयी हैं, उसमें यह कहना मुश्किल है कि जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा. कारण कि सर्वविदित है कि इस चुनाव में वोटों की खरीद-फरोख्त की परंपरा का निर्वाह अब भी किया जाता है. चुनावी जीत को लेकर प्रत्याशी अपनी तिजोरी का कोई भी ताला तोड़ने से बाज नहीं आते हैं. जाति व पार्टी का नारा चुनाव के अंतिम पहर में मौन हो जाता है और वोटों के मोल-जोल का दौर शुरू हो जाता है. जहां तक सीतामढ़ी में प्रत्याशियों के हैसियत का सवाल है तो यह कहा जा सकता है कि अबकी बार कोई किसी से कम नहीं है. हर कोई अपनी जीत सुनिश्चित कराने को लेकर वोटों की मुहबोली कीमत अदा करने की कूबत रखने वाले हैं. बाजार में खुलेआम चर्चा है कि इस बार चुनाव में खाद्यान्न से लेकर शिक्षा माफिया तक अपनी औकात दिखाने को आतुर है. अब देखना है कि जिले के पंचायत प्रतिनिधि विकास व अपने मान-सम्मान के रक्षा की बात करने वाले प्रतिनिधि के चुनाव का कौन सा राह अपनाते हैं. पैसा पर खुद को बेचना पसंद करते हैं अथवा लोकतांत्रिक मर्यादा की रक्षा के साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

एआईपीएमटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

यूपीसीपीएमटी परीक्षार्थियों की उम्मीद बढ़ी

वैष्णवी वंदना

ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) में हुई धांधलियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद उत्तर प्रदेश के छात्रों, उनके अभिभावकों और कुछ सामाजिक संस्थाओं में साहस का संचार हुआ है और उन्होंने यूपीसीपीएमटी में की गई अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है. परीक्षा रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है और यूपी–सीपीएमटी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की भूमिका बनाई जा रही है.

ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट (यूपी–सीपीएमटी) की शुचिता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. परीक्षा का आयोजन कराने वाले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अशोक कुमार सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी सफाई को गलत बताया है. विश्वविद्यालय ने सॉल्वर के पटना में बैठकर नकल कराने का दावे को गलत ठहराया, जबकि विश्वविद्यालय के दावे को अभिभावक बेबुनियाद बता रहे हैं. समय के पहले हड़बड़ी में रिजल्ट घोषित करने के मसले पर विश्वविद्यालय का इतना ही कहना था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. यूपीसीपीएमटी परीक्षा का परिणाम 15 जून को आना था, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से सात जून को ही परिणाम घोषित कर दिया गया. परीक्षा की मेजबानी कर रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली इस वजह से भी शक के घेरे में आ गई है. हालांकि विश्वविद्यालय का कहना है कि 2013 में कानपुर यूनिवर्सिटी की मेजबानी में यूपीसीपीएमटी की परीक्षा हुई थी, तब भी रिजल्ट तय तारीख से पहले घोषित हुए थे. इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि पेपर लीक होने के कारण तीन मई को लिया गया ऑल इंडिया प्री–मेडिकल टेस्ट 2015 सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल हुए लगभग सभी साढ़े छह लाख छात्रों को अब दोबारा टेस्ट देना है.

इसी तरह 25 मई, 2015 को हुए उत्तर प्रदेश सीपीएमटी परीक्षा को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में निरुपमा और दो अन्य अभ्यर्थियों की तरफ याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता की वकील डॉ. नूतन ठाकुर ने कहा कि परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक होने के बात सार्वजनिक हो गई थी और इस सम्बन्ध में एसटीएफ ने थाना गौतमपल्ली में मुकदमा कायम कर 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया था. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में भी यह कहा गया है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एआईपीएमटी की सुनवाई के समय भी एसपी रोहतक की रिपोर्ट से यह बात उजागर हुई कि विजय यादव, नन्हा और सुजीत नाम के तीन लोगों ने उस परीक्षा के साथ–साथ यूपीसीपीएमटी में भी पेपर लीक किया था. इसके बारे में एसटीएफ को कुछ पता ही नहीं चला. लिहाजा, याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए समान मामला होने के कारण यूपीसीपीएमटी परीक्षा को भी निरस्त करने की मांग की गई है. यूपीसीपीएमटी की धांधली के विरोध में स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट ने भी व्यापक मुहिम छेड़ रखी है. ट्रस्ट ने भी परीक्षा रद्द कर उसे दोबारा आयोजित करने की मांग की है. स्वराज–आन्दोलन ट्रस्ट के प्रबन्ध ट्रस्टी घनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि इस वर्ष 25 मई को सम्पन्न यूपी–सीपीएमटी परीक्षा–2015 में प्रश्नपत्र लीक होने, उसका लाभ पेड अभ्यर्थियों तक पहुंचाने व अनेक अनियमितताओं के कारण प्रदेशभर के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है. अभिभावकों की गाढ़ी कमाई मिट्टी में मिल गई है. स्वराज–आन्दोलन की पहल पर अभी तक अभ्यर्थियों ने दो याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की हैं. दिलीप गुप्ता और नवनीत की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश अरुण टंडन की कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और दूसरी याचिका निरुपमा और निर्भय चौहान इत्यादि की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में न्यायाधीश राजन राय की कोर्ट में दाखिल की गई है. इस पर 28 जुलाई को सुनवाई होनी है. रितेश व कुछ अन्य ने मिल कर भी एक याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से एआईपीएमटी रद्द करने के आदेश के बाद यूपीसीपीएमटी पेपर को भी रद्द करने की मांग आंदोलन की शक्ल में बदलती जा रही है. परीक्षार्थियों का आरोप है कि यूपी–सीपीएमटी के पर्चा लीक प्रकरण से कई सफेदपोश भी जुड़े हुए हैं. छात्र तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने प्रेस क्लब पहुंच कर मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखीं और यूपीसीपीएमटी रद्द करने की मांग की. एसटीएफ की ओर से भी थाना हजरतगंज में दर्ज कराई गई एफआईआर में स्पष्ट कहा गया है कि परीक्षा से पूर्व प्रश्नपत्र लीक कराकर यहां पहुंचाया गया और यहां से विभिन्न सॉल्वरों द्वारा इसे साल्व करके पूर्व से निश्चित किए गए परीक्षार्थियों के पास मोबाइल फोन एवं रिसीवर के माध्यम से और भौतिक रूप से छायाप्रति के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर भेजने का कार्य किया गया. इसके एवज में परीक्षार्थियों से 15 से 20 लाख रुपए लिए गए.

शिकायत यहां तक हुई कि यूपीसीपीएमटी परीक्षा के दौरान राजधानी में परीक्षा केंद्र ही बदल दिया गया. विकासनगर स्थित कैरियर कॉन्वेंट कॉलेज परीक्षा के लिए निर्धारित सेंटर था, लेकिन परीक्षा कैरियर कॉन्वेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कराई गई. इसका खुलासा खुद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने किया. यूपीसीपीएमटी की परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से प्रश्न पुस्तिका वापस जमा कराने की प्रक्रिया भी संदेहास्पद बताई जा रही है. परीक्षा समन्वयक प्रो. अजेय गुप्ता का कहना था कि शासनादेश के तहत ऐसा किया गया. परीक्षा के सम्बन्ध में 10 मार्च, 2015 को शासनादेश जारी हुआ था, लेकिन उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से प्रश्न पुस्तिका भी वापस जमा करा ली जाए. ट्रस्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस झूठ को कानूनी चुनौती दी है. घनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने परीक्षा के आवेदन में घोषणा पत्र को किसी राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड कराने की अनिवार्यता कर रखी थी, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय से यह सर्कुलर पहले ही जारी हो चुका है कि अब देश में अभ्यर्थियों के लिए स्वप्रमाणन (सेल्फ अटेस्टेशन) ही मान्य होगा.

15 जून को एआईपीएमटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके पेज नंबर 14 के पांचवें बिन्दु में लिखा है कि जांच के दौरान नन्हा व सुजीत ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि 25 मई, 2015 को आयोजित यूपीसीपीएमटी की परीक्षा के प्रश्नपत्र की उत्तर कॉपी विजय यादव से उसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से प्राप्त हुई थी, जिसका प्रयोग एआईपीएमटी परीक्षा में नकल करने में किया गया था. यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कन्सील्ड वायरिंग के साथ अन्डरगारमेंट में फिट किए गए थे. स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट यह मांग कर रहा है कि प्रदेश के सभी मंडलों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल आने वाले भवनों में जैमर, ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे व अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की गारंटी हो. परीक्षा के लिए अलग से भवन बने तो यह आदर्श होगा, उसी भवन में यूपी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, बैंकिंग व अन्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हों. प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने वाले व अनियमितता करने वालों के लिए सख्त कानून बने और कम से कम छह माह तक अभियुक्त को जमानत न मिल पाए. शीघ्र केस फाइनल हो और दोषी को उम्र कैद की सजा हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

यह धंधा अब चलन बन चुका है...

उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट में प्रश्न पत्र लीक होना, नकल कराना, परीक्षा केंद्र बदलना और पहले से तैयार उत्तर की कॉपी मोटी रकम लेकर बंटवाना पुराना चलन है. पिछले साल भी गाजियाबाद में यूपीसीपीएमटी के पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द कर दी गई थी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तब भी गंभीरता का उपक्रम करते हुए मुख्य सचिव आलोक रंजन को उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर शीघ्र जांच कराने का आदेश दिया था, लेकिन सब गंभीरता ढाक के तीन पात ही निकली. उस बार परीक्षा का आयोजन लखनऊ का प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज युनिवर्सिटी (केजीएमयू) कर रहा था. गाजियाबाद के इलाहाबाद बैंक में जिस स्ट्रॉन्ग रूम में क्वेश्चन पेपर रखे गए थे, उसी में छेड़छाड़ की गई थी. उस समय भी नोएडा से यूपी एसटीएफ की टीम गाजियाबाद पहुंची थी. खूब गहमागहमी मची. गाजियाबाद के सिटी कोतवाली में पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन धांधली बंद नहीं हुई. मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठी थी, लेकिन अखिलेश सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. फिर तो कहा जाने लगा कि एसटीएफ की जांच दोषियों को और उनके राजनीतिक संरक्षकों को बचाने का काम करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ और अनुभवी नौकरशाह ने कहा 10 साल पहले भी यूपीसीपीएमटी में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था. यह 2005 की बात है. इस घटना के बाद तमाम सख्त नियम बनाए गए और बड़ी गंभीरता के साथ उस नियम के पालन की कसरतें की गईं, लेकिन उसके बाद से हर साल ही प्रदेश में कहीं न कहीं प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं सामने आने लगीं. वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नागरिकों, नेताओं, नौकरशाहों और दलालों की रजामंदी और मिलीभगत से यह धंधा चलता है, इसे कोई रोक नहीं सकता. ■

हरीश का युवा रोजगार योग

राजकुमार शर्मा

विश्व योग दिवस पर मोदी के योग कार्यक्रम से पल्ला झाड़ने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को योग का राजनीतिक नफा–नुकसान जब समझ में आया तो उन्होंने तुरन्त यू–टर्न लेते हुए युवा रोजगार योग करने की ठान ली. मोदी के योग के कार्यक्रम से जनता का भारी जुड़ाव होने का संकेत मिलते ही हरीश को समझ में आ गया कि विरोध से हानि उठानी पड़ सकती है. इसी से भयाक्रान्त हरीश सरकार मंच पर योग करते दिखी. विश्व योग दिवस पर देवभूमि की पूरी कांग्रेस योग गुरु बाबा रामदेव के योग पर हमलावर के साथ चाहती थी कि नेहरू परिवार, कांग्रेस का जबरदस्त विरोध कर मोदी की सरकार बनाने में मददगार रहे बाबा के हेडमास्टरी में भारत में योग का कार्यक्रम न संचालित किया जाए.

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोदी सरकार से भी बड़ी लकीर खिंचने की मंशा से योग से निरोग से एक कदम आगे बढ़ कर योग से युवा को मिले रोजगार का तरीका पेश कर जो कार्य किया, वह हिमालयी राज्य ख़ास तौर से युवकों में चर्चा का विषय बना है. हरीश सरकार ने प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान तो कर डाला, इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र के पाले में गेंद सरकाने में भी देरी नहीं की. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने योग सिखाने के लिए रखे जाने वाले अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस योजना को राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत अंगीकृत करने का अनुरोध किया है. इन्होंने कहा कि राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का होने के नाते इसमें 90/10 के अनुपात में अनुदान देने दिया जाए. उत्तराखंड एक मात्र ऐसा प्रदेश है, जो योग के प्रोत्साहन के लिए पूरी कार्ययोजना लेकर सामने आया है. इस तरह से देखा जाय तो उत्तराखंड युवकों को योग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने वाला अव्वल राज्य बन गया है.

बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार बर्फ से ढके केदारनाथ जैसे पावन क्षेत्रों में योग कराने की संभावनाओं को तलाश कर रही है. यह देखा जा रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में योग कराना संभव है कि नहीं. केदारनाथ में भी योग कराने की संभावना को तलाशा जाएगा.

बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार बर्फ से ढके केदारनाथ जैसे पावन क्षेत्रों में योग कराने की संभावनाओं को तलाश कर रही है. यह देखा जा रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में योग कराना संभव है कि नहीं. केदारनाथ में भी योग कराने की संभावना को तलाशा जाएगा. इस दौरान उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वे अपने योग के प्रति उत्साही मित्रों को भी केदारनाथ में आकर योग करने को आमंत्रित करेंगे. उन्होंने योग अनुदेशकों के संबंध में केंद्र से सहयोग की अपेक्षा के बाबत पत्र लिखे जाने की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी साझा की. उन्होंने कहा कि अगले वर्ष होने वाले अर्द्ध कुंभ के दौरान ऋषिकेश में योग महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए तिथि अभी तय करनी शेष है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में योग एंड वेलनेस योजना पर कार्य किया जा रहा है. इस कड़ी में ऋषिकेश व बागेश्वर में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 150 स्कूलों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा. यहां शिक्षा विभाग की ओर से प्रशिक्षित लोग रखे जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार योग दिवस को लेकर अपनी कार्ययोजना पर तकरीबन एक माह पहले से कार्य कर रही थी. उन्होंने कहा पहले यह घोषणाएं जागेश्वर के कार्यक्रम में होनी थी, अब यह देहरादून में की गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगा को पर्यटन के साथ जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा. सरकार अब प्रदेश के तीन व पांच सितारा होटलों में योग की सुविधाएं अनिवार्य करने जा रही है. इसके तहत होटलों को इन सुविधाओं के बिना सरकार की ओर से एनओसी नहीं दी जाएगी. इसके अलावा सरकार उत्तराखंड आयुर्वेद चिकित्सालय में फैकल्टी ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी की स्थापना कराएगी. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार व इसके माध्यम से रोजगार सृजन के संबंध में आयोजित बैठक में उपरोक्त निर्देश जारी किए. इन्होंने अपर मुख्य सचिव एस राजू को विद्यालयों में मानदेय आधार पर योग प्रशिक्षकों के पद एक माह में आरंभ करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री रावत ने केंद्र से मिलने वाले सहायता को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में 411 करोड़ रुपये कम मदद मिली है. गत वित्तीय वर्ष शुरुआती तीन माह में सरकार को सभी मदों में 2372.83 करोड़ रुपया मिला था, जबकि इस वर्ष कुल 1961 करोड़ रुपये मिला है. इसके अलावा पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं मिल पाया है. अर्द्ध कुंभ के लिए अभी तक कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है. ■

कार्ययोजना के मुख्य बिंदू

- प्रदेश के 68 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में प्रतिदिन होगा योग.
- 25 नगर निकायों में एक माह के भीतर चिन्हित होंगे योगा कॉर्नर.
- आयुष के जरिए तैनात प्रशिक्षक देंगे मुफ्त प्रशिक्षण.
- देहरादून के गांधी पार्क व हल्द्वानी के स्टेडियम में पुलिस के सहयोग से चलाए जाएंगे योग कॉर्नर, 15 दिनों के भीतर देंगे कार्ययोजना.
- स्कूलों में योग को पाठ्यक्रम के रूप में किया जाएगा शामिल. शिक्षा विभाग को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सहयोग से पाठ्यक्रम बनाने के निर्देश. कैबिनेट में लाया जाएगा मुद्दा.
- वीआइपी घाट हरिद्वार और जीएमवीएन ऋषिकेश भी 12 अन्य क्षेत्रों के साथ योग क्षेत्र के रूप में किए जाएंगे विकसित.
- कुमाऊं विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा के साथ जोड़ा जाएगा योग.

feedback@chauthiduniya.com

व्यापमं के बाद अब डीमेट घोटाला...

मध्यप्रदेश डेंट्ल एंड मेडिकल एडमिशन टेस्ट (डीमेट) की शुरूआत साल 2006 में हुई थी. पहले ही साल यह परीक्षा विवादों में घिर गई थी. इस वजह से कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद परीक्षा को बहाल कर दिया गया. इसके बाद 2007 से 2009 तक हर साल सरकार के पास डीमेट को लेकर शिकायतें आती रहीं. साल 2009 में सरकार ने निर्णय किया कि निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटें व्यापमं द्वारा आयोजित प्री मेडिकल टेस्ट(पीएमटी)के जरिये भरी जायेंगी. शासन के इस फैसले के खिलाफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद निर्णय दिया कि निजी मेडिकल कॉलेजों की 43 प्रतिशत सीटें डीमेट से, 42 प्रतिशत सीटें व्यापमं से और 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटे से भरी जायेंगी. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सीटों को भरने की यह व्यवस्था आज भी प्रदेश में लागू है.

नवीन चौहान

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले की जांच अभी चल ही रही थी, तब तक मध्य प्रदेश के निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश में घोटाले का पर्दाफाश हो गया. अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के होने वाली परीक्षा डीमेट से जुड़ा घोटाला तकरीबन दस हजार करोड़ रुपये का है. शासन के कोटे से निजी डेंटल और मेडिकल कॉलेजों में भरी जाने वाली सीटों को भरने में पिछले 10 सालों में जबरदस्त तरीके से हेराफेरी की गई है. इसके लिए प्राइवेट कॉलेजों ने तरह-तरह के दांव-पेंच का इस्तेमाल किया और करोड़ों रुपये वारे-न्यारे कर दिए.

मध्य प्रदेश डेंटल एंड मेडिकल एडमीशन टेस्ट (डीमेट) की शुरुआत साल 2006 में हुई थी. पहले ही साल यह परीक्षा विवादों में घिर गई थी. इस वजह से कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद परीक्षा को बहाल कर दिया गया. इसके बाद 2007 से 2009 तक हर साल सरकार के पास डीमेट को लेकर शिकायतें आती रहीं. साल 2009 में सरकार ने निर्णय किया कि निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटें व्यापमं द्वारा आयोजित प्री मेडिकल टेस्ट(पीएमटी)के जरिये भरी जायेंगी. शासन के इस फैसले के खिलाफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद निर्णय दिया कि निजी मेडिकल कॉलेजों की 43 प्रतिशत सीटें डीमेट से, 42 प्रतिशत सीटें व्यापमं से और 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटे से भरी जायेंगी. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सीटों को भरने की यह व्यवस्था आज भी प्रदेश में लागू है.

अब बात आती है कि आखिर घोटाला कहां और कैसे हुआ. मध्य प्रदेश में सात निजी मेडिकल और 18 डेंटल कॉलेज हैं. इन निजी कॉलेजों में 900 सीटें एमबीबीएस की और 198 सीटें पीजी की हैं. निजी कॉलेजों का लालच केवल डीमेट कोटे तक ही सीमित नहीं रहा. ये कॉलेज स्टेट कोटे का सीटों को भी हजम करने में जुटे रहे. व्यापमं मामले में व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने चौथी दुनिया से बताया कि कॉलेजों ने इसके लिए नया तरीका इजाद किया. कॉलेज पीएमटी परीक्षा में पैसे देकर कुछ सीनियर छात्रों या कहें स्कोरर को बैठा देते थे. परीक्षा पास करने के बाद इन छात्रों ने निजी कॉलेजों की स्टेट कोटे की सीट पर दाखिला ले लिया और कुछ दिन बाद कॉलेज से नाम कटा लिया. इस तरह उस सीट को कॉलेज बेचने के लिए फिर से स्वतंत्र हो गए. आशीष ने बताया कि जे पी बघेल नाम के छात्र ने साल 2010 में ग्वालियर स्थित गजराराजे मेडिकल कॉलेज(जीआरएमसी) में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लिया था. साल 2011 में वह व्यापमं द्वारा आयोजित पीएमटी की परीक्षा में बैठा और चयनित हो गया. चयन के बाद उसने भोपाल के चिरायु मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटे की एमबीबीएस की सीट आवंटित करवा ली. कुछ दिनों बाद फीस न होने की बात कहकर अपना एडमीशन रद्द करवा लिया. बाद में चिरायु मेडिकल कॉलेज की इस सीट को डीमेट कोटे में ट्रांसफर कर दिया गया. यह डीमेट से हुई धांधली का एक उदाहरण है. अब तक इस तरह के 50 मामले सामने आए हैं. इसके बाद यदि वह सीट एमबीबीएस की है तो 15 से 20 लाख रुपये और पीजी की सीट 1.5 से 2 करोड़ रुपये में भर दी जाती थी. निजी मेडिकल में स्टेट कोटे की 42 प्रतिशत सीटों के एवज में राज्य सरकार निजी मेडिकल कॉलेजों को अनुदान देती है, लेकिन सीट को मैनेजमेंट कोटे से भरने के बाद भी कॉलेज राज्य सरकार से ग्रांट लेते रहे, यह राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी है.

निजी मेडिकल कॉलेजों ने व्यापमं कोटे की सीटों पर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये लेकर छात्रों को प्रवेश दे दिया. क्या निजी मेडिकल कॉलेजों में हो रहे एडमीशन के इस खेल की सरकार को भनक नहीं थी या फिर सरकार भी इसमें बराबर की भागीदार थी. साल 2006 में डीमेट की शुरुआत के बाद से अब तब प्रदेश सरकार में पांच चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं, क्या कमल पटेल, अजय विश्नोई, महेन्द्र हार्डिया, अनूप मिश्रा और वर्तमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस घोटाले में शामिल हैं, यह बात तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या उपरोक्त सभी से एसआईटी पूछताछ करेगी? क्योंकि सरकार की शह के बिना निजी मेडिकल कॉलेज इस तरह प्रवेश प्रक्रिया में इस तरह मनमानी नहीं कर सकते थे. इसका सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है कि राज्य सरकार को मामले की पूरी जानकारी थी. शिवराज सिंह चौहान और उसके मंत्री डीमेट मामले में जान कर अनजान बने रहे. इस सांठगांठ की वजह से न जाने कितने छात्रों ने अकाल मौत को गले लगा लिया. उस वक्त उसे आत्महत्या करार दिया गया था, लेकिन अब जब पूरी चयन प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है तो उन छात्रों की आत्महत्या को हत्या मानकर व्यापमं और डीमेट घोटाले के आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुक़दमा भी चलाया जाना चाहिए.

भले ही शिवराज सिंह स्वयं को व्यापमं घोटाले में पाक साफ बता रहे हों, लेकिन जिस तरह इस घोटाले की जांच दिन-ब-दिन उलझती जा रही है और रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में उनके लिए आने वाला वक्त शिवराज सिंह के लिए आसान नहीं होने वाला है. जबलपुर हाईकोर्ट ने डीमेट के संबंध में सरकार को नोटिस जारी कर दिया है ऐसे में शिवराज सरकार का बच पाना मुश्किल ही नहीं, बल्कि लिए इज्जत बचा पाना आसान नहीं होगा.■

navinonline2003@gmail.com

कैसे हुआ घोटाले का पर्दाफाश

करीब चार महीने पहले व्यापमं घोटाले की जांच के दौरान ग्वालियर एसआइटी ने अतुल शर्मा नामक दलाल को गिरफ्तार किया. तब डीमेट घोटाले की पहली परत खुली. उसने बताया कि 2010 एमएस कोर्स में उसने ऋचा जौहरी का एडमिशन कराया था. ऋचा जबलपुर के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. एमएस जौहरी की बेटी हैं. अतुल ने व्यापमं घोटाले के मुख्य आरोपी नितिन मोहिंद्रा के नाम का जिक्र भी किया था. मोहिंद्रा फिलहाल जेल में हैं. जब उनसे पूछताछ हुई, तो खुलासा हुआ कि ऋचा का नाम योगेश कुमार उपरीत ने उनके पास भेजा था. उपरीत 2003-04 में व्यापमं के निदेशक थे. रिटायरमेंट के बाद उपरीत ने जबलपुर में एक डेंटल कॉलेज शुरू किया. वे एपीएमडीसी(एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज) के सदस्य और बाद में 10 सालों तक डीमेट के परीक्षा नियंत्रक भी रहे हैं. उन्हें 3 जून,2015 को ग्वालियर एसआइटी ने गिरफ्तार किया. 72 वर्षीय उपरीत ने पूछताछ के दौरान कई बड़े लोगों के नाम उजागर किए हैं. निजी कॉलेज इस जांच को दबाना चाहते थे, ताकि पूरा मामला व्यापमं घोटाले तक ही सिमटकर रह जाए. उपरीत के बयानों को यदि सच माना जाये तो बीडीएस, एमबीबीएस, एमएस और एमडी कोर्स में एडमीशन के नाम पर उगाहे गए. हर साल तकरीबन 1500 सीटें डीमेट के जरिए भरी गईं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह घोटाला तकरीबन दस हजार करोड़ रुपये का है. योगेश उपरीत ने प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों की अरबों की काली कमाई का राज एसआईटी के सामने खोल दिया है. उन्होंने एसआईटी को बताया कि निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए डीमेट परीक्षा तो केवल औपचारिकता के लिए होती है, जिन छात्रों का सलेक्शन होना होता था, उनकी लिस्ट कॉलेज प्रबंधन पहले ही डीमेट को थमा देता था और उन्हीं छात्रों की आंसरशीट के गोले काले किए जाते थे.■

डीमेट के जरिये नेताओं ने भाई-भतीजों को डॉक्टर बनाया

डीमेट के जरिये गलत तरीके से अपने बच्चों और रिश्तेदारों को मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन दिलाने वालों की सूची लंबी है. इस सूची में नेताओं के अलावा अफसर भी शामिल हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने पिछले आरोप लगाया था कि प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बेटी आकांक्षा और अवंतिका का, अजय विश्नोई ने बेटे अभिजीत का, कमल पटेल ने भतीजी प्रियंका और इंदौर की विधायक मालिनी गौड़ ने कर्मवीर गौड़ का दाखिला कराया. कटारे ने कुछ और नाम लिए थे. इनमें स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्र, शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता, पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर, हरनाम सिंह राठौड़, नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और पीस कमेटी के अखिलेश पांडे शामिल हैं. हालांकि सरकार के प्रवक्ता और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए डीमेट का गलत फायदा उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं के नाम भी उजागर किए. इनमें आरिफ अकील,पीसी शर्मा, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, अरुण यादव, हजारी लाल रघुवंशी और तुलसी सिलावट आदि शामिल हैं.

डीमेट मामले में कोर्ट ने जारी किया सरकार को नोटिस

रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने मध्यप्रदेश हाइकोर्ट में डीमेट के संबंध में उन्होंने 17 जून, 2015 को याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर और जस्टिस किशोर कुमार त्रिवेदी की दो सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार, मुख्य सचिव(चिकित्सा), मुख्य सचिव(गृह), मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक, पुलिस महानिदेशक, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति सहित 60 लोगों को नोटिस जारी किया है. पारस सकलेचा ने चौथी दुनिया से बात करते हुए बताया कि माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर साल 2007 से 2014 तक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में डीमेट कोटे से भर्ती में फर्जीवाड़े की सीबीआई से जांच कराने, एनआरआई कोटे की भर्ती की सीबीआई जांच कराने तथा 2007 से 2013 के दरम्यान पीएमटी से भरी जाने वाली स्टेट कोटे की सीटों को मैनेजमेंट कोटे से भरने की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी. साथ ही उन्होंने 12 जुलाई, 2015 को होने वाली डीमेट परीक्षा माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग की थी. 12 जुलाई को होने वाली डीमेट परीक्षा पर सुनवाई के लिए अदालत ने 3 जुलाई को सुनवाई करेगी. सकलेचा का कहना है कि शिवराज सरकार मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में धांधली के फर्जीवाड़े को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है. उन्होंने बताया कि डीमेट में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है. एडमीशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी(एएफआरसी) की अपीलीय कोर्ट ने अपनी जांच में पाया कि 2009 से 2013 के बीच निजी मेडिकल कॉलेजों की स्टेट कोटे की 731 सीटें मैनेजमेंट कोटे से भरी गईं. अपीलीय कोर्ट ने अपनी जांच में यह भी पाया कि वर्ष 2013 में सरकारी कोटे की 198 सीटों पर मैनेजमेंट कोटे से छात्रों के दाखिले आखिरी दिन किए गए थे. यह सब सोची-समझी साजिश थी. सकलेचा ने बताया कि जब वे विधायक थे, तब उन्होंने विधानसभा में डीमेट को लेकर सवाल उठाया था कि इस परीक्षा के माध्यम से जिन छात्र-छात्राओं ने निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश लिया था. उनमें से आधे से छात्र-छात्राओं के अंक 12 में 50 से 60 प्रतिशत के बीच थे. उन्होंने कहा कि इन सभी ने पैसे के बल पर प्रवेश लिया है. इससे प्रदेश में गुणवत्ता वाले चिकित्सकीय मानव संसाधन का निर्माण नहीं होगा, जो कि आगे चलकर सीधे तौर पर प्रदेश और देश दोनों को प्रभावित करेगा.■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

आडवाणी जी ने एक मामूली, लेकिन महत्वपूर्ण बयान दिया है कि 40 साल बाद भी आपात स्थिति जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. लोगों ने विभिन्न तरीकों से इस बयान की व्याख्या की है, लेकिन सबसे तर्कसंगत व्याख्या यह हो सकती है कि आडवाणी जी जैसे एक पुराने राजनेता सत्ता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज आप जो कर रहे हैं, उसका दीर्घकालिक दुष्परिणाम निकले. जब तक आप सत्ता में हैं, आपको पता नहीं चलता कि क्या गलत है.श्रीमती गांधी बिना सोचे-समझे इतना आगे निकल गईं कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो खुद अपने द्वारा उठाए गए कदम में ही उलझ जाएंगी.

यह सरकार एनडीए-2 की है या यूपीए-3 की

केन्द्र सरकार में एक वर्ष बाद प्रधानमंत्री को अब सत्ता का असल स्वाद पता चल रहा है. सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा. दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस हार से सबक सिखने के बजाए और अपनी राजनीतिक लोकप्रियता को बढ़ाने के बजाए वे प्रशासनिक तरीके से केजरीवाल सरकार के लिए मुसिबतें खड़ी करने लगे. उन्होंने केजरीवाल के लिए बाधाएं पैदा करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय का उपयोग किया. सारे सही और गलत तरीकों का उपयोग किया. यह रणनीति कारगर नहीं होगी. जिस किसी ने भी इंदिरा गांधी के लंबे शासनकाल का अध्ययन किया है, उसे एहसास है कि प्रशासनिक उपाय बहुत कारगर साबित नहीं होते हैं. दिल्ली में तो इसे हर हाल में असफल होना है. ऐसा लगता है कि दिल्ली भाजपा, पार्टी का किरण बेदी को नेता चुनने की वजह से सहयोग नहीं कर रही है. यदि भाजपा पुन: स्थापित होना चाहती है तो उसे पुराने संगठन को पुनर्गठित करना होगा.

नई दिल्ली की राजनीति से एक अन्य पहलू निकलकर सामने आ रहा है. इंडियन प्रीमियर लीग वाले ललित मोदी चाहते थे कि भारत आए बिना उन्हें ब्रिटेन से यात्रा करने की सहूलियत मिले. ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय उच्चायोग में आवेदन किए बगैर वे ब्रिटिश सरकार से यात्रा करने की अनुमति पाने के लिए अनुरोध कर रहे थे. वह भी ब्रिटेन के दस्तावेजों के आधार पर. अब यहां मामला सामने आ गया, जिसकी वजह से सुषमा स्वराज को भारी शर्मिन्दगी उठानी पड़ी. यह भ्रष्टाचार की बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अविवेक की बात है. यह व्यवहार करने का तरीका नहीं है. भारत एक बड़ा देश है और आपको इस तरह के छोटे से एहसान के लिए काम नहीं करना चाहिए था. शायद प्रधानमंत्री को इस सब की जानकारी थी, इसलिए सुषमा स्वराज को हटाया नहीं गया. ब्रिटेन में स्थायी निवास पाने के लिए वसुन्धरा राजे ने ललित मोदी की सिफारिश की और यहां यह भी कहा कि इस बात को लीक न किया जाए कि हमने कोई सिफारिश की है. यह बचकानी हरकत थी. कोई भी ऐसा आदमी, जिसका 20-30 साल का सार्वजनिक जीवन रहा है, ऐसा नहीं करेगा. मॉरीशस रूट के माध्यम से वसुंधरा राजे के बेटे की कंपनी को दिए गए कुछ ऋण की बात भी सामने आई है. मॉरीशस रूट और इस तरह का व्यापार हमेशा से संदिग्ध रहा है, लेकिन इस मामले में यह बताना कि भ्रष्टाचार कहां हुआ है, यह बताना बेहद मुश्किल है. लेकिन इलेक्ट्रानिक मीडिया चैनल और अखबार ऐसी खबरों से भरे पड़े हैं.

इसी बीच आडवाणी जी ने एक मामूली, लेकिन महत्वपूर्ण बयान दिया है कि 40 साल बाद भी आपात स्थिति जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. लोगों ने विभिन्न तरीकों से इस बयान की व्याख्या की है, लेकिन सबसे तर्कसंगत व्याख्या यह हो सकती है कि आडवाणी जी जैसे एक पुराने राजनेता सत्ता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज आप जो कर रहे हैं, उसका दीर्घकालिक दुष्परिणाम निकले. जब तक आप सत्ता में हैं, आपको पता नहीं चलता कि क्या गलत है. श्रीमती गांधी बिना सोचे-समझे इतना आगे निकल गईं कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो खुद अपने द्वारा उठाए गए कदम में ही उलझ जाएंगी. बेशक, मोदी समर्थकों ने इस बयान को मोदी के खिलाफ माना और विरोधी खुश हो गए, मानों बहुत सारी समस्याएं हैं. मेरी राय में ये सिर्फ एक वरिष्ठ नेता की हल्की चेतावनी है. वे देश को जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके निहितार्थ को समझना चाहिए. वे वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं और राजनीति में लंबे समय तक उन्होंने सेवा की है. अब समय आ गया है कि उन नेताओं की बातों पर ध्यान दिया जाए, जिन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की है.

आखिरी दो बजट भी सामान्य बजट ही थे, क्योंकि लोगों और बाजार को बजट से काफी आशायें थीं, जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान कहा जा रहा था और वादे किए जा रहे थे. दिलचस्प बात यह है कि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यहां सरकार यूपीए-2 की नीतियों को ही आगे बढ़ाना चाहती है और यूपीए-3 की तरह दिखना चाहती है, जैसा कि अभी नज़र आ रहा है. वित्त मंत्री ने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था कि वे टैक्स टेररिज्म (कर आतंकवाद) को खत्म करेंगे, इसके लिए कुछ सर्कुलर भी जारी किए गए, लेकिन वे काफी नहीं हैं.

मुंबई से भी कुछ घोटालों की खबरें आ रही हैं. एक जूनियर मंत्री, जिसने अपने राजनीतिक जीवन का सफर हाल ही में शुरू किया है, उनसे शायद ये गलती हुई है. उन्होंने सीधे पार्टी को भुगतान करने की बजाए बिचौलियों को भुगतान किया है. इसे अभी भ्रष्टाचार के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन नौकरशाही के स्तर पर चूक जरूर हुई है. सवाल यह है कि वे क्या कर रहे थे? अगर मंत्री कुछ गलत फैसला कर रहा है तो ब्यूरोक्रेसी को टोकना चाहिए. इससे यही जाहिर होता है कि ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री की अनुभवहीनता का फायदा उठा रहे हैं. सरकार को बहुमत का अहंकार नहीं होना चाहिए. बहुमत आता है, जाता है, लेकिन व्यवस्था ठीक से चलती रहना चाहिए. खैर, वक्त है कि चीजों को समय रहते दुरुस्त किया जाए.

जहां तक ललित मोदी प्रकरण का सवाल है, तो उनके बारे में मेरी जो थोड़ी बहुत जानकारी है, उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि वो खुद को क्रेडिट देने के चक्कर में किसी और की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जैसा उन्होंने हाल ही में किया है. आखिरकार, सुषमा स्वराज और वसुन्धरा राजे ने उनकी मदद की. मोदी को चाहिए था कि उनकी छवि को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन वे इस बात का इजहार खुशी से कर रहे हैं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है.

इस बीच, कई योजनाओं की घोषणाएं हुई हैं. स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात है, लेकिन वास्तविक रूप में क्या हो रहा है, सरकार को यह लोगों को बताना चाहिए. महंगाई नियंत्रण में नहीं है. निजी क्षेत्र की भावनाएं बेहतर नहीं हुई हैं. विदेशी निवेशक अभी भी मैट नोटिस को लेकर आशंकित हैं. वित्त मंत्री खुद एक कॉरपोरेट वकील और बुद्धिमान व्यक्ति हैं. मैं यह नहीं कह सकता कि वो चीजों को पटरी पर क्यों नहीं ला पा रहे हैं. बेशक लोग कह रहे हैं कि सबकुछ पीएमओ द्वारा नियंत्रित है यह मैं नहीं जानता. वित्त मंत्रालय में ऐसे अधिकारी हैं, जो यहां के क्रियाकलापों की समझ रखते हैं और परिणाम को समझते हैं. विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आप जो कर रहे हैं, उससे कुछ अलग करना होगा. आखिरी दो बजट भी सामान्य बजट ही थे, क्योंकि लोगों और बाजार को बजट से काफी आशायें थीं, जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान कहा जा रहा था और वादे किए जा रहे थे. दिलचस्प बात यह है कि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यहां सरकार यूपीए-2 की नीतियों को ही आगे बढ़ाना चाहती है और यूपीए-3 की तरह दिखना चाहती है, जैसा कि अभी नज़र आ रहा है. वित्त मंत्री ने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था कि वे टैक्स टेररिज्म (कर आतंकवाद) को खत्म करेंगे, इसके लिए कुछ सर्कुलर भी जारी किए गए, लेकिन वे काफी नहीं हैं. आयकर विभाग की मानसिकता सालों में बनती है. उसे एक दिन में नहीं बदला जा सकता. अगर आप ऐसे करते हैं और राजस्व का नुकसान होता है तो वे इसका दोष सरकार की नीतियों पर ही मढ़ देंगे. वित्त मंत्री को अवकाश प्राप्त राजस्व सेवा के अधिकारियों की एक छोटी सी कमेटी बनानी चाहिए, जो सरकार को दिशा दे सके, कानून में बदलाव ला सके. जब तक कानून में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

पुलिस अधिकारी को किसने गोली मारी

यह एक ऐसी रिपोर्ट है, जो उन दिनों की पुलिस का चेहरा तो साफ़-साफ़ दिखाती ही है, साथ ही यह भी दिखाती है कि पुलिस व्यवस्था में अपने उच्च अधिकारियों को बचाने का क्या मैकेनिज्म है. इस रिपोर्ट से कई सवाल खड़े किए गए थे. ये ऐसे सवाल थे, जो एक पत्रकार ने अपनी खोजबीन की बिना पर खड़े किए थे, जिन्हें अपराधियों से निपटने में माहिर पुलिस नज़रअंदाज कर गई थी. इस रिपोर्ट को पढ़कर आपको अंदाजा हो सकेगा कि पुलिस की कार्यशैली में कोई बदलाव आया या नहीं?

एक फ्लैट में दो पुरुष और एक स्त्री. अचानक गोली चलने की आवाज़ तथा औरत की तेज चीख सुनाई दी. आसपास के लोग पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष के सिर में गोली लगी है, जो बाद में अस्पताल जाकर मर गया. लेकिन पुलिस ने वहां मौजूद दूसरे पुरुष तथा स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया. इतना ही नहीं, उस कमरे में बच रहे पुरुष को सारे सबूत मिटाने का मौक़ा भी दिया गया. गोली के शिकार व्यक्ति का नाम था राजीव वर्मा. उत्तर प्रदेश पीएसी की उनतालिसवीं बटालियन के कमांडेंट राजीव वर्मा की मौत उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों के खोखले चरित्र और उनमें पनप रही गंदी आदतों के कारण समय-असमय घटने वाली अशोभनीय वारदातों में से एक है.

28 सितंबर, 1981 को लखनऊ में इतनी तेज वर्षा हो रही थी कि स्कूलों में रेनी डे की छुट्टी दे दी गई थी. उस दिन लखनऊ के पुलिस लाइन में स्थित फ्लैटों में रहने वाले अधिकारियों में से कुछ के यहां नाश्ते की तैयारी चल रही थी और कुछ लोग अपने-अपने बरामदों में बैठे चाय की चुस्की के साथ बारिश का आनंद ले रहे थे. इसी बीच साढ़े नौ बजे के क़रीब लखनऊ के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) प्रकाश सिंह के फ्लैट से ऐसी आवाज़ आई, जैसे कोई पंखा टूटकर गिरा हो या गीली मिट्टी पर पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा हो. इसी आवाज़ के साथ श्रीमती प्रकाश सिंह की एक तेज चीख सुनाई दी.

राजीव वर्मा की पत्नी मंजू वर्मा ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि उस दिन सुबह में उन्होंने मेज पर नाश्ते की प्लेट लगाना शुरू किया. इसी बीच राजीव वर्मा ने कहा, सरदार जी के यहां से आते हैं फोन करके. क्योंकि, उनका फोन उस समय खराब था. इसके पंद्रह मिनट बाद गोली की आवाज़ और चीख सुनकर जब वह प्रकाश सिंह के फ्लैट में पहुंची, तो श्री वर्मा को ज़मीन पर गिरा पाया.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

चीख सुनकर प्रकाश सिंह के फ्लैट के नीचे तथा आसपास के घरों में रहने वाले लोग बाहर आए. कुछ बड़े अधिकारी जैसे श्री पंडा, जो इस समय बलिया में पुलिस अधीक्षक हैं, श्री भट्ट (एसपी-विजिलेंस), डीआईजी एसएनपी सिन्हा आदि प्रकाश सिंह के फ्लैट पर पहुंचे. वहां उन्होंने राजीव वर्मा को फर्श पर गिरा पाया, जिनके सिर में गोली लगी थी! गोली की आवाज़ सुनकर ट्रैफिक पुलिस के एक उपाधीक्षक श्री अरोड़ा भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जो उस वक्त उसी इलाके से गुज़र रहे थे. उन्होंने ही राजीव वर्मा को उठाकर अपनी जीप से बलरामपुर अस्पताल तक पहुंचाया. अस्पताल में कोई न्यूरो सर्जन नहीं था. श्री अरोड़ा मेडिकल कॉलेज से डॉ. दूबे को लेकर आए, खून का भी इंतजाम किया गया. लेकिन यह सारी व्यवस्था करने में एक घंटा से भी ज़्यादा समय लग गया. राजीव वर्मा की मौत सिर का ऑपरेशन होने से पहले ही हो गई. प्रकाश सिंह, जिनके फ्लैट में श्री वर्मा को गोली लगी थी, राजीव वर्मा के अस्पताल जाने के दस मिनट बाद नीचे उतरे तथा अपनी कार में अस्पताल गए. इन दस मिनटों में प्रकाश सिंह ने टेलीफोन का रिसीवर ठीक किया, अपने हेड कांस्टेबल से कहकर रिवाल्वर खाली कराया तथा उंगलियों के निशान साफ़ कराए.

राजीव वर्मा की पत्नी मंजू वर्मा ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि उस दिन सुबह में उन्होंने मेज पर नाश्ते की प्लेट लगाना शुरू किया. इसी बीच राजीव वर्मा ने कहा, सरदार जी के यहां से आते हैं फोन करके. क्योंकि, उनका फोन उस समय खराब था. इसके पंद्रह मिनट बाद गोली की आवाज़ और चीख सुनकर जब वह प्रकाश सिंह के फ्लैट में पहुंची, तो श्री वर्मा को ज़मीन पर गिरा पाया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौक़े पर पहुंचे. पुलिस महानिरीक्षक ने सीआईडी को जांच का काम सौंपा, जब इसमें ढिलाई दिखाई पड़ी, तो मुख्यमंत्री ने चौबीस घंटे में जांच पूरी करने के आदेश दिए. लेकिन इन पंक्तियों के लिखे जाने तक यानी हत्या के चौबीस दिनों बाद तक न जांच पूरी हुई और न प्रकाश सिंह के विरुद्ध दफा 302 (कत्ल) का मुक़दमा कायम हुआ. उनके विरुद्ध साक्ष्यों को नष्ट करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत मुक़दमा दायर किया गया, जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है.

खुफिया विभाग के अधिकारी इस घटना के पीछे तीन संभावनाएं देख रहे थे-हत्या, दुर्घटना या आत्महत्या की. इन्हीं अनुमानों के आधार पर उन्होंने जांच की शुरुआत की. लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी जांच में कितनी रुचि ले रहे हैं, यह इसी बात से जाहिर होता है कि 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के यहां मंजू वर्मा एवं प्रकाश सिंह को बुलाकर सुलह कराने की कोशिश की गई. जानकार सूत्रों का कहना है कि आईपीएस अधिकारियों ने यह सोचा कि जब राजीव वर्मा मर ही गए, तो इस प्रकरण पर ज़्यादा छानबीन से आईपीएस बिरादरी की बदनामी क्यों होने दी जाए. अत: सीआईडी अधिकारियों को इशारा दिया गया कि दुर्घटना की संभावनाओं को ही आधार बनाकर जांच की जाए. यदि इसे दुर्घटना मान लिया जाएगा, तो प्रकाश सिंह के विरुद्ध केवल सबूत नष्ट करने का मामला ही चल पाएगा. लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं, जिनसे लगता है कि दुर्घटना की कहानी गढ़ी हुई है. ■ *(क्रमश:)*

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सरकारी तंत्र को जवाबदेह बनाना होगा

बाढ़, सूखा या बारिश के दिनों में सारे देश में होने वाले जल भराव को लेकर क्या कोई राजनीतिक सहमति नहीं बन सकती. हम जब उत्तर भारत के लोग किसी समस्या की बात करते हैं, तो उसे सारे देश की समस्या बताते हैं, जैसे मैं अपनी इस बातचीत में बता रहा हूं, पर हमारे उत्तर भारत के अखबारों में हम यह खबरें नहीं पढ़ते कि दक्षिण भारत के शहरों में भी जल भराव जैसी समस्याएं हैं.

बारिश क्या आई, देश के लिए आफत लेकर आ गई. हर शहर परेशान हो गया है. सिर्फ एक घंटे की बारिश और ट्रैफिक जाम. कई जगहों पर मैनहोल के अन्दर बच्चों के गिरने और मैनहोल में बह जाने कारण मौत की खबरें दिल को दहला गईं. यह पिछले 65 सालों से हो रहा है. तीन महीने बारिश का मौसम उत्तर भारत के सभी शहरों के लिए प्रलय जैसा मौसम बन जाता है. यह हर साल होता है. तीन महीने बीतते ही पुराने दुखों को लोग भूल जाते हैं और आने वाले दुखों के लिए अपने आपको तैयार करने लगते हैं. शोर-शराबा होता है, लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर या जिन संस्थाओं के ऊपर पानी निकासी की व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मा है, वे लोग बिल्कुल भी नहीं चेतते हैं.

इसी तरह हर साल बाढ़ आती है, हर साल सूखा पड़ता है, हर साल सर्दी से लोगों की मौतें होती हैं. ये सारी विपदायें प्रति वर्ष का निश्चित कैलेंडर बन गई हैं, पर न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार, न कोई राजनीतिक दल इस पूरी स्थिति का सामना करने के लिए अपने को तैयार करता है. होता दरअसल, बिल्कुल उल्टा है. पहले से यह तय हो जाता है कि इस बार बाढ़ में कितने पैसे का बजट देना है और उसमें से कितना पैसा लोगों की जेब में पहुंच जाना है. कितना पैसा सूखा राहत में जाना है. कितना पैसा जानवरों के चारे में जाना है. उस पैसे का किस विभाग के जरिए बंटवारा होगा इसका एक निश्चित नक्शा बना हुआ है और प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में जल भराव, सड़कों का टूटना और मैनहोल की सफाई के नाम पर पिछले साल से ज्यादा पैसा अगले साल लेने की योजना पहले से बन जाती है और उस पैसे में भी बंदरबांट हो जाती है. लोग वहीं के वहीं खड़े दिखाई देते हैं.

क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर सख्त कदम नहीं उठा सकते कि जिन संस्थाओं के ऊपर इनका हल निकालने की जिम्मेदारी है, अगर वो संस्थाएं हल नहीं निकालती हैं, तो उन संस्थाओं के मुखिया की जिम्मेदारी तय कर उनके लिए किसी सज़ा का प्रावधान किया जाए. कुछ लोग कह सकते हैं कि यह अलोकतंत्रिक बात है. मैं कहता हूं यह अलोकतंत्रिक नहीं, पूर्ण लोकतांत्रिक बात है. जब देश के लोग एक अच्छी व्यवस्था बनाने और चलाने के लिए सरकार चुनते हैं, तो पूरे विश्वास से चुनते हैं और उनका यह मौलिक अधिकार है कि उन्हें उन सुविधाओं का भरपूर फायदा मिले और उन समस्याओं से छुटकारा मिले, जो समस्याएं प्रतिवर्ष उन्हें तथाकथित दैवीय आपदा के रूप में मिलती हैं, क्योंकि आजकल एक बड़ा समुदाय यह कहने लगा है कि बाढ़, सूखा, ज्यादा बारिश का होना यह दैवीय है, नहीं, यह दैवीय नहीं है. मानवीय लालच के ये बड़े-बड़े उदाहरण हैं, जो योजना बनाकर किस तरह पैसे को खाना है और कितना पैसा राजनीतिज्ञों की जेब में जाएगा, कितना पैसा ब्यूरोक्रेट्स की जेब में जाएगा और कितना पैसा छोटे कर्मचारियों की जेब में जाएगा, यह सब गणित के हिसाब से तय होता है और उसके ऊपर ईमानदारी से अमल होता है. बस ठगे से रह जाते हैं वो लोग, जो लोग वोट देते हैं, जो लोग इन समस्याओं से छुटकारा पाने की आशा में सरकार का मुंह देखते हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बेपरवाह अपने भीतर फैले इस महाजाल को बजाए रोकने के बढ़ाती जा रही है.

क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर सख्त कदम नहीं उठा सकते कि जिन संस्थाओं के ऊपर इनका हल निकालने की जिम्मेदारी है, अगर वो संस्थाएं हल नहीं निकालती हैं, तो उन संस्थाओं के मुखिया की जिम्मेदारी तय कर उनके लिए किसी सज़ा का प्रावधान किया जाए. कुछ लोग कह सकते हैं कि यह अलोकतंत्रिक बात है. मैं कहता हूं यह अलोकतंत्रिक नहीं, पूर्ण लोकतांत्रिक बात है.

बाढ़, सूखा या बारिश के दिनों में सारे देश में होने वाले जल भराव को लेकर क्या कोई राजनीतिक सहमति नहीं बन सकती. हम जब उत्तर भारत के लोग किसी समस्या की बात करते हैं, तो उसे सारे देश की समस्या बताते हैं, जैसे मैं अपनी इस बातचीत में बता रहा हूं, पर हमारे उत्तर भारत के अखबारों में हम यह खबरें नहीं पढ़ते कि दक्षिण भारत के शहरों में भी जल भराव जैसी समस्याएं हैं. हम यह भी नहीं पढ़ते कि दक्षिण भारत में किस तरह सूखा पड़ता है, किस तरह वहां बाढ़ का मुक़ाबला होता है, बल्कि जब कभी वहां चक्रवात, तूफान, समुद्री तटों के ऊपर विनाश जैसी खबरें आती हैं, तो हमें यह देखकर हर्ष होता है कि वहां का प्रशासन उनका मुक़ाबला बहुत मुस्तैदी से करता है.

वैसा मुक़ाबला उत्तर भारत में क्यों नहीं हो सकता, क्यों उत्तर भारत में आमतौर पर यह राय बनी है कि दक्षिण भारतीय अधिकारी ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं? क्या उत्तर भारत में भ्रष्टाचार के साथ अक्षमता का भी रोग है? क्या हिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी उत्तर भारतीय प्रदेशों के लोग इस कलंक के साथ अपना जीवन गुजारने में गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो अक्षम हैं, भ्रष्टाचारी हैं? क्यों आमतौर पर उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारतीय अधिकारियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं? उन्हें ज्यादा क्षमतावान मानते हैं. यह सवाल हैं और यह सवाल एप्रोच के हैं, यह सवाल नजरिए के हैं, यह सवाल कार्यक्षमता के हैं, यह सवाल कार्य कुशलता के हैं.

सवाल शायद दक्षिण या उत्तर का नहीं है, सवाल पूरी सरकार की एप्रोच का है. दक्षिण में सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं. उत्तर में शायद लोगों के प्रति कम संवेदनशील होती हैं. पर समस्या तो है और इस समस्या का निदान अगर फौरन नहीं तलाशा गया, तो हम यह मान लेंगे कि जैसे होली, दिवाली, ईद-बकरीद आती है, उसी तरह से बाढ़, सूखा, बारिश के दिनों में जल भराव जैसी समस्याएं सालाना राष्ट्रीय त्यौहारों में होती दिखाई देने लगेंगी. हम सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं कि लोगों को उस क्षमता तक निराश मत कीजिए कि वो अपने को इतना नि:सहाय मानने लगें कि देश में व्याप्त बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बीमारी जैसी समस्याओं के साथ बाढ़, सूखा में होने वाली लूट और नागरिक सुविधाओं के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की अमानवीयता, असंवेदनशीलता लोगों को अपना भाग्य लगने लगे. ■

editor@chauthiduniya.com

ललित मोदी प्रकरण

राई का पहाड़ बनाने की कोशिश

दरअसल, इनमें से कोई भी मामला असल मुद्दे से संबंधित नहीं था. असल मुद्दा यह था कि ब्रिटेन द्वारा ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज़ दिए जाने पर भारत के आपत्ति न जताने से कहीं हितों का टकराव तो नहीं था? भारत के पास दूसरा विकल्प यह था कि वह ब्रिटेन से कहता कि ललित मोदी को यात्रा की अनुमति न दी जाए. अगर ललित मोदी का अपनी पत्नी के इलाज के लिए उनके साथ पुर्तगाल जाना ज़रूरी था, जो पहली नज़र में सही प्रतीत होता है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा यात्रा की अनुमति न दिया जाना एक कठोर निर्णय होता.

मेघनाद देसाई

हेराल्ड मैकमिलन 1950 के दशक के आख़िरी दिनों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे. किसी ने उनसे पूछा कि उन्हें किस बात से सबसे अधिक डर लगता है, विपक्ष से या अपनी ही पार्टी के लोगों से? उनका जवाब था, कार्यक्रम प्यारे, कार्यक्रम! 21 जून के योग दिवस के एक हफ्ते पहले की घटनाओं को देखर नरेंद्र मोदी भी मैकमिलन के उस वाक्य को दोहरा रहे होंगे. जो कार्यक्रम एक मामूली घटनाक्रम बनकर रह गया होता, उसने महाभारत जैसा विशालकाय रूप ले लिया. इससे यह भी पता चलता है कि आप कैबिनेट की ख़बरों पर नियंत्रण करके मीडिया को चटखारे लेने से रोक तो सकते हैं, लेकिन एक भूमंडलीकृत दुनिया में आपको पता नहीं चलता कि कौन-सी ख़बर कहां से बाहर निकल आए. राष्ट्रमंडल खेल घोटाला उस वक्त उजागर हुआ था, जब ब्रिटिश आयकर अधिकारियों ने लंदन की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसने मशाल हस्तांतरण का कार्यक्रम आयोजित किया था, के वैट भुनाने (रिक्लेम) पर सवाल उठाए थे. अगर हम केवल भारतीय मीडिया पर भरोसा करते, तो यह घोटाला कभी उजागर नहीं होता.

दि संडे टाइम्स ऐसा अख़बार है, जो ब्रिटेन में सांसदों के संभावित दुराचरणों की खोज में लगा रहता है. हालिया दिनों में अख़बार ने कीथ वाज़ से संबंधित एक घपला उजागर किया था. हालांकि, इस घपले का कोई प्रत्यक्ष भारतीय संबंध नहीं था. इस मामले में सवाल यह था कि क्या यहां वाज़ के हितों का टकराव (कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) था, क्योंकि उन्होंने यूके बॉर्डर एजेंसी के दफ्तर से गृह मंत्रालय की चयन समिति के अध्यक्ष की हैसियत से एक यात्रा दस्तावेज़ हासिल करने की कोशिश की थी. लोक आचरण के संसदीय आयुक्त अब इस मामले की जांच करेंगे.

अब इस मामले को और तूल देना उचित नहीं है. लेकिन, इस बीच भारतीय मीडिया द्वारा दि संडे टाइम्स की इस छोटी-सी ख़बर पर राई का पहाड़ बनाया जा रहा है. कारण यह है कि वाज़ ने जिस व्यक्ति की ख़ातिर यात्रा दस्तावेज़ हासिल करने के लिए हस्तक्षेप किया था, उसका नाम ललित मोदी था. ललित मोदी का पासपोर्ट ज़ब्त है. वह लंदन निर्वासन में एक सुखी जीवन बिता रहे हैं. ब्रिटेन से कहीं जाने के लिए उन्हें यात्रा दस्तावेज़ की ज़रूरत थी. यह ऐसा दस्तावेज़ है, जो ब्रिटेन में रह रहे देशविहीन लोगों को यहां से आने-जाने के लिए जारी किया जाता है.

वाज़ मोदी को यह दस्तावेज़ दिलवाने की वकालत कर रहे थे. उनका कहना था कि मोदी को पुर्तगाल जाकर उनकी पत्नी का कैंसर का चेकअप कराना था. इस पूरे प्रकरण में सुषमा स्वराज की जो भूमिका थी, वह यह थी कि उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटेन मोदी को यात्रा दस्तावेज़ दे देता है, तो भारत को कोई ऐतराज़ नहीं होगा. यह कहा गया कि उन्होंने सर जेम्स बेवन को फोन करके यह बात बताई. यह सीधे तौर पर अनुकंपा के आधार पर लिया गया एक फ़ैसला था. इसका फ़ैसला ब्रिटेन को लेना था. इसमें भारत की भूमिका केवल इतनी थी कि उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी. लेकिन अफ़सोस, भारतीय राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं होता, खास तौर पर तब, जबकि संसद का नया सत्र सामने हो. इस मामले पर हर कोण से नज़र डाली गई. सुषमा स्वराज के पति, उनकी पुत्री और उनके भतीजे के मोदी से रिश्ते की बात कही गई. ललित मोदी के ल्बिज़ा (पुर्तगाल) में पार्टी करने की बात कही गई. ललित मोदी की नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अमित शाह एवं दूसरे लोगों के साथ तस्वीरें आम की गईं.

वाज़ मोदी को यह दस्तावेज़ दिलवाने की वकालत कर रहे थे. उनका कहना था कि मोदी को पुर्तगाल जाकर उनकी पत्नी का कैंसर का चेकअप कराना था. इस पूरे प्रकरण में सुषमा स्वराज की जो भूमिका थी, वह यह थी कि उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटेन मोदी को यात्रा दस्तावेज़ दे देता है, तो भारत को कोई ऐ-तराज़ नहीं होगा. यह कहा गया कि उन्होंने सर जेम्स बेवन को फोन करके यह बात बताई. यह सीधे तौर पर अनुकंपा के आधार पर लिया गया एक फ़ैसला था. इसका फ़ैसला ब्रिटेन को लेना था. इसमें भारत की भूमिका केवल इतनी थी कि उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी. लेकिन अफ़सोस, भारतीय राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं होता, खास तौर पर तब, जबकि संसद का नया सत्र सामने हो.

दरअसल, इनमें से कोई भी मामला असल मुद्दे से संबंधित नहीं था. असल मुद्दा यह था कि ब्रिटेन द्वारा ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज़ दिए जाने पर भारत के आपत्ति न जताने से कहीं हितों का टकराव तो नहीं था? भारत के पास दूसरा विकल्प यह था कि वह ब्रिटेन से कहता कि ललित मोदी को यात्रा की अनुमति न दी जाए. अगर ललित मोदी का अपनी पत्नी के इलाज के लिए उनके साथ पुर्तगाल जाना ज़रूरी था, जो पहली नज़र में सही प्रतीत होता है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा यात्रा की अनुमति न दिया जाना एक कठोर निर्णय होता. इसके लिए वाज़ को अपने कैबिनेट के साथियों से बातचीत करनी पड़ती. भारत में प्रशासनिक स्तर पर जो कमी है, वह यह है कि यहां मंत्रियों के आपसी हितों के टकराव की जांच के लिए कोई प्रणाली नहीं है. इस कमी को दूर करने की ज़रूरत है. प्रधानमंत्री के पास एक सुनहरा मौक़ा है कि वह सुशासन के लिए एक ऐसी प्रणाली स्थापित करें. कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया, शायद मोदी इसके लिए कुछ करें. ■

feedback@chauthiduniya.com

हैरत की बात है कि पेड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही से संबंधित दोनों महकमे, वन विभाग और सिंचाई विभाग, एक–दूसरे पर दोषारोपण कर जिम्मेदारी थोपने में संलग्न हैं. ग्लोबल वॉर्मिंग से पृथ्वी को बचाने के लिए वैसे तो देश भर में पौधारोपण व हरे पेड़ों को बचाने के लिए सरकार जोर–शोर से प्रयासरत है और इस पर करोडों रुपये पानी की तरह बरबाद किये जा रहे हैं लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी समुचित देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था दुरुस्त न होने से देश भर में पेड़ों के तस्कर न सिर्फ करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि पहुंचाते हैं बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के कई प्रयासों को धक्का पहुंचा रहे हैं.

डॉक्टरों को क्यों करनी पड़ती है हड़ताल

मोनिशा भटनागर

दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने जून को एक बार फिर हड़ताल करने का फैसला किया. लगभग हजार सीनियर और जूनियर रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने हड़ताल फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन ऑफ दिल्ली (एफओआरडीए) की पहल पर यह हड़ताल करने का फैसला लिया. एफओआरडीए के प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया था कि सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, आरएमएल, एलएनजेपी, जीबी पंत, डीडीयू, जीटीबी सहित राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले सीनियर और जूनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर 22 जून से हड़ताल पर रहेंगे. डॉक्टरों ने साथ ही यह भी साफ़ किया था

डॉक्टरों ने अपनी असुरक्षा का मसला तो उठाया ही साथ ही जी-वनरक्षक दवाओं, जांच और इलाज केलिए जरूरी तमाम उपकरणों व कॉटन पट्टी का अभाव झेल रहे अस्पतालों की हालत को भी सामने रखा. सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों, डाक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों की संख्या भी जरूरत से काफी कम है. यही नहीं समय पर वेतन, खाने की समुचित व्यवस्था और यहां तक की पीने केपानी की उपलधता तक केलिए डॉक्टरों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है.

दिल्ली देश की राजधानी है. देश की राजधानी में अगर अस्पतालों की हालत इतनी ष्ठ राब है कि वहां के डॉक्टरों को अस्पताल की सेहत सुधारने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाना पड़े, तो देश के बाकि राज्यों में हालत क्या होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है. इस हड़ताल ने एक बार फिर अस्पतालों की बदतर हालत सबके सामने ले आई. स्वास्थ्य व्यवस्था की बुरी अवस्था किसी से छिपी नहीं है, न प्रशासन से न राजनेताओं से लेकिन इसमें सुधार के लिए कोई आगे कदम बढ़ता हुआ नहीं दिखता. ■

कि वह हड़ताल करना नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन का उनकी परेशानियों की तरफ ध्यान दिलाने केलिए मजबूरी में यह फैसला लिया गया. शुरुआत में एफओआरडीए द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात की गई थी लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा डॉक्टरों की सारी मांगे मान लिए जाने और आवश्यक सेवा प्रतिरक्षण अधिनियम (एस्मा) लगाये जाने पर 2 दिन में ही हड़ताल समाप्त कर दी गई.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के कारण मरीजों को काफी अधिक परेशानी उठानी पड़ती है लेकिन डॉक्टरों को हो रही परेशानियों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. एक साल में दूसरी बार इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टरों की हड़ताल का कारण कई सवाल उठती है. हड़ताल कर रहे इन डॉक्टरों का कहना था कि प्रशासन की गलती की वजह से उन्हें मार खानी पड़ती है. डॉक्टरों द्वारा की गयी मांगों में सबसे प्रमुख मांग सुरक्षा की है. मरीजों के नाराज़ परिजन अपना गुस्सा डॉक्टरों पर ही उतारते हैं. मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में कमी की वजह से उन्हें हो रही परेशानी का गुस्सा भी डॉक्टरों को ही भुगतना पड़ता है. डॉक्टरों का कहना था कि साल के शुरू में हड़ताल ष्ठ त्म करने केबाद भी उन्होंने यह मांगें उठाई थीं लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली के सीएम, लेफ्टिनेंट गवर्नर, हेल्थ मिनिस्टर को पत्र लिखने केबावजूद भी किसी ने इस मामले में पहल नहीं की, और इसलिये ही वो दोबारा हड़ताल करने पर मजबूर हो गए. हालांकि इस बार 22 जून को ही दिल्ली केमुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांगों को जायज़ ठहराते हुए समस्या को सुलझाने की बात कही. डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली के अस्पतालों में सुविधाओं की भारी कमी है. मरीजों की समय पर जांच नहीं हो पा रही है, उन्हें दवा नहीं मिल रही है, इमरजेंसी में इलाज की पूरी सुविधा नहीं मिल रही है. सर्जरी केलिए महीनों तक इंतजार के लिए कहा जाता है और जब उन्हें सुविधा में कमी मिलती है तो उनका गुस्सा हम पर निकलता है. यह सारी प्रशासनिक समस्याएं हैं लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कमी चाहे किसी की भी हो मरीजों की नाराज़गी केवल डॉक्टरों को ही सहनी पड़ती है. यह सही है की आमतौर पर प्रशासन की कमी की वजह से मरीज समझते हैं कि डॉक्टर की कमी से उन्हें ज्यादा परेशानी हो रही है और इसलिए ही उनकी नाराज़गी, जो कई बार हिंसा में बदल जाती है, डॉक्टरों को झेलनी पड़ती है. कई ऐसे मामलें हैं जिनमे मरीजों या उनके परिजनों ने डॉक्टरों पर हमला बोला हो. ऐसे में उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी प्रशासन की है ताकि वह लोगों की जान बचाने का अपना काम पूरी निष्ठा से कर सकें. मरीजों का सीधा रिश्ता डॉक्टरों से है प्रशासन से नहीं लेकिन यह प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि वे डॉक्टरों की सुरक्षा और मरीजों की सुविधा का पूरा ख्याल रखे.

डॉक्टरों ने अपनी असुरक्षा का मसला तो उठाया ही साथ ही जीवनरक्षक दवाओं, जांच और इलाज केलिए जरूरी तमाम उपकरणों व कॉटन पट्टी का अभाव झेल रहे अस्पतालों की हालत को भी सामने रखा. सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों, डाक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों की संख्या भी जरूरत से काफी कम है. यही नहीं समय पर वेतन, खाने की समुचित व्यवस्था और यहां तक की पीने के पानी की उपलधता तक के लिए डॉक्टरों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है. दिल्ली देश की राजधानी है. देश की राजधानी में अगर अस्पतालों की हालत इतनी ष्ठ राब है कि वहां के डॉक्टरों को अस्पताल की सेहत सुधारने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाना पड़े, तो देश के बाकि राज्यों में हालत क्या होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है. इस हड़ताल ने एक बार फिर अस्पतालों की बदतर हालत सबके सामने ले आई. स्वास्थ्य व्यवस्था की बुरी अवस्था किसी से छिपी नहीं है, न प्रशासन से न राजनेताओं से लेकिन इसमें सुधार के लिए कोई आगे कदम बढ़ता हुआ नहीं दिखता. ■

feedback@chauthiduniya.com

पेड़ों की तस्करी का ज़िम्मेदार कौन

राणा अवधूत कुमार

आम तौर पर पर्यावरण को हरा–भरा रखने के साथ ही वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा पेड़–पौधे लगाये जाते हैं. वहीं नहरों की कटाई रोकने के लिए भी वृक्षारोपण किया जाता है, जिसके लिए वन विभाग बाकायदा वैसी नहरों को चिन्हित कर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करती है. लेकिन सरकार व स्थानीय प्रशासन की ला–परवाही व अनदेखी से आये दिन लकड़ियों के तस्कर अपनी कार–गुज़ारियों से न सिर्फ करोड़ों के हरे पेड़ काट लेते हैं बल्कि सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने के साथ ही नहरों को असुरक्षित करने और कीमती लकड़ियों की कालाबाज़ारी भी करते हैं. इस पर प्रशासन की खामोशी पूरे मामले को और पेचीदा बना देती है.

हैरत की बात है कि पेड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही से संबंधित दोनों महकमे, वन विभाग और सिंचाई विभाग, एक–दूसरे पर दोषारोपण कर जिम्मेदारी थोपने में संलग्न हैं. ग्लोबल वॉर्मिंग से पृथ्वी को बचाने के लिए वैसे तो देश भर में पौधारोपण व हरे पेड़ों को बचाने के लिए सरकार जोर–शोर से प्रयासरत है और इस पर करोडों रुपये पानी की तरह बरबाद किये जा रहे हैं लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी समुचित देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था दुरुस्त न होने से देश भर में पेड़ों के तस्कर न सिर्फ करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि पहुंचाते हैं बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के कई प्रयासों को धक्का पहुंचा रहे हैं. इस स्थिति में सवाल उठता है कि पेड़ों की देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?

क्या है पूरा मामला

वैसे तो हरे पेड़–पौधों को काटने का गिरोह पूरे देश और बिहार के सभी जिलों में सक्रिय है. ऐसा एक मामला रोहतास जिले में भी सामने आया है. वहां पिछले कई वर्षों में सुनियोजित तरीके से वन तस्कर न सिर्फ करोड़ों रुपये के किमती पेड़ों को काट दिया गया बल्कि नहरों पर कटाव का एक बड़ा खतरा भी उत्पन्न हो गया है. गौरतलब है कि करीब दो दशक पूर्व वित्तीय वर्ष 1993–94 में सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल अंतर्गत कोनकी गांव एवं दरिगांव नहर तट पर रैखिक वनरोपण कार्यक्रम में जवाहर रोजगार योजना के तहत वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया. उस समय वन विभाग ने कुल 42880 शीशम व अन्य इसी तरह की प्रजातियों के पेड़–पौधे लगाये थे. इनकी देखभाल के लिए वन विभागीय कर्मी के रूप में लाल बिहारी राम वनपाल और गणेश पांडेय को वनरक्षी के तैनात किया गया. लेकिन वन विभाग का आंकड़ा ही कहता है कि मौजूदा समय में महज 5000 के आसपास ही पेड़ बच पाये हैं. जबकि सही संख्या क्या है यह नहरों की स्थिति देखकर ही पता चल जाता है कि वहां हकीकत में अब पेड़ों की संख्या हजार भी नहीं है.

आरटीआई से हुआ खुलासा

हरे पेड़ों को काटने और तस्करी करने में एक पूरा गिरोह पिछले कई वर्षों से लगा हुआ है. एक समय इन पेड़ों से पूरा वातावरण हरा–भरा हो गया था. पिछले सात वर्षों से हरे पेड़ों की अनवरत कटाई होने से नहर टूटने की आशंका काफी बढ़ गयी है. जिससे नहर के दक्षिणी हिस्से के जलमग्न होने की आशंका भी बढ़ गयी है. इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाने वाले मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष व आरटीआई कार्यकर्ता शीतला प्रसाद तिवारी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से हरे पेड़ों की अवैध कटाई पर न तो वन विभाग का ध्यान था और न सिंचाई विभाग का जबकि इस संबंध में दोनों विभागों के कई वरीय अधिकारियों को सूचना दी गयी. पेड़ों की मौजूदा संख्या और सुरक्षा समेत तमाम जानकारी सूचना के अधिकार से ही प्राप्त हुआ. जबकि 2012 में ही जन शिकायत प्रकोष्ठ में हरे पेड़ों को काटने का मामला पहुंचा तो तत्कालीन डीएफओ एस चंद्रशेखर ने इस पर त्वरित करते हुए छापेमारी कर 18 इंच–24 इंच गोलाई के 11 शीशम के पेड़ बरामद किये थे. तब सक्षम न्यायालय में वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज भी किया गया था लेकिन बाद में कार्रवाई के नाम पर कोई खास

सफलता विभाग को नहीं मिली. जहां कार्रवाई की प्रक्रिया आज भी महज़ फाइलों में सिमट कर रह गयी है. जिस पर किसी का ध्यान नहीं है.

जिम्मेदारी लेने से बच रहे दोनों विभाग

नहरों के किनारे लगे पेड़ों को बचाने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है, यह भी एक अहम सवाल बना हुआ है.क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना से यह खुलासा हुआ कि नहरों के किनारे पर लगाये गये पेड़ भगवान भरोसे ही हैं. कारण कि पिछले कुछ वर्षों से पेड़ों की सही संख्या और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी के बारे में पूछा गया तो चकित करने वाली जानकारी मिली. दोनों विभाग एक–दूसरे पर पेड़ों की सुरक्षा की बात थोपते हैं. नियम कहता है कि वृक्ष रोपने से लेकर अगले तीन वर्षों तक वन विभाग को इसकी देख–रेख करनी होती है. इसके बाद जहां पेड़ लगाये जाते हैं, देख–रेख इनकी जिम्मेदारी हो जाती है. लेकिन यहां दोनों विभाग एक–दूसरे पर दोषारोपण करने में जुटे हैं. अब जिम्मेदारी चाहे जिसकी भी हो लेकिन इस बीच करीब 35000 पेड़ तस्कर चुरा ले गये. विभागीय सूत्र बताते हैं कि इन पेड़ों की बाजार कीमत 25 करोड़ से अधिक है. तो आखिर करोड़ों के पेड़ों की चोरी में कहीं यहां की स्थानीय पुलिस भी संलिप्त तो नहीं. वैसे भी इस नहर से जुड़े बड्डी थाना महज दो किलोमीटर पर स्थित है जहां थाने में अक्सर जंगल की लकड़ियां दिखायी देती है.

मामले से जुडे लोगों की प्रतिक्रिया

नहर चाटों में पेड़–पौधों को लगाने व सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग की होती है. पेड़ गिरने पर विभाग को खबर कर दी जाती है.पेड़ों की सुरक्षा के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है.

– अरुण कुमार, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग.

क्षेत्र के ऊपर है कि वह वन विभाग का सुरक्षित अधिसूचित है कि नहीं. यदि दूसरे विभाग की भूमि पर वन विभाग पौधारोपण करता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी इस पर नहीं है.

– एसके सिंह, आरसीसीएफ, वन विभाग, पटना.

पेड़ों की तस्करी में पास के कैमूर जिला सहित बाहरी तस्कर भी संलग्न हैं. इसकी सूचना वन विभाग, सिंचाई विभाग और मुख्यमंत्री जनता दरबार तक की गयी, सरकार एवं अधिकारियों की लापरवाही से करोड़ों के हरे पेड़ों को तस्कर चुरा ले गये.

– शीतला प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष, मानवाधिकार प्रतिष्ठान.

नहरों–चाटों में लगे पेड़ों की सुरक्षा वन विभाग एवं सिंचाई विभाग दोनों को करनी है. इस इलाके में पेड़ों की कटाई के मामले पहले भी आये थे, मैंने स्वयं छापेमारी कर पेड़ बरामद किया था. सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में दोनों विभागों को उनकी देखभाल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

अफगानिस्तान में लोकतंत्र पर हमला

अफगानिस्तान के संसद पर आतंकी हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. काबुल में इतने अहम स्थान पर हुए इस हमले ने नाटो की मदद के बिना तालिबान के खिलाफ अफगान सुरक्षा बलों की लड़ाई के बीच यहां की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सवाल खड़ा कर दिए हैं. सवाल अफगानिस्तान की अंदरुनी राजनीति से उपजे विवादों पर भी उठ रहे हैं. सवाल यह भी हैं कि क्या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की पाकिस्तान से करीबी और पाकिस्तान के कहने पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी आतंकवादियों पर की गई कार्रवाइयों के बदले के रूप में तालिबान द्वारा यह हमला किया गया? कारण चाहे जो भी हों, लेकिन आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो प्रतिबद्धता से संपूर्ण विश्व को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी.

राजीव रंजन

आतंकवाद और आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता. रमजान के इस पवित्र महीने में आतंकवादियों ने इस बात को साबित भी कर दिया है. सिर्फ 26 जून को ही आतंकवादियों ने तीन देशों फ्रांस, कुवैत में एक शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त और ट्यूनीशिया में समुद्र तट पर हमले कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया. यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान के मुताबिक, जनवरी से जून 2015 तक पूरे अफगानिस्तान में आतंकी हमलों में 3237 और अकेले काबुल में 1174 लोग मारे गए. इन आंकड़ों से अफगानिस्तान में आतंकवाद की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि अफगानिस्तान ही नहीं, पूरा विश्व आतंकवाद की गिरफ्त में है.

संसद पर हमले को लेकर अफगानिस्तान ने कहा है कि इस हमले में पाकिस्तान के एक खुफिया अधिकारी ने तालिबान की मदद की थी. अफगान संसद पर हुए हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है. सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पिछले महीने 25 मई को अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों और तालिबानी नेताओं के बीच चीन में एक बेहद गोपनीय वार्ता हुई थी. इस बात की जानकारी चीन के ही कुछ खुफिया अधिकारियों ने आईएसआई को दे दी. पाकिस्तान को लगता है कि कहीं अफगानिस्तान में उसकी भूमिका कम न हो जाए या अफगान सरकार भारत और अमेरिका के ज्यादा करीब न चली जाए, इसीलिए तालिबान के एक खास धड़े से यह हमला कराया गया है. चीन में हुई उस बातचीत में अफगान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद मासूम स्तानिकजेई ने किया, जो कि पिछले सप्ताह तक देश की शांति वार्ता संस्था हाई पीस काउंसिल के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे. उनके अलावा पूर्व सांसद सत्ता में साझेदार अब्दुल्ला अब्दुल्ला के सहयोगी मोहम्मद असीम ने भी इस बैठक में शिरकत की. तालिबान की ओर से तीन वरिष्ठ नेता मुल्ला अब्दुल जलील, मुल्ला मोहम्मद हसन रहमानी और मुल्ला अब्दुल रज्जाक बैठक में शामिल हुए. खास बात यह है कि ये तीनों पाकिस्तान में ही रहते हैं और तालिबान के क्वेटा स्थित नेतृत्व परिषद के करीबी हैं.

हालांकि पाकिस्तान ने इस आरोप को गलत बताया है. आरोप सही हों या नहीं, इस पर फर्क तभी पड़ता है, जब तक विश्व के देश आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएं. अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर इस हमले का आरोप लगा रहा है, तो इस पर आसानी से विश्वास भी हो जाता है, क्योंकि दुनिया में यह बात आम है कि पाकिस्तान विश्व आतंकवाद की नर्सरी है और यह कलंक पाकिस्तान के दामन पर बहुत पहले से ही लगती आ रही है. अब तो इस बात पर भी मुहर लग गई है कि पाकिस्तान की सरकार और अदालतें भी आतंकवादियों की रक्षा करती हैं. लश्करे-तइबा के सरगना और मुंबई बम कांड का साजिशकर्ता ज़कीउररहमान लखवी को संयुक्त राष्ट्र ने दोषी करार दिया है और 15 में से 14 राष्ट्र दंडित करना चाहते हैं, उसे पाकिस्तान द्वारा रिहा करने और सारी सुविधाएं देने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि लखवी को पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करना चाहता है और दूसरी तरफ वह इसलिए भी लखवी को इतनी तवज्जो दे रहा है कि लखवी की गतिविधियां भारत विरोधी थीं. इसका क्या मतलब समझा जाए कि पाकिस्तान सिर्फ उसी आतंकवाद का विरोधी है, जो उसके खिलाफ है, उसका विरोधी नहीं है, जो भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ है?

अफगानिस्तान में संसद पर हमले के कारण के रूप में यह बात भी सामने आ रही है कि अफगाानिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी और पाकिस्तान सरकार के बीच हाल के महीनों में कई समझौते हुए हैं. अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख के विरोध के बावजूद अफगानिस्तान ने आईएसआई से समझौते किए. पाकिस्तान के कहने पर अफगानिस्तान में छिपे पाकिस्तानी आंतकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई. इसी के जवाब में तालिबान वहां हमले कर रहा है. अफगानिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है कि वहां की सरकार को इस बात का भरोसा है कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान से निपटा जा सकता है. यहां अगर गनी सरकार पाकिस्तान की बजाय भारत के साथ सुरक्षा नीतियां बनाती तो परिणाम बेहतर होते. गनी सरकार की इस नीति से ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका देश ही प्रभावित होगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत भी काफी हद तक प्रभावित होगा. जिस तरह से काबुल में पहले भी भारतीय उच्चायोग पर हमले हो चुके हैं, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस हमले ने भारतीय उच्चायोग और हमारे दूसरे काउंसलेट की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. अफगानिस्तानी संसद सहित वहां के कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भारत सरकार के जरिए काम हो रहा है, अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों को भी इससे हानि हो सकती है. इसलिए अफगानिस्तान में अगर तालिबान की पकड़ मजबूत होती है तो भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा बढ़ेगा. दूसरी तरफ अफगानिस्तान में लंबी लड़ाई के बाद अब अमेरिका और नाटो के देश अपनी अधिकतर सेना को वापस बुला चुके हैं. अमेरिकी सेना के जाते ही तालिबान अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में धीरे-धीरे पकड़ मजबूत कर रहा है. वहीं, काबुल में बड़े हमलों की साजिश रच रहा है. उत्तरी प्रांत कुंदुज के दो जिलों चारदारा और दश्त-ए-अर्ची पर अब अफगान तालिबान का कब्जा है. अमेरिका और नाटो देशों ने अफगान बलों को आतंकवाद विरोधी अभियानों की ट्रेनिंग देने के लिए 60 अरब डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों के पास अमेरिकी बलों जैसी काबिलियत और आधुनिक हथियार नहीं हैं.

आतंकवाद के मुद्दे पर चीन को अलग कर के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जिस पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के संसद पर हमले का आरोप लग रहा है, चीन उसे अपनी ढाल के रूप में तैयार कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र संघ की 15 सदस्यीय कमेटी मुंबई बम कांड के साजिशकर्ता लखवी की गिरफ्तारी चाहती थी, फिर भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते चीन ने अड़ंगा लगा दिया. चीन खुशफहमी में है कि वह जिस देश की सहायता कर रहा है, वह भी भारत विरोधी गतिविधियों में उसकी सहायता करता रहेगा, लेकिन वह भूल जा रहा है कि आतंकवाद और आतंकवादी किसी का सगा नहीं हो सकता. इसका ताजा उदाहरण है 26 जून को कुवैत में मस्जिद पर जुम्मे की नमाज के दौरान हमला. अफगानिस्तान के प्रमुख मौलवियों ने भी तालिबानी आतंकवादियों से आग्रह किया था कि वे रमजान के महीने में हमले न करें, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी, क्योंकि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता. अभी एक सप्ताह पहले ही चीन के शहर काशगर में 18 लोग मारे गए हैं. अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन को कुछ इसी तरह से फलने-फूलने का मौका दिया था, जो बाद में उसके लिए नासूर बन गया. क्या अफगानिस्तान जैसे आतंकवाद पीड़ित देश के लोग, जिसके दिल पर आतंकवादियों ने हमला किया है, क्या चीन के बारे में अच्छी राय बनाएंगे? चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन-यात्रा के दौरान आतंकवाद के खिलाफ साझा मोर्चे की बात कही थी और यही बात उसने फरवरी में रूस, चीन, भारत संवाद में भी कही थी. अब चीन के बारे में बाकी दुनिया के देश क्या राय बनाएंगे?

एक विदेशी न्यूज एजेंसी के जर्नलिस्ट ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि हमले के पीछे अफगानिस्तान की अंदरूनी राजनीति हो सकती है, उसने कहा कि अफगानिस्तान में संसद ही सबसे सुरक्षित जगह है और वहां आत्मघाती धमाके के बाद भी घुसना असंभव है, लेकिन न सिर्फ हमलावर संसद परिसर में घुसे, बल्कि संसद भवन के भीतर भी एक आतंकी पहुंच गया. इस जर्नलिस्ट ने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब कोई बड़ा सुरक्षा अधिकारी या सांसद उसकी मदद करे. जर्नलिस्ट की बातों पर यकीन करना कोई अचरज वाली बात नहीं है, क्योंकि फिलहाल, अफगानिस्तान में उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है.

अफगानिस्तान की संसद पर हमले से साफ है कि वहां अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद अफगान-तालिबान बेअसर नहीं हुआ है. तालिबान अब अफगानिस्तान के अंदरूनी जिलों पर कब्जा कर रहा है. वह काबुल में हाई प्रोफाइल हमलों को अंजाम दे रहा है. पिछले दिनों काबुल एयरपोर्ट और राजधानी में एक गेस्ट हाउस पर हमला और उसके बाद अफगानिस्तान की संसद पर हमला कर आतंकवादियों ने सीधे-सीधे अफगानिस्तानी लोकतंत्र पर हमला किया है. अफगानिस्तान में हर दिन 10 हमले नाकाम किए जा रहे हैं. फिर भी काबुल में 6 महीने में एक हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. नाटो के जनरल जॉन कैंबेल के मुताबिक, सिर्फ मई में काबुल एयरपोर्ट सहित राजधानी के अंदर 6 बड़े हमले हुए. इनमें 19 नागरिकों सहित 100 लोगों की मौत हो गई. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, पूरे देश में आतंकी हमलों के कारण सुरक्षा बलों के जवानों की मौतों के आंकड़े में 75 फीसदी का इजाफा हुआ है. 2014 में 4634 अफगान जवान आतंकी हमलों में शहीद हुए थे.■

feedback@chauthiduniya.com

अफगानिस्तान में भारतीय कितने सुरक्षित

- काबुल में हाल के महीनों में ही कोलोला पुश्ता के पार्क पैलेस पर आतंकी हमले में 4 भारतियों की मौतें हुई थीं.
- हेलमंद प्रांत में तालिबान ने फादर अलेक्सिस प्रेमकुमार एंटनीसामी का अपहरण कर लिया था.
- 2014 में अफगानिस्तान में भारतीयों के खिलाफ 14 आतंकी वारदातें हुईं, जबकि 2013 में जलालाबाद स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले सहित 3 आतंकी घटनाएं हुई थीं.

भारत का तोहफा है अफगानिस्तान का संसद भवन

अफगान जनता को लोकतंत्र का तोहफा देने के लिए भारत ने काबुल में संसद भवन बनवाया है. भारत ने इसका निर्माण कार्य 2009 में शुरू किया था. संसद भवन में 4 हिस्से हैं-हाउस ऑफ पीपुल, ऑफिसर्स हाउस, एंट्रेंस लॉबी और 120 सदस्यों की क्षमता वाला सीनेट हॉल. इसके निर्माण की लागत 710 करोड़ रुपए आई थी, जिसमें करीब 350 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए थे. इसके निर्माण के लिए 150 विशेषज्ञ भारत से बुलाए गए थे.

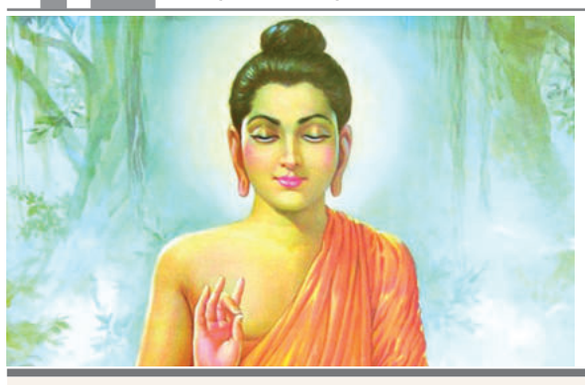

उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया. उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्यागकर तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया. बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा. उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया, और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी. मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गयी किसी गलती के बारे में सोच कर बार-बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं. हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नयी ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए.

सद्गुरु भक्तों के अर्न्तमन को जानते हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

गुरु-मुख होने की आवश्कता

संसार में जो अनेक तरह के बंधन हैं, मनुष्य उनमें क्यों फंसता है?

संसार के अनेक बंधनों में हम इसलिए फंसते हैं, क्योंकि हमारे मन में संसार के प्रति आकर्षण होता है. हम उस भावना के अनुरूप चलना चाहते हैं, जो मन के अनुकूल लगती है. जो कुछ भी मन के अुनकूल नहीं लगता, उससे हम क्षुब्ध हो जाते हैं. यदि हमने प्रतिकूलता में भी अपने को साध लिया, तो अनुकूल के बंधन में भी नहीं बधेंगे. जो प्रतिकूल या अनुकूल दोनों के बंधन में नहीं आते हैं, उनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं. मन अपने को सही ठहराने के लिए बेहया वृत्ति अपनाता है, किसी भी तरह से अपनी ओ खींचेगा. छोटी-छोटी चीजों में हम स्वयं फंसते हैं, अत: उनमें से स्वयं ही निकलना होगा. खुद ही निर्णय करना पड़ेगा कि हमको मन-मुख होना है या गुरु-मुख. इेकिन इतना निश्चित है कि-मन-मुख निकलकर जो होता है गुरु-मुख... ... ...संसार उसके लिए असार पर सार केवल गुरु ही हैं.

सामान्य जीवन में समय के बदलाव के कारण व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का कौन सा उपाय है?

साधारण और नित्य एक ही दिनचर्या सा जीवन जीने वाले लोगों के लिए केवल वर्तमान में नहीं बल्कि हर युग में कठिनाई रही है. साधारण जीवन व्यतीत करने का अर्थ है-सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सास्कृतिक रूप से पीढ़ियों की आध्यात्मिक परंपराओं को लेकर चलना और समय-प्रवाह में उनमें होने वाले परिवर्तनों के साथ अपने को ढालना. जो लोग अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों से अलग होकर केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही चलना चाहते हैं, उनके लिए यह मार्ग अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, सामान्य सांसारिक जीवन जीते हुए इस मार्ग पर चलने में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं. बहुत से सांसारिक भक्त इन समस्याओं से निदान के लिए गुरु भक्ति का मार्ग ढूढ़ रहे हैं. एक बार यदि कोई सच्चे अर्थ में गुरु-मुख होता है, तो उसके लिए सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी आध्यात्मवाद के मार्ग पर चलना आसान हो जाता है. ऐसी परिस्थिति में चेतना के विकास हेतु इस मार्ग में चलने के लिए भक्त की इच्छा-शक्ति, सद्गुरु की कृपा एवं दिव्य प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है. इस मार्ग पर चलने में शुरू-शुरू में कठिनाई महसूस हो सकती है. इसके लिए कई वर्षों की तैयारी की आवश्यकता होती है. अगर कोई भक्त गुरु की खोज में गुरु के जीवन चरित्र को पढ़े तथा उनका चिंतन करता रहे और धैये धारण करते हुए अपनी चारित्रिक शुद्धता बनाए रखता है, तो धीरे-धीरे सद्गुरु के दिव्य भाव उसके अन्त:करण को प्रभावित करेंगे. यदि विश्वास के साथ वह निरंतर ऐसा करता रहता है, तो एक विहित समय पर उसे गुरु अवश्य मिलेंगे. यह कहना और भी सटीक होगा कि यदि इस प्रकार गुरु की खोज में वह निरंतर लगा रहता है, तो वह गुरु का ध्यान अपनी ओर अवश्य आकर्षित कर लेगा, क्योंकि गुरु में सभी के अवगुणों एवं गुणों को पहचानने की दिव्य क्षमता है

और वे सभी भक्तों के अर्न्तमन को जानते हैं. इसीलिए यह कहा गया है कि शिष्य गुरु नहीं ढुढ़ते बल्कि गुरु ही शिष्य को अवश्य ढूंढ़ लेते हैं. जैसा कि बाबा ने कहा था.

मैं अपने भक्त को सात समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूंगा, जिस प्रकार कि एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी में बंधा हो खींच कर अपने पास लाया जाता है.

हमारे कठिनाइयों और परेशानियों से भरे जीवन में करुणा, क्षमा और नि:स्वार्थ-सेवा के गुण को विकसित करने के लिए बहुत साधना/प्रयत्न की आवश्यकता है. करुणा एवं नि:स्वार्थ सेवा सद्गुरु के लक्ष्य हैं. इसका र्म यह है कि दीन-दुखियों एवं अन्य प्राणियों की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करते हुए गुरु के आदेशों का पालन और उनकी शिक्षाओं के अनुसार आचरण करने से ही इस मार्ग पर चलने की शुरूआत करनी चाहिए. फिर धीरे-धीरे और कठिन प्रयास करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. जिंदगी की मुसीबतों को झेलते हुए अपनी कोशिशों से व्यक्ति अपने जीवन में जो भी गुण विकसित करता है, वे उसमें स्थायी रूप से घर कर लेते हैं और फिर वे गुण उसकी आत्मा का एक अंश बन जाते हैं. वही गुण उसके साथ जन्म-जन्मान्तर तक चलते हैं. आध्यात्मिक मार्ग में और विकसित होने के लिए वह अगले जन्मों में भी पुन: गुरु की सहायता प्राप्त करता है.

चेतना के विकास का संक्षिप्त मार्ग

हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं और वह अपने सीमित रूप में ही सब कुछ सोचने-समझने के लिए मजबूर है. उसे उसके सीमित दायरे से निकालने का सहज उपाय क्या है?

हर प्राणी की चेतना के विकास की अपनी एक ऐसी स्थिति होती है. सृष्टि के विकास की यही कहानी है. असंख्य योनियों को पाक करके वह मानव बना है. इसके लिए भी न जाने उसे कितने प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़ा है. उस की सोच समझ अपनी स्थिति के ही अनुरुप है. श्वान (कुत्ते) के समक्ष चाहे कितनी ही रंगीन रोशनी क्यों न हो उसमें रंग को पहचानने की क्षमता नहीं है. केवल सद्गुरु ही प्राणी को एक स्थिति से निकालकर चेतना की दूसरी स्थिति में ले जाने में सक्षम हैं. मनुष्य की सबसे बडी दुर्बलता यह है कि उसका मन अत्यंत चंचल है तथा तर्क-वितर्क-कुतर्क के कारण उसमें अस्थिरता बनी रहती है और वह अपने मूल लक्ष्यों से भटक जाता हैं. एक ही स्थिर बिंदु पर ध्यान केंद्रित रहे तो वहीं से संपूर्ण जगत दिखाई देगा, उसे इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है. दो बिंदोओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा केवल आवश्यकता नहीं है. दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा केवल ऋजु (सरल रेखा) है. वह सरल रेखा है- गुरू का अनुसरण करना ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

दिल्ली की लड़ाई

जब तोप मुकाबिल हो-दिल्ली की लड़ाई देश हित में नहीं है(22 जून -28 जून 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. संतोष भारतीय ने बिल्कुल सही कहा है कि दिल्ली की लड़ाई देश हित में नहीं है. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जो देश की राजधानी के लिए शुभ संकेत नहीं है. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाई में किसी का अगर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो वह दिल्ली की जनता का. अभी हाल ही में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के कारण दिल्ली के सड़कों पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी. सफाई कर्मचारी इसलिए हड़ताल पर थे, क्योंकि उनको कई महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी. ऐसे कई सारे ऐसे मामले हैं जिसे लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लड़ाई है. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को साथ बैठकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए.

-विकास कुमार, पालम, दिल्ली.

भाजपा का संकट

ललित मोदी मामले में भाजपा घिरती नजर आ रही है. ललित मोदी मामले में राजस्थान की मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला कर रही है. उधर पूर्व आईपीएल चीफ ललित मोदी ने ट्वीट कर सियासी तुफान खड़ा कर दिया. ललित मोदी ने अपने ट्वीट में अब राष्ट्रपति भवन की सेक्रेटरी का नाम लिया है. उनके एक के बाद एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का नाम है. उधर शिवसनेा ने भी इस मामले को लेकर भाजपा पर सवाल खड़ा किए हैं. आने वाले दिनों ललित मोदी मामला एक बड़ा मुसीबत खड़ा कर सकता है.

-रविशंकर सिंह, बक्सर, बिहार.

सरकार को संज्ञान लेना होगा

कांग्रेस ललित मोदी मामले को लेकर नेरन्द्र मोदी सरकार पर हमलावार थी ही कि उसे प्रधानमंत्री पर हमला करने का एक और हथियार मिल गया है. भाजपा की महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगा है. आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार में महिला व बाल विकास कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे ने सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए 24 कान्ट्रैक्ट को 24 घंटे में मंजूरी दे दी और उन्होंने यह कॉन्ट्रैक्ट अपने करीबियों को दिया है. भाजपा को अपने मंत्रियों और राज्य सरकारों को आदेश देना चाहिए कि हर कार्य में पारदर्शिता बरतें. पिछले दिनों ललित मोदी मामले और पंकजा मुंडे पर घोटाले के आरोप से भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा है. नरेन्द्र मोदी ने लोगों से वादा किया था कि न खाएंगे न खाने देंगे. अगर भाजपा के केन्द्र या राज्य सरकारों पर घोटाले का अगर आरोप लगता है, तो इससे सबसे ज्यादा नरेन्द्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचेगा. इसलिए सरकार को इन मामलों का संज्ञान लेना चाहिए.

-अरुण यादव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

एनडीए को मिलेगी कड़ी चुनौती

कवर स्टोरी-बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद, लालू-नीतीश का तूफानी कदम(22 जून -28 जून 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि लालू नीतीश का बिहार में एक साथ चुनाव लड़ना उनका एक तुफानी कदम ही है. जनता परिवार का एक होना देश के लिए शुभ संकेत हैं, क्योंकि मजबूत सरकार के साथ-साथ एक मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है, जो सरकार के जनविरोधी कदमों का जोरदार तरीके से विरोध कर सके. कांग्रेस अब उस हालत में नहीं है, क्योंकि जनता ने अब उसकी बातों पर विश्वास करना बंद कर दिया है. अगर बिहार विधान सभा चुनाव में जनता परिवार एक नहीं होता, तो भाजपा को कोई जीतने से नहीं रो सकता था. लेकिन अब बिहार विधान सभा में भाजपा को एक कड़ी चुनौती मिलेगी.

-सत्यनारायण तिवारी, दरभंगा, बिहार.

जांबाज़ वीके सिंह

आलेख-एक फौजी की निगरानी में हज मिशन, इस बार धोखेबाजों की खैर नहीं(22 जून -28 जून 2015) पढ़ा. काफी अच्छा लगा. नरेन्द्र मोदी सरकार ने यह काम बहुत अच्छा किया है कि इस बार हज यात्रा की जिम्मेदारी विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह को दिया है. जनरल वीके सिंह ने सेना में रहते हुए अपने कार्य को सफलता पूर्वक निभाया है और दुश्मनों को करारा जवाब दिया है. वे कुछ दिनों पहले जंग जैसे हालात से जूझते यमन में फंसे भारतीयों को वहां से सफलता पूर्वक निकाल कर लाए. जनरल वीके सिंह हज यात्रा की जिम्मेदारी को भी सफलता पूर्वक निभाएंगे.

-फिरोज खान, सीतापुर, उत्तर प्रदेश.

नरेन्द्र मोदी के लिए चुनौती

कुछ दिनों पहले अखबारों में और टीवी चैनलों पर आए सर्वे बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल को एक साल होने के बाद भी उन पर लोगों का विश्वास कायम है. लेकिन मोदी को जिस विचारधारा और पूंजी ने यहां तक पहुंचाया है, उसे एक साथ साधना मोदी के लिए कठिन चुनौती है. एक को हिन्दु धर्म और संस्कृति का परचम चाहिए, तो दूसरे को विकास. ऐसे में नरेन्द्र मोदी सामाजिक समरसता व आर्थिक बराबरी को साधकर ही अपनी राजनीति को नई उंचाईयों तक ले जा सकते हैं.

-सत्य प्रकाश(शिक्षक) लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

भगवान बुद्ध के वचन

चौथी दुनिया ब्यूरो

भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे. उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए. सभा में सभी शान्ति से बुद्ध की वाणी सून रहे थे, लेकिन वहां बैठा एक व्यक्ति अचानक ही आग-बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो. तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो. ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे. यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वहां से चला गया. अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहंच गया. उन्हें देखते ही वह उनके चरणो में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु.

बुद्ध ने पूछा: कौन हो भाई? तुम्हे क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो?

उसने कहा: क्या आप भूल गए. मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था. मै शर्मिन्दा हूं. भगवान बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा: बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो. तुम्हे अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो, अब तुम आज में प्रवेश करो. बुरी बाते तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते है. बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो.

उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया. उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्यागकर तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया. बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा. उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया, और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी. मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गयी किसी गलती के बारे में सोच कर बार-बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं. हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नयी ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

बाज़ार का बेवजह विरोध

अनंत विजय

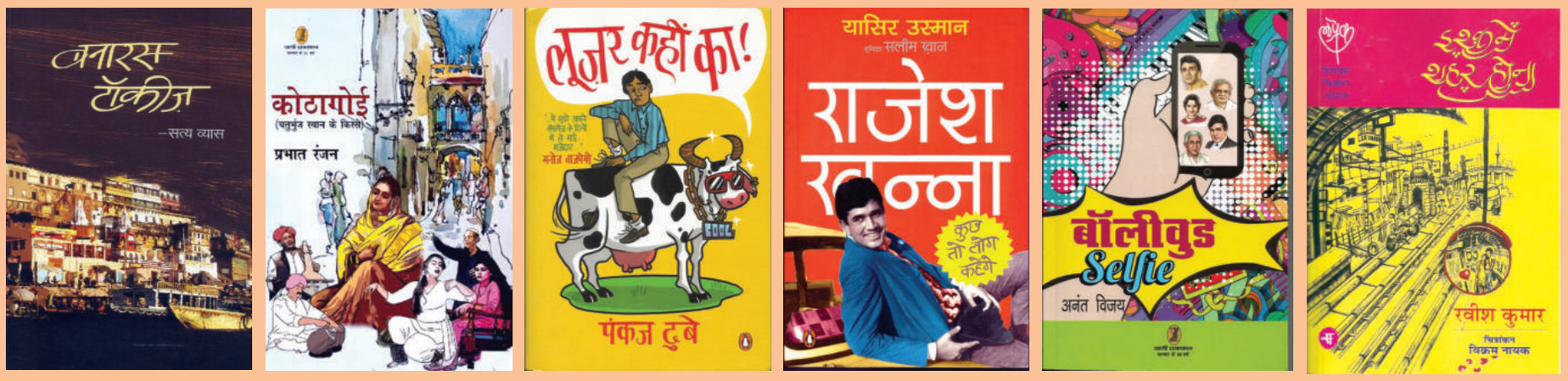

साहित्य और बाज़ार, यह एक ऐसा विषय है, जिसे लेकर हिंदी के साहित्यकार बहुधा बचते हैं या फिर मौक़ा मिलते ही बाज़ार की लानत-मलामत करने में जुट जाते हैं. बाज़ार एक ऐसा पंचिंग बैग है, जिस पर हिंदी साहित्य के पुरोधाओं से लेकर नौसिखिया लेखक तक आते-जाते मुक्का मारते हुए निकल जाते हैं. साहित्यकारों ने जिस तरह से बाज़ारवाद के विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है, उससे साहित्य का लगातार नुक़सान हो रहा है. बजाय इस नुक़सान को समझने के स्वयं को साबित करने और स्वयं को आदर्शवादी साबित करने की होड़ में बाज़ार का विरोध जारी है. सार्वजनिक मंचों पर बाज़ार का विरोध करना बौद्धिक होने का इंस्टैंट लाइसेंस है, ठीक उसी तरह, जैसे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की आलोचना करना सेक्युलरिज्म का लाइसेंस है. राजनीति की बात अलहदा है, लेकिन साहित्य में बाज़ारवाद के विरोध ने लेखकों की राह मुश्किल कर दी और नतीजा यह हुआ कि बाज़ार ने साहित्य को हाशिये पर डाल दिया. हाशिये पर जाने से यह हुआ कि किताबों की दुकानें और बिक्री लगभग ख़त्म हो गईं. इसका एक बड़ा नुक़सान यह भी हुआ कि प्रकाशकों का ध्यान साहित्य से ज़्यादा साहित्येतर किताबों की ओर चला गया है. अब कई प्रकाशक कहानी, कविता व उपन्यास आदि से इतर विधाओं की किताबों में ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं. उनका तर्क है कि साहित्य से ज़्यादा साहित्येतर विषयों की किताबें बिकती हैं. संभव है.

इस वक्त साहित्य में कवियों की कई पीढ़ियां एक साथ सक्रिय हैं, कुंवर नारायण से लेकर बाबुषा कोहली तक, लेकिन प्रकाशक हैं कि कविता संग्रह छापने को तैयार नहीं हैं. उनका साफ़ कहना है कि कविता का बाज़ार नहीं है, कविता संग्रह बिकते नहीं हैं. क्या यह स्थिति किसी भी भाषा के साहित्य के लिए उत्तम कही जा सकती है? कदापि नहीं. साहित्य को बाज़ार से अलग करने की ऐतिहासिक वजहें हैं. बाज़ार का विरोध करने वाले कमोबेश वही लोग हैं, जो पूंजीवाद का विरोध करते रहे हैं और पूंजीवाद का विरोध मार्क्सवाद के अनुयायी करते रहे हैं. साहित्य में लंबे समय तक और बहुत हद तक अभी भी मार्क्सवादियों का बोलबाला है, लिहाजा बाज़ार का विरोध होता रहता है. अगर हम वस्तुनिष्ठ होकर इस विरोध का आकलन करें, तो हमें इसमें बुनियादी दोष नज़र आता है. लेखक लिखता है और फिर वह उसे प्रकाशक को छापने के लिए देता है. किताब छपने के बाद प्रकाशक और लेखक, दोनों की इच्छा होती है कि उसकी बिक्री हो. प्रकाशक अपने कारोबार के लिए, तो लेखक पाठकों तक पहुंचने और बेहतर रॉयल्टी की अपेक्षा में बिक्री की इच्छा रखता है. अब देखिए, विरोधाभास यहीं से शुरू हो जाता है. वह लेखक, जो बाज़ारवाद को पानी पी-पीकर कोसता है, वही अपनी किताब को उसी बाज़ार में सफल होते देखना चाहता है, उसी बाज़ार से बेहतर रॉयल्टी की चाहत रखता है. अब यह कैसे संभव है कि आप जिसका विरोध करेंगे, वही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा? बाज़ार की चाहत होने के बावजूद लेखकों ने बाज़ार का विरोध करना शुरू कर दिया. नतीजा यह हुआ कि बाज़ार ने भी लेखकों को उपेक्षित कर दिया और अंतत: साहित्य का नुक़सान हो गया.

बाज़ार का विरोध एक हद तक उचित हो सकता है, लेकिन सुबह-शाम, उठते-बैठते बाज़ार को गाली देने का फैशन नुक़सानदेह है. जब मार्क्सवाद का प्रतिपादन किया गया था या उसके बाद जब कई देश उसके रोमांटिसिज्म में थे, उस वक्त बाज़ार का विरोध उचित लगता था. कालांतर में मार्क्सवाद की ज़्यादातर अवधारणाओं को लोगों ने ठुकरा दिया, लेकिन लेखकों द्वारा बाज़ार का विरोध जारी रहा. आज के बदले वैश्विक परिवेश में बाज़ार एक हक़ीक़त है. आप चाहें, तो उसे कड़वी मान लें. इस हक़ीक़त का विरोध कर या उससे ठुकरा कर प्रासंगिकता बरकरार रखना लगभग मुश्किल-सा है. हिंदी के लोगों को याद होगा, चंद सालों पहले दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने साहित्य अकादमी के साथ मिलकर लेखकों को पुरस्कृत करने की एक योजना बनाई थी. साहित्यकारों ने इतना हो-हल्ला मचाया कि उस कंपनी ने साहित्य से ही तौबा कर ली. पूंजीवाद और बाज़ारवाद का विरोध

बाज़ार का विरोध एक हद तक उचित हो सकता है, लेकिन सुबह-शाम, उठते-बैठते बाज़ार को गाली देने का फैशन नुक़सानदेह है. जब मार्क्सवाद का प्रतिपादन किया गया था या उसके बाद जब कई देश उसके रोमांटिसिज्म में थे, उस वक्त बाज़ार का विरोध उचित लगता था. कालांतर में मार्क्सवाद की ज़्यादातर अवधारणाओं को लोगों ने ठुकरा दिया, लेकिन लेखकों द्वारा बाज़ार का विरोध जारी रहा. आज के बदले वैश्विक परिवेश में बाज़ार एक हक़ीक़त है. आप चाहें, तो उसे कड़वी मान लें.

करने वाले हिंदी के साहित्यकारों को धन्ना सेठों से लखटकिया पुरस्कार लेने में संकोच नहीं होता है, लेकिन अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी साहित्य के लिए कुछ करना चाहती है, तो यह उन्हें साम्राज्यवाद, बाजारवाद और साहित्य को उपनिवेश बनाने की कोशिश लगने लगता है. बाज़ार की हक़ीक़त स्वीकार करते हुए उसे साहित्य और अपने हित में इस्तेमाल करने की कोशिश की जानी चाहिए. हमारे यहां तो साहित्य में जो एक सांचा बन जाता है और अगर वह जरा भी सफल हो जाता है, तो चीजें या रचनात्मकता भी उसी में ढलती रहती हैं. वसुधा के फरवरी 1957 के अंक में हरिशंकर परसाईं ने ढलवां साहित्य शीर्षक से लिखा था, जैसे एक सांचे में ढले गहने होते हैं, वैसा ही कुछ साहित्य विशेष प्रकार के सांचों में ढलकर बनता है. सांचे में सुभीता होता है, सुनार को सोचने का काम नहीं करना पड़ता. सांचे में नुक़सान भी है, एक किस्म का माल ढलता है, कारीगर की कला-प्रतिभा व्यर्थ चली जाती है, बदलती जनरुचि उसी के माल को कुछ दिनों बाद नापसंद करने लग जाती है. बाज़ारवाद के विरोध का भी यही हश्र हुआ. पहले तो यह लोगों को लुभाता था, आकर्षक लगता था, क्रांति आदि की आहट महसूस होती थी, लेकिन कालांतर में जनरुचि बदली, लेकिन साहित्य के अलंबरदारों ने बाज़ारवाद के विरोध का सांचा नहीं बदला. लगातार उसी में माल ढलता रहा और कलाकार की कला-प्रतिभा जनरुचि को पकड़ने में नाकाम रही. हरिशंकर परसाईं अपने उसी लेख में लिखते हैं, कई यथार्थवादी लेखक यथार्थ जीवन में प्रवेश किए बिना, जनजीवन से सीधा और संवेदनात्मक संपर्क स्थापित किए बिना एक सांचे पर ढलाई कर रहे हैं. इसमें मनुष्य कहीं दिखता नहीं है. कुछ समझते हैं कि सुर्ख मेंहदी, सुर्ख सूरज, लाल कमीज, सुर्ख धरती आदि लिख देने से यह प्रगतिवाद कहलाने लगेगा. या फिर किसी के द्वारा किसी की प्रेमिका को सुर्ख रूमाल भेंट करने से क्रांति हुए बिना नहीं रहेगी. इन रचनाओं में ठप्पेदार शब्दों के सिवाय कुछ नहीं रहता. जीवन तत्व ग़ैरहाजिर! संवेदना लुप्त!! बाज़ार और बाज़ारवाद का विरोध भी कुछ इसी तर्ज पर होता रहा है. अपने फ़ायदे के लिए बाज़ार का विरोध, वह भी घिसे-पिटे तर्कों के आधार पर. यह तो नहीं कहा जा सकता कि बाज़ार का विरोध करने वाले साहित्यकार बदलते वक्त को नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अपने फ़ायदे के लिए वे बाज़ारवाद के विरोध की दुदुंभि बजाना नहीं छोड़ रहे.

चालीस-पचास सालों बाद अब स्थितियां कुछ बदलती नज़र आ रही हैं. कुछ युवा लेखकों ने बाज़ार को ध्यान में रखकर किताबें भी लिखनी शुरू की हैं और उन्हें पाठक वर्ग तक पहुंचाने का उद्यम भी शुरू किया है. यह एक अच्छी सोच है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए. अंग्रेजी में हमेशा से यह होता रहा है. मुझे याद आता है कि जब 2007 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के डेढ़ सौ साल हो रहे थे, तो हिंदी के प्रकाशनों ने योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक कई किताबें जारी की थीं. उससे लेखकों को भी लाभ हुआ और प्रकाशकों को तो हुआ ही. इसी तरह 25-26 जून को इमरजेंसी के चालीस साल होने को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी के प्रकाशकों ने वरिष्ठ पत्रकार कूमी कपूर की किताब जारी कर दी. अब इस साल जब भी, जहां भी इमरजेंसी की बात हो रही, तो कूमी की किताब की चर्चा हो रही है. इससे किताबों का बाज़ार बनता है. हिंदी के प्रकाशक एवं लेखक, दोनों इस तरह से योजना बनाकर किसी खास तिथि को ध्यान में रखते हुए न तो किताब लिखते हैं और न छापते हैं.

बाज़ार को भुनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की ज़रूरत है. स्वांत: सुखाय लेखन के बजाय बहुजन हिताय की ओर क़दम बढ़ाने की ज़रूरत है. अंग्रेजी में दो-चार किताबें लिखकर लेखक का जीवन चल जाता है, लेकिन हिंदी में नहीं. क्यों? वजह साफ़ है. दीवार पर लिखी इबारत को भी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यह सब कुछ देखकर अनदेखा करने जैसी स्थिति है. आज के युवा लेखकों को भी यह समझना होगा कि बाज़ारवाद का विरोध करके साहित्य के चंद मठाधीशों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सकता है, कुछ प्रसिद्धि आदि भी मिल सकती है, लेकिन पाठकों का प्यार हासिल नहीं हो सकता. पाठकों तक पहुंचने का माध्यम बाज़ार ही है. अंग्रेजी में एक कहावत है, च्वाइस इज योर्स. तय कर लीजिए.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

व्यक्तित्व के धनी बाबू राम बुझावन

डॉ. अनिल सुलभ

हिंदी साहित्य के ही नहीं, अपितु सार्वजनिक जीवन में ही अजातशत्रु थे राम बुझावन बाबू. वह इकहरे बदन के सुदर्शन कद और व्यक्तित्व के धनी थे. मंद-स्मित भाव से युक्त, शांत और गुरु-गंभीर मुखारविंद था उनका. आकर्षक और प्रभावशाली. बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन समेत अन्य साहित्यिक एवं सारस्वत संस्थाओं के आयोजनों में उनसे मिलना हो जाता था. विद्वता एवं विनम्रता, जो एक-दूसरे की पूरक और पर्यायवाची हैं, उनमें सहज द्रष्टव्य थीं. वह शील के प्रतिमान कहे जा सकते थे. सामने पड़ते ही नमस्कार के साथ उनके जुड़े हाथ उनकी विनम्रता की ऊंचाई को और बड़ा कर देते थे. जीवन के अंतिम वर्षों में भी उनकी यह प्रवृत्ति बदली नहीं थी। ऊर्जा का अशेष भंडार उनमें था. ढलान की उम्र में भी, जब उनके दुबले एवं लंबे शरीर पर, चेहरे पर ढीली हो रही चमड़ी ढलकने लगी थी, उनके स्वर में वही पुरानी बुलंदी थी, जो कभी एक व्याख्याता एवं प्राध्यापक के रूप में रही होगी.

ऊंचे, गंभीर एवं सुस्पष्ट स्वर में दिए जाने वाले उनके व्याख्यान बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अनेक बार अध्यक्ष रह चुके ऋषि तुल्य मनीषी विद्वान एवं साहित्यकार पंडित राम दयाल पांडेय की याद दिलाते थे. उनका सरल, निश्छल, तरल एवं विरल व्यक्तित्व आज सुलभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है. लगभग 40 वर्षों तक पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के व्याख्याता एवं प्राध्यापक के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं देने वाले और अनेक शिष्यों एवं प्रशिष्यों के अतुल्य श्रद्धास्पद गुरु-दादागुरु प्रोफेसर राम बुझावन सिंह के यही गुण उन्हें अजातशत्रु बनाते थे और यही गुण उनके दीर्घायुष्य के कारक भी थे. कुछ और वर्ष जीते, तो सौ वर्ष की आयु जीने वाले कुछ चंद लोगों में वह भी गिने जाते. उन्होंने 94 वर्ष की आयु में इस नश्वर संसार से विदा ली. विरले लोग ही ऐसी आयु और ऐसा जीवन जीते हैं, जिनके जाने के बाद भी दुनिया उन्हें भरे हृदय और सजल नेत्रों से याद करती है.

हिंदी साहित्य के अजातशत्रु नामक स्मृति-ग्रंथ उनके विशाल व्यक्तित्व और सफल जीवन के अंश लेकर प्रकाशित हुई है. राम बुझावन बाबू जैसे व्यक्ति पर, जो संस्थाओं की संस्था थे, व्यक्ति-भर नहीं, डेढ़-दो सौ पृष्ठों की पुस्तक पर्याप्त नहीं हो सकती, तथापि पुस्तक

हिंदी साहित्य के अजातशत्रु नामक स्मृति-ग्रंथ उनके विशाल व्यक्तित्व और सफल जीवन के अंश लेकर प्रकाशित हुई है. राम बुझावन बाबू जैसे व्यक्ति पर, जो संस्थाओं की संस्था थे, व्यक्ति-भर नहीं, डेढ़-दो सौ पृष्ठों की पुस्तक पर्याप्त नहीं हो सकती, तथापि पुस्तक के विद्धान प्रधान संपादक डॉ. गनौरी महतो एवं सुबुद्ध संपादक आलोक कुमार सिन्हा ने, श्रमपूर्वक बिहार के सुप्रतिष्ठित साहित्य-सेवियों और मनीषी विद्धानों से जो संस्मरणात्मक आलेख मंगवाने में सफलता प्राप्त की, उन संग्रहणीय आलेखों के कारण यह पुस्तक प्रबुद्ध एवं श्रद्धावान पाठकों के लिए एक निधि बन गई है. इन आलेखों को पढ़कर राम बुझावन बाबू के विराट व्यक्तित्व को काफी हद तक समझा जा सकता है.

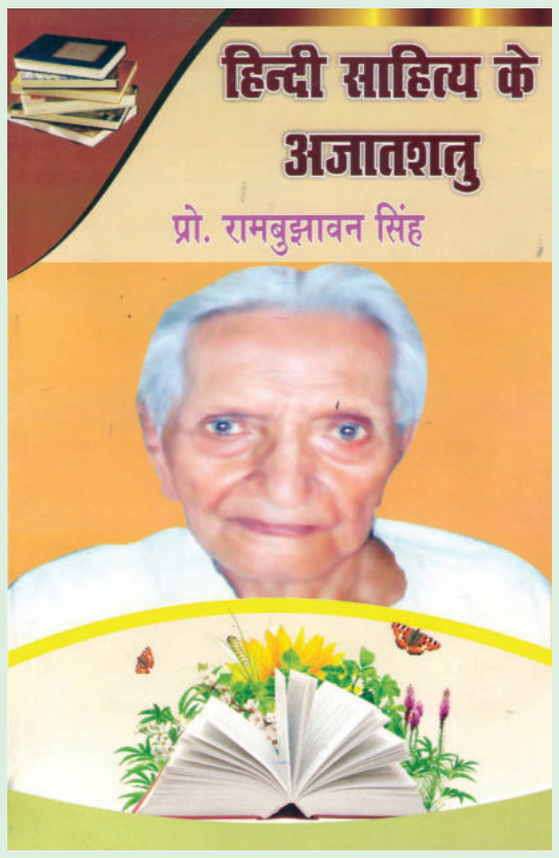

के विद्वान प्रधान संपादक डॉ. गनौरी महतो एवं सुबुद्ध संपादक आलोक कुमार सिन्हा ने, श्रमपूर्वक बिहार के सुप्रतिष्ठित साहित्य-सेवियों और मनीषी विद्वानों से जो संस्मरणात्मक आलेख मंगवाने में सफलता प्राप्त की, उन संग्रहणीय आलेखों के कारण यह पुस्तक प्रबुद्ध एवं श्रद्धावान पाठकों के लिए एक निधि बन गई है. इन आलेखों को पढ़कर राम बुझावन बाबू के विराट व्यक्तित्व को काफी हद तक समझा जा सकता है.

पुस्तक में संकलित कविवर सत्य नारायण, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद, साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री एवं विद्वान साहित्यकार आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव, आचार्य निशांत केतु, प्रोफेसर राम वचन राय, डॉ. शिववंश पांडेय, डॉ. रामदेव प्रसाद, डॉ. चितरंजन प्रसाद सिंह, डॉ. कुणाल कुमार, सिद्धेश्वर और साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष एवं भाषा भारती संवाद के प्रधान संपादक नृपेंद्र नाथ गुप्त के आलेख विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. कुल 29 आलेखों के इस पठनीय ग्रंथ में जिन अन्य विद्वानों के मूल्यवान आलेख संकलित किए गए हैं, उनमें पंडित शिवदत्त मिश्र, डॉ. यशवंत सिंह, मिथिलेश कुमारी, डॉ. जयंत सिंह, डॉ. ध्रुव कुमार, राजेंद्र पांडेय, रमाकांत रंजन किशोर, सच्चिदानंद श्याम, बांके बिहारी साव, प्रोफेसर विमला आर्या, प्रोफेसर सुखित वर्मा, डॉ. नीरज कुमार और संपादक-द्वय डॉ. गनौरी महतो एवं आलोक कुमार सिन्हा आदि शामिल हैं.

प्रांजलि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक न केवल उस अजात शत्रु प्रो. राम बुझावन सिंह के विराट व्यक्तित्व को संसार के समक्ष प्रतिष्ठित करती है, अपितु अनेक प्रकार से सुबुद्ध पाठकों के लिए लाभकारी है, ऐसा मेरा विश्वास है. दिवंगत श्रद्धेय बाबू राम बुझावन की आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि के इस पुष्प-गुच्छ के रूप में तर्पण की इस समष्टि-परक क्रिया से अपने मन-प्राण को शुद्ध करने तथा पाठक-वृंद को भी इसका अवसर प्रदान करने के इस सारस्वत कार्य हेतु प्रकाशक और संपादकों के साथ उनके सहयोगीगण डॉ. यशवंत सिंह, श्रीमती शैल सिन्हा, डॉ. राज नारायण राय, डॉ. रामदेव प्रसाद, पंडित शिवदत्त मिश्र बधाई के पात्र हैं. पुस्तक की सर्व-ग्राह्यता अवश्यमेव असंदिग्ध है.■

feedback@chauthiduniya.com

ज़ोलो ने बेहद सस्ता लैपटॉप लॉन्च किया

ज़ोलो ने किफायती क्रोमबुक लैपटॉप लॉन्च किया है. इस क्रोमबुक लैपटॉप में 11. 6 इंच की स्क्रीन दी गई है. इसमें 2 जीबी रैम है. इस लैपटॉप में गूगल ड्राइव 100 जीबी स्टोरेज की क्षमता है. इस लैपटॉप में एचडी 720x1280 पिक्सल रेजोल्यूशन वेबकैम दिया गया है. जोलो क्रोमबुक में 16 जीबी की मेमोरी है. इस लैपटॉप में ब्लूटुथ जैसे बेसिक फीचर्स दिए गए हैं और साथ ही एचडीएमआई, कार्ड रीडर, दो यूएसबी पोर्ट्स, वाई-फाई भी है. कनेक्टिविटी की बात करें, तो इस लैपटॉप में कंपनी ने दो यूएसबी 2.0 पोर्ट, एसडी कार्ड रीडर, एचडीएमआई, वाई-फाई और ब्लूटुथ के ऑप्शन उपलब्ध हैं. जोलो क्रोमबुक लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर 2 से 10 घंटे तक काम करता है. अन्य फीचर जैसे 9 यूजर्स एक साथ वीडियो चैटिंग कर सकते हैं. इसके साथ ही जीमेल और गूगल ड्राइव ऑफलाइन भी इस्तेमाल किया जा सकता है.■

माइक्रोमैक्स का कैनवस टेबी लैपटॉप

इस टैबलेट में 8जीबी की इंटरनल मेमोरी है. इसमें 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और फ्रंट में वीजीए कैमरा है. माइक्रोमैक्स कैनवस टैबलेट को पहली बार बच्चों पर फोकस करते हुए बनाया गया है. इससे मोबाइल फोन की तरह वॉयस कॉल भी की जा सकती है. माइक्रोमैक्स कैनवस टेबी टेबलेट के साथ कंपनी एजुकेशन से जुड़े 100 एप्स और 500 से ज्यादा वीडियो फ्री में दे रही है. इसके अलावा इसमें किड्स पेंट वाइल्ड एनिमल, किड्स पेंट वीकल, किड्स स्पैल और लर्न फ्रूट्स, लर्न बॉडी पार्ट्स जैसे कई सारे फीचर्स उपलब्ध हैं.

माइक्रोमैक्स ने कैनवस टेबी नाम का नया टैबलेट लॉन्च किया है. इस टैबलेट में 7 इंच की स्क्रीन दी गई है. इस फोन का डिस्प्ले 7 इंच का है. यह एंड्रॉयड 4.4 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और इसमें 1.3 गीगाहर्ट्ज ड्यूलकोर प्रोसेसर है. इसमें 1 जीबी रैम है और यह ड्यूल सिम सपोर्ट टैबलेट है. इस टैबलेट में 8जीबी की इंटरनल मेमोरी है. इसमें 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और फ्रंट में वीजीए कैमरा है. माइक्रोमैक्स कैनवस टैबलेट को पहली बार बच्चों पर फोकस करते हुए बनाया गया है. इससे मोबाइल फोन की तरह वॉयस कॉल भी की जा सकती है. इस टेबी टैबलेट में किड्स एजुकेशन का ध्यान रखा गया है. माइक्रोमैक्स कैनवस टेबी टैबलेट के साथ कंपनी एजुकेशन से जुड़े 100 एप्स और 500 से ज्यादा वीडियो फ्री में दे रही है. इसके अलावा इसमें किड्स पेंट वाइल्ड एनिमल, किड्स पेंट वीकल, किड्स स्पैल और लर्न फ्रूट्स, लर्न बॉडी पार्ट्स जैसे कई सारे फीचर्स उपलब्ध हैं. यह टैबलेट 32 जीबी तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है. यह एक 3जी टैबलेट है, जिसमें वाई–फाई, ब्लूटुथ 4.0, जीपीएस और माइक्रो यूएसबी जैसे कई सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए गए हैं. इसकी बैटरी 3200 एमएएच की है. इसकी कीमत 6499 रूपए रखी गई है. ■

Say hello to Canvas Tabby – the window for your kid to explore the world!

Android KitKat 4.4 | Customised Kids Mode | ParentalControl & Reports

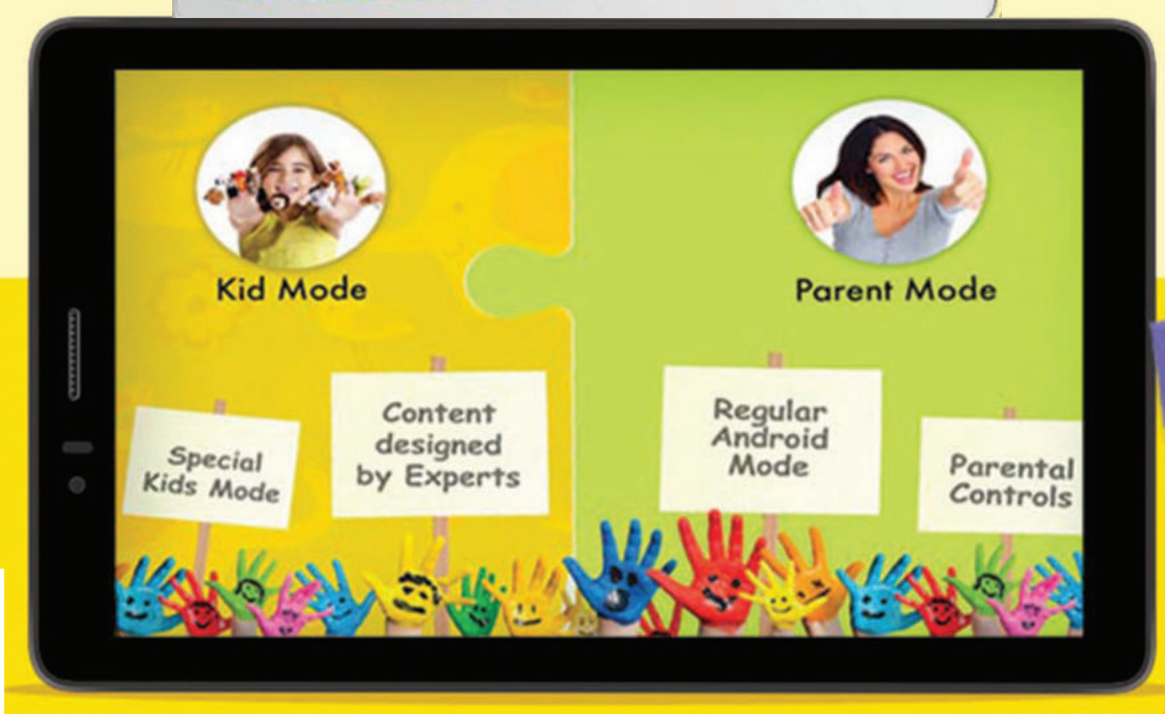

we touch. we learn

Powered by

दुकाती ने लॉन्च की यूनिक बाइक्स

इटली की प्रसिद्ध बाइक निर्माता कंपनी दुकाती ने दो नई बाइक्स बाजार में उतारी है. कंपनी ने इन्हें अपनी स्क्रंबलर बाइक सीरीज के तहत आईकन तथा अरबल एंडूरो नाम से लॉन्च किया है. 803 सीसी इंजन से लैस यह बाइक कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन तथा स्टील टीयरड्रॉप टैंक के साथ इंटरचेंजेबल एल्युमिनियम साइड पेनल्स से लैस है. इसके अलावा इसमें चौड़े हेंडलबार्स, ग्लास लैंस तथा एलईडी गाइड लाइट वाली हेडलाइट तथा डयूल स्पोर्ट व्हील्स दिए गए हैं. दुकाती स्क्रंबलर आईकन को येलो तथा दुकाती रेड कलर्स इन रंगों की च्वॉयस में उतारा गया है. यह सबसे यूनिक लुक और डिजाइन वाली बाइक है जो कंफर्टेबल सीट के साथ आई है. कंपनी का कहना है कि रिब्बड डिजाइन, टेक्निकल फेब्रिक्स के साथ लाइन्स वाली यह बाइक फर्स्ट क्लास एर्गोनोमिक कंफर्ट देने वाली है. इस बाइक में फोर्क प्रोटेक्टर्स, इंजन संप गार्ड, हेडलाइड ग्रिल प्रोटेक्टर आदि उपलब्ध हैं. अरबन एंडूरो दिखने में ऑफ रोड बाइक जैसी लगती है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक फाइबर से बने हाई माउंटेड मैडगाड तथा स्पॉक व्हील्स दिए गए हैं. इस बाइक कीमत लगभग 7 लाख रुपये है.■

दुकाती स्क्रंबलर आईकन को येलो तथा दुकाती रेड कलर्स इन रंगों की च्वॉयस में उतारा गया है. यह सबसे यूनिक लुक और डिजाइन वाली बाइक है जो कंफर्टेबल सीट के साथ आई है.

इस डिवाइस से अपने टीवी को कम्प्यूटर में बदलिए

स्पलेंडो हकीकत में एक पोर्टेबल मिनी डेस्कटॉप कम्प्यूटर है. इसमें वो सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मौजूद हैं, जो एक पीसी में होते हैं. यह विंडोज 8.1 ओएस पर काम करता है. इसके अलावा यह वायरलैस माऊस तथा की-बोर्ड से कनेक्ट हो जाता है.

एक ऐसी डिवाइस बाजार में उपलब्ध है, जिससे आप अपने टीवी को कम्प्यूटर में बदल सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट और आईबॉल ने मिलकर स्पलेंडो नाम की एक ऐसी छोटी सी डिवाइस लॉन्च की है, जो आपके टीवी को कंप्यूटर में बदल सकती है. इस डिवाइस को आप अपनी जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं. इस डिवाइस को टीवी से कनेक्ट करने के बाद आप उसमें वो सभी काम कर सकते हैं, जो एक पर्सनल कम्प्यूटर होते हैं.

स्पलेंडो हकीकत में एक पोर्टेबल मिनी डेस्कटॉप कम्प्यूटर है. इसमें वो सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मौजूद हैं, जो एक पीसी में होते हैं. यह विंडोज 8.1 ओएस पर काम करता है. इसके अलावा यह वायरलैस माऊस तथा की-बोर्ड से कनेक्ट हो जाता है. इसमें दिए गए यूएसबी पोर्ट के तहत टीवी से कनेक्ट करने के बाद आप वेब ब्राउजिंग समेत ईमेल चैक करने यूटयूब वीडियो देखने, गेम खेलने और डॉक्यूमेंट्स एडिट करने जैसे कार्य कर सकते हैं. स्पलेंडो मिनी डेस्क्टॉप में 2जीबी रैम, 32 जीबी इंटरनल मेमोरी, एचडीएमआई मेल प्लग, नॉर्मल यूएसबी पोर्ट, माइक्रोयूएसबी पोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटुथ 4.0 आदि गए हैं. इसकी 1 साल की वॉरंटी भी है. इसकी कीमत 8999 रूपये रखी गई है.■

माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टेबल डुअल चार्जर

माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बैंक लॉन्च किया है. माइक्रोसॉफ्ट पोर्टेबल चार्जर का आकार इतना छोटा है कि इसे आप आसानी से जेब में रख सकते हैं. लेकिन यह केवल ब्लैक कलर में उपलब्ध है. 5200 एमएएच बैटरी वाले पॉवर बैंक का वजन 141 ग्राम है. 9000 एमएएच बैटरी वाला पॉवर बैंक 215 ग्राम का है, वहीं 9000 एमएएच बैटरी वाले पॉवर बैंक का वजन 275 ग्राम है. माइक्रोसॉफ्ट पोर्टेबल चार्जर्स में दो यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं. इस पावर बैंक से आप एकसाथ दो फोन को चार्ज कर सकते हैं.

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यह चार्जर स्मार्टफोन के साथ ही साथ टैबलेट को भी चार्ज करने में समक्ष है. बाजार में उपलब्ध अन्य पावर बैंक की तरह माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टेबल चार्जर में भी एक एलईडी लाइट लगाई गई है, जिससे इसकी बैटरी में पावर होने का पता चलेगा.

यह पावर बैंक 5200 एमएएच, 9000 एमएएच और 12000 एमएएच की बैटरी क्षमता के साथ मिलेगा. भारत में इसकी कीमत लगभग क्रमश: 2,200 रुपये, 2,900 रुपये और 3,500 रुपये हो सकती है तय की जा सकती है.■

इस कैमरे से फोन पर देखें, घर में क्या हो रहा है

सिक्योरिटी कैमरे बनाने वाली कंपनी नेटगियर ने अर्लो नाम के कैमरे लॉन्च किए हैं. यह कैमरे वायरलैस हाई डेफिनेशन होम सिक्योरिटी कैमरे हैं. अब तक आपको घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे से रिकॉर्डिंग सेव करने के लिए किसी डिवाइस से वायर माध्यम से जोड़ना पड़ता था, लेकिन अब यह नहीं करना होगा. नेटगियर ने सिक्योरिटी कैमरी वाली पूरी किट उतारी है. इस किट में दो एचडी आउटडोर कैमरे मोशन सेंसर्स तथा नाइट विजन केपेबिलिटी के साथ दिए जा रहे हैं. इसके अलावा इसमें एक स्मार्ट होम बेस स्टेशन, चार मैग्नेटिक डोम माउंट्स तथा दो अतिरिक्त माउंट्स तथा 200 एमबी फ्री क्लाउड स्टोरेज दिया जा रहा है. इसके साथ ऑफर है कि यदि कोई ग्राहक नेटगियर वायरलैस सिक्योरिटी वाली यह किट न लेकर आप केवल कैमरा ही लेना चाहे तो भी उपलब्ध है. कंपनी एक कैमरे को 9900 रूपये बेच रही है. इसके अलावा यदि कोई ग्राहक पूरी किट ले रहा है तो उन्हें एक फ्री एप भी उपलब्ध कराया जा रहा है. इस एप के तहत कैमरे द्वारा की जा रही रिकॉर्डिंग का लाइव यूजर अपने आईओएस अथवा एंड्रॉयड स्मार्टफोन/टैबलेट्स पर देख सकते हैं. नेटगियर सिक्योरिटी कैमरों वाली कंप्लीट किट की कीमत 35000 रूपये रखी गई है.■

दूसरे नंबर पर रहे श्रीलंका के कुमार संगकारा को 14 प्रतिशत वोट मिले, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट 13 प्रतिशत वोट के साथ क्रिकेट प्रशंसकों की तीसरी पसंद रहे. 2013 में क्रिकेट को अलविदा कहने वाले तेंदुलकर शीर्ष दस टेस्ट खिलाड़ियों में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं. शीर्ष दस खिलाड़ियों की सूची में श्रीलंका के दो, दक्षिण अफ्रीका के तीन और ऑस्ट्रेलिया के चार खिलाड़ी शामिल हैं.

नेमार को मिस करूंगा : मेसी

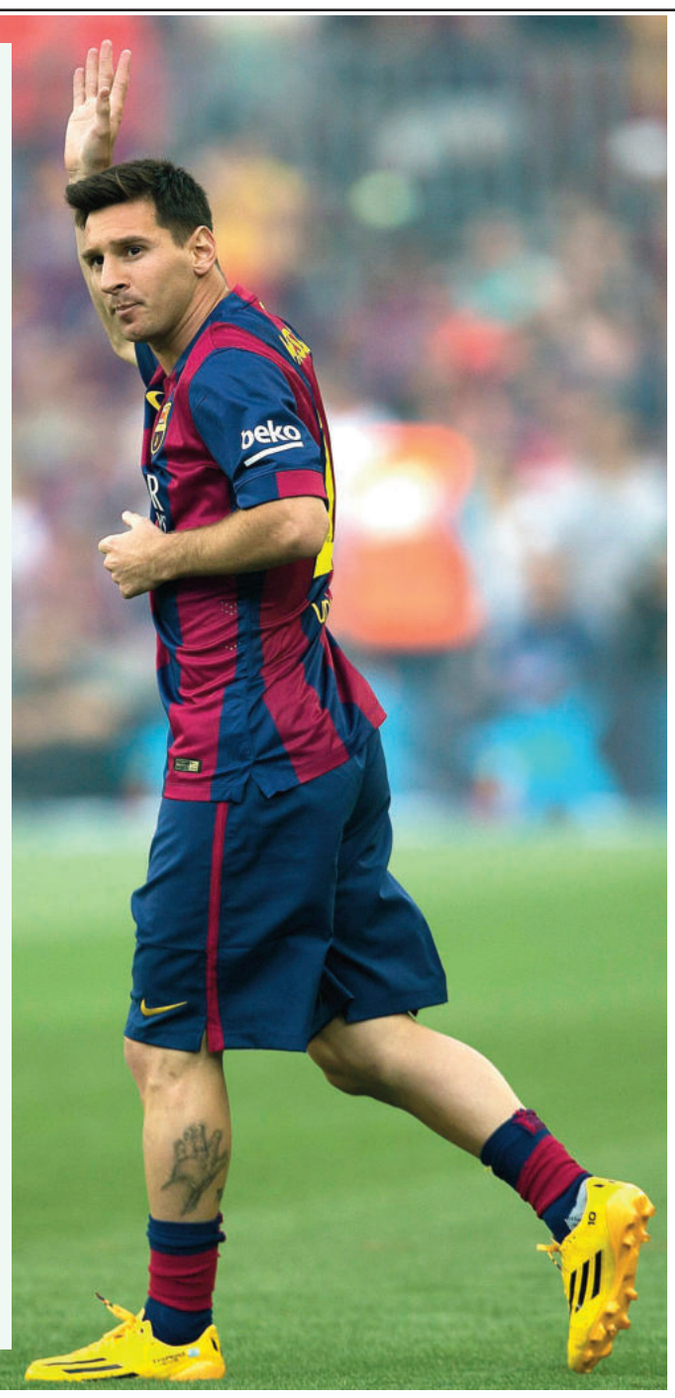

चौथी दुनिया ब्यूरो

अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान लायनल मेसी ने कहा है कि वे कोपा अमेरिका प्रतियोगिता में नेमार की कमी महसूस करेंगे. नेमार पर पूरी प्रतियोगिता के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. दरअसल ब्राजील और कोलंबिया के बीच ग्रुप स्टेज के दौरान नेमार कोलंबियाई खिलाड़ी से भिड़ गए थे. इसके बाद नेमार पर चार मैच का बैन लगाया गया है. ब्राजील ये मैच हार गया था. 1991 के बाद ये ब्राजील पर कोलंबिया की पहली जीत थी. ब्राजील फुटबॉल कॉन्फेडरेशन प्रतिबंध के खिलाफ अपील करने के बारे में सोच रही है. ब्राजील के कोट डुंगा ने कहा, कानूनी विशेषज्ञ इस पर फैसला करेंगे. हम नहीं चाहते कि कुछ हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो. हम चाहते हैं कि संतुलित फैसला हो. अपने बार्सिलोना टीम–मेट के बारे में मेसी का कहना था, मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि नेमार कोपा अमेरिका प्रतियोगिता में नहीं खेलेंगे. नेमार मेरा दोस्त है और मुझे उनकी फिक्र है. ब्राजील के लिए नेमार बहुत अहम है. ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला तीन–तीन अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर हैं. ■

दरअसल ब्राजील और कोलंबिया के बीच ग्रुप स्टेज के दौरान नेमार कोलंबियाई खिलाड़ी से भिड़ गए थे. इसके बाद नेमार पर चार मैच का बैन लगाया गया है. ब्राजील ये मैच हार गया था. 1991 के बाद ये ब्राजील पर कोलंबिया की पहली जीत थी. ब्राजील फुटबॉल कॉन्फेडरेशन प्रतिबंध के खिलाफ अपील करने के बारे में सोच रही है.

धोनी के बचाव में पाकिस्तानी क्रिकेटर

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम के एकदिवसीय कप्तान महेन्द्र सिंह धौनी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद आफरीदी उनके बचाव में उतर आए हैं. पाकिस्तान टी–20 टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है

कि जिस तरह से धोनी को टारगेट किया जा रहा है, वो उससे खुश नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उप–महाद्वीप में इस तरह की परंपरा है कि एक सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद बेहतरीन क्रिकेटर की भी आलोचना होने लगती है. उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के मौजूदा प्रदर्शन के बारे में आलोचना होनी चाहिए मगर उस खिलाड़ी के पिछले प्रदर्शन को भी देखना चाहिए. अगर आप धोनी की बात करते हैं, तो उनके रिकॉर्ड को आप देखिए और फिर किसी नतीजे पर पहुंचें. वो भारत के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका रिकॉर्ड ये साबित भी करता है. एक कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर धोनी की सफलता गजब की रही है. उन्होंने भविष्य के लिए एक बेहतरीन टीम का निर्माण किया है. ■

जहीर अब्बास आईसीसी के नए अध्यक्ष बने

आईसीसी का नया अध्यक्ष पाकिस्तान के पूर्व कप्तान को बनाया गया है. जहीर अब्बास का कार्यकाल एक साल का होगा. बार्बेडॉस में हुई तीन दिन की सालाना बैठक में यह फैसला लिया गया. जहीर अब्बास इस बैठक में मौजूद थे और उन्हाने वहां पर मौजूद सभी लोगों का आभार प्रकट किया. मैं पीसीबी का शुक्रगुजार हूं. उन्होंने कहा कि मैं हमारे महान खेल के संचालन मंडल का अध्यक्ष बन कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. इस खेल ने अलग–अलग क्षमता के साथ हम लोगों को दोस्ती, इज्जत, पहचान और अपने–अपने देशों की सेवा करने का मौका दिया. व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि इस खेल ने जो मुझे दिया है, जिसे मैं शायद ही कभी चुका सकूं. मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आईसीसी सदस्यों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस खेल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा. जहीर अब्बास ने पाकिस्तान की और से 78 टेस्ट मैच, 62 वनडे मुकाबले खेले हैं और अपने 22 साल के प्रथम–श्रेणी के क्रिकेट में उन्होंने 34,843 रन बनाए हैं.■

आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 10 में अश्विन

आईसीसी की रैंकिंग में वनडे गेंदबाजों की लिस्ट में भारतीय किक्रेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन टॉप 10 में शामिल हो गए. बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे मैचों में 6 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन दो पायदान चढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं. अभी तक टॉप 10 में अश्विन भारत के इकलौते गेंदबाज हैं, जो आईसीसी की रैंकिंग में 10वें नंबर पर हैं, इसी के साथ मोहम्मद शमी दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं, जो टॉप 20 में शामिल हैं. शमी 12 वे नंबर पर है. अगर बल्लेजी की बात करें, तो विराट कोहली भारतीय खिलाड़ियों में चौथे नंबर पर हैं. शिखर धवन 6वें पायदान से खिसककर 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं. भारतीय कप्तान धोनी आंठवें नंबर पर बने हुए हैं. ■

सचिन बने 21वीं सदी के नंबर वन टेस्ट क्रिकेटर

भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी चुना गया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक ऑनलाइन पोल में सचिन को सबसे अधिक 23 प्रतिशत वोट मिले. साल 2000 के बाद से 100 सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ियों के लिए कराए गए इस ऑनलाइन पोल के वोटों की गिनती 10 दिन तक चली. बाद में पाठकों ने शीर्ष दस खिलाड़ियों पर चर्चा की. वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस टीम के सलाहकार के रूप में काम कर रहे तेंदुलकर को 23 प्रतिशत वोटों के साथ सदी का नंबर एक टेस्ट खिलाड़ी चुना गया. दूसरे नंबर पर रहे श्रीलंका के कुमार संगकारा को 14 प्रतिशत वोट मिले, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट 13 प्रतिशत वोट के साथ क्रिकेट प्रशंसकों की तीसरी पसंद रहे. 2013 में क्रिकेट को अलविदा कहने वाले तेंदुलकर शीर्ष दस टेस्ट खिलाड़ियों में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं. शीर्ष दस खिलाड़ियों की सूची में श्रीलंका के दो, दक्षिण अफ्रीका के तीन और ऑस्ट्रेलिया के चार खिलाड़ी शामिल हैं. ■

वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस टीम के सलाहकार के रूप में काम कर रहे तेंदुलकर को 23 प्रतिशत वोटों के साथ सदी का नंबर एक टेस्ट खिलाड़ी चुना गया. दूसरे नंबर पर रहे श्रीलंका के कुमार संगकारा को 14 प्रतिशत वोट मिले, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट 13 प्रतिशत वोट के साथ क्रिकेट प्रशंसकों की तीसरी पसंद रहे.

शीर्ष दस टेस्ट खिलाड़ियों की सूची

खिलाड़ी	वोट
1–सचिन तेंदुलकर (भारत)	23%
2–कुमार संगकारा (श्रीलंका)	14%
3– एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)	13%
4–रिकी पोंटिंग(ऑस्ट्रेलिया)	11%
5– जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)	11%
6– एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)	10%
7– शेन वार्न (ऑस्ट्रेलिया)	9%
8– ग्लेन मैकग्रा (ऑस्ट्रेलिया)	5%
9– मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)	3%
10– डेल स्टेन (दक्षिण अफ्रीका)	1%

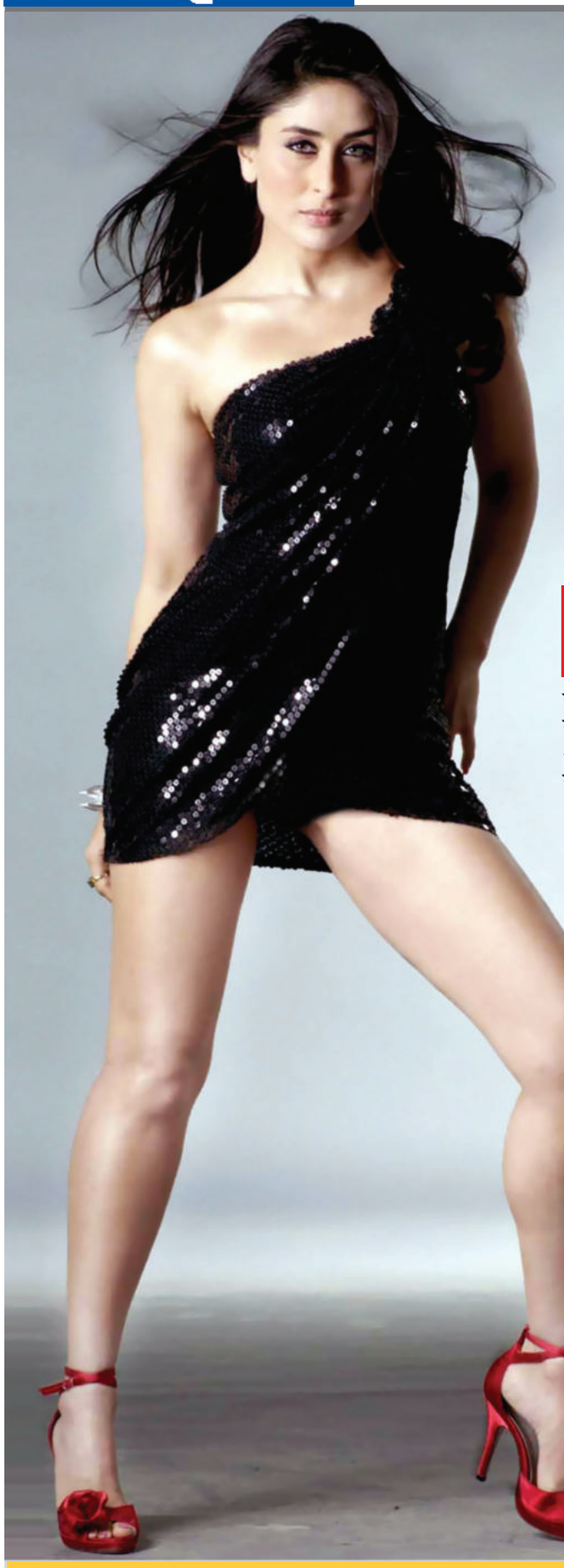

करीना को ग्लैमरस देखना चाहती हैं शर्मिला

करीना ने कहा उन्होंने मुझे फेवीकोल गाने (दंबग-2) में पसंद किया था, उन्हें मेरा डांस पंसद आया था. करीना ने कहा कि शादी और बच्चे होने के बाद भी उन्होंने करियर जारी रखा वह मेरे लिए प्रेरणा हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया.

अभिनेत्री करीना कपूर का कहना कि उनकी सास शर्मिला टैगोर उन्हें ग्लैमरस भूमिकाओं में देखना पसंद करती हैं. करीना ने कहा कि वो हमेशा मुझे सेक्सी और ग्लैमरस देखना चाहती हैं. गृहस्थी और फिल्मी जीवन को साथ-साथ लेकर चलने का प्रेरणा करीना अपनी सास शर्मिला से लेती हैं. करीना ने कहा उन्होंने मुझे फेवीकोल गाने (दंबग-2) में पसंद किया था, उन्हें मेरा डांस पंसद आया था. करीना ने कहा कि शादी और बच्चे होने के बाद भी उन्होंने करियर जारी रखा वह मेरे लिए प्रेरणा हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया. उन्होंने बड़े सुपरस्टार और फिल्मकारों के साथ काम किया. यह मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है कि अपने फिल्मी जीवन के साथ-साथ परिवार को भी हमेशा साथ लेकर चलने की प्रेरणा मुझे उनसे ही मिलती है. करीना ने कहा कि मैं हेमा मालिनी और अपनी सास की बड़ी फैन रही हूं. मुझे उनका किरदार काफी पंसद आता था. मैं उनकी कमी फिल्मों में महसूस करती हूं, क्योंकि वह बहुत महान अभीनेत्रियों में शुमार थीं और उनके अभिनय के लोग दीवाने थे.■

करीना ने आलिया- वरुण की तारीफ

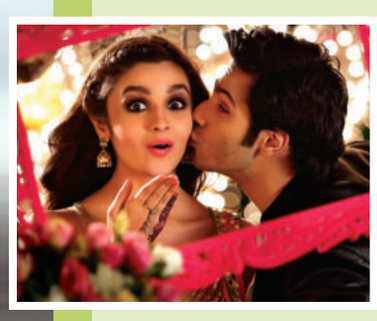

करीना कपूर का मानना है कि अपनी पीढ़ी में वे लंबी रेस का घोड़ा थीं. करीना का कहना है कि आज मैं एक हीरोइन के साथ-साथ स्टार भी हूं. अपना स्टार स्टेटस बनाए रखने के लिए कमर्शियल फिल्में भी करनी होती हैं, जो मैंने हमेशा की. लेकिन ऑफबीट फिल्में भी मेरे करियर का हिस्सा रही हैं. उनके और ऋतिक के स्थान पर फिल्म शुद्धि में काम कर रहे वरुण और आलिया को उन्होंने बॉलीवुड का डार्क हॉर्स बताया जो शीर्ष तक जाएंगे. आलिया के साथ उन्होंने उड़ता पंजाब की है, लेकिन दोनों का कोई सीन साथ नहीं होगा. करीना ने कहा कि आलिया में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है वे टॉप तक पहुंचेंगी. वे अर्जुन कपूर के साथ आर. बाल्की की फिल्म करेंगी. उन्होंने ये रोल मुझे ध्यान में रखते हुए ही लिखा है. मेरे घर जब कहानी सुना रहे थे, तो इंटरवल तक आते ही मैंने कह दिया मैं कर रही हूं.■

हॉलीवुड ख़बरें

हॉलैंड अगले स्पाइडरमैन होंगे

पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रूप में हॉलैंड की पहली फिल्म 28 जुलाई 2017 को रिलीज होगी.

एक्टर टॉम हॉलैंड पॉपुलर फिल्म सीरीज की अगली फिल्म में स्पाइडरमैन बनेंगे. सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियो ने दुनिया भर में किरदारों की तलाश करने के बाद 19 वर्षीय हॉलैंड का नाम तय किया है. कॉप कार मूवी फेम जॉन वाट्स स्पाइडरमैन का निर्देशन करेंगे. पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रूप में हॉलैंड की पहली फिल्म 28 जुलाई 2017 को रिलीज होगी. इससे पहले स्पाइडरमैन फिल्मों में इस सुपरहीरो का किरदार टोबी मैगर और रीबूट सीरीज द अमेजिंग स्पाइडरमैन में एंड्रयू गारफील्ड निभा चुके हैं. गौरतलब है कि मार्वल, सोनी पिक्चर्स तथा निर्माता केवीन फीज और एमी पास्कल द इंम्पॉसिबल, वुल्फ हॉल में हॉलैंड की परफॉर्मेंस और अपकमिंग फिल्म इन द हर्ट ऑफ द सी के शॉट्स से काफी इम्प्रेस हुए और उन्हें स्पाइडरमैन के रोल के लिए सलेक्ट करने का फैसला किया.■

इश्क लड़ाते दिखीं पैरिस हिल्टन

यह नया जोड़ा करीब एक महीने से एक-दूसरे को डेट कर रहा है और दोनों साथ में बहुत खुश हैं.

जानी-मानी सोशलाइट पैरिस हिल्टन इन दिनों वह एक करोड़पति व्यवसायी को डेट कर रही हैं. पैरिस को स्पैनिश आइलैंड फॉरमेंटेरा के पास एक यात्री जहाज में थॉमस ग्रॉस नाम के व्यवसायी के साथ रोमांस करते देखा गया, जो 20 करोड़ डॉलर संपत्ति का मालिक है. एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नया जोड़ा करीब एक महीने से एक-दूसरे को डेट कर रहा है और दोनों साथ में बहुत खुश हैं. दोनों की मुलाकात कान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुई थी और वहीं उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी. पैरिस बेहद रोमांचित हैं कि उन्हें अपने लिए उपयुक्त साथी मिल गया है, जो काफी विनम्र स्वभाव का है. पैरिस को थॉमस का साथ बेहद पंसद है और दोनों साथ में काफी मस्ती कर रहे हैं.■

दीपिका शाही लुक में नजर आएंगी

जानी-मानी फैशन डिजाइनर अंजू मोदी के कंधों पर इस वक्त संजय लीला भंसाली की नई फिल्म बाजीराव मस्तानी के परिधान डिजाइन की जिम्मेदारी है. उनका कहना है कि फिल्म बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण को शाही लुक दिया गया है. अंजू ने कहा कि दीपिका शाही स्टाइल के परिधानों में नजर आएंगी. फिल्म में दीपिका पादुकोण का किरदार मुस्लिम महिला का है, इसलिए हमने उन पर शरारा और कुर्तियां आजमाई हैं. फिल्म में प्रयुक्त पोशाकों के संबंध में उन्होंने कहा कि फिल्म बाजीराव मस्तानी एक विशेष युग से संबंधित है, इसलिए हमने प्राचीन मुगल स्टाइल का अंगरखा और मराठी स्टाइल की नऊवारी साड़ी रखी है, क्योंकि यह मराठा पेशवा से संबंधित कहानी है. अंजू फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया (एफडीसीआई) की संस्थापक सदस्य हैं. उन्होंने भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला राम-लीला से बॉलीवुड में कदम रखा था. बाजीराव मस्तानी 18वीं सदी के मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम (रणवीर सिंह) और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी (दीपिका) की प्रेम कहानी पर आधारित है. इसमें प्रियंका चोपड़ा पेशवा बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई की भूमिका में हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

> अंजू ने कहा कि दीपिका शाही स्टाइल के परिधानों में नजर आएंगी. फिल्म में दीपिका पादुकोण का किरदार मुस्लिम महिला का है, इसलिए हमने उन पर शरारा और कुर्तियां आजमाई हैं.

कंगना ने केतन मेहता की अगली फिल्म साइन की है. ये फिल्म झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित होगी. कंगना भी इस फिल्म में लक्ष्मीबाई का रोल करने के लिए खासी उत्साहित हैं. कंगना ने स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा था, तो जब उनसे इस रोल के लिए संपर्क किया गया, तो वो बेहद उत्साहित थीं. उन्हें केतन की स्क्रिप्ट भी बहुत पसंद आई.

कंगना रानी लक्ष्मीबाई बनेंगी

कंगना रनोट के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं. एक के बाद एक कामयाब फिल्में दे रही कंगना के आगे-पीछे निर्माताओं और निर्देशकों की लाइन लगी हुई है. पिछले दिनों उन्होंने विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून साइन की थी. अब खबर है कि कंगना ने केतन मेहता की अगली फिल्म साइन की है. ये फिल्म झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित होगी. कंगना भी इस फिल्म में लक्ष्मीबाई का रोल करने के लिए खासी उत्साहित हैं. कंगना ने स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा था, तो जब उनसे इस रोल के लिए संपर्क किया गया तो, वो बेहद उत्साहित थी. उन्हें केतन की स्क्रिप्ट भी बहुत पसंद आई. कंगना इस फिल्म के लिए की गई रिसर्च से भी काफी प्रभावित थीं. केतन मेहता ने फिल्म में कंगना को साइन किए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि कंगना को साइन कर लिया गया है. हिन्दी और इंग्लिश में बनने जा रही इस फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू की जाएगी. इस फिल्म के लिए कंगना को तलवारबाजी से लेकर घुड़सवारी तक वो सभी चीजें सीखनी होंगी, जिससे वो झांसी की रानी के किरदार को पूरी तरह निभा सकें. खबर यह भी है कि फिल्म में जनरल ह्यू रोज के रोल के लिए हॉलीवुड स्टार ह्यू ग्रैंट से भी संपर्क किया गया है. जनरल ह्यू रोज ने सेंट्रल इंडियन फील्ड फोर्स की कमांडिंग की थी और 1858 में उन्होंने झांसी में भारत के बागियों से मुकाबला किया था. वो रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के कायल थे.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार -झारखंड

06 जुलाई -12 जुलाई 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

किसकी कुंडली में है राजयोग

इस चुनाव में, यह लगभग तय है, भाजपा बतौर नेता किसी के नाम की घोषणा नहीं करेगी. उसके दल के भीतर के अपने कारण तो हैं ही, बिहार में इस दल के समर्थकों की सामाजिक संरचना भी इसका कारण है. जनता परिवार गठबंधन ने, जिसके नेता नीतीश कुमार घोषित हैं, सूबे में चुनाव पूर्व राजनीतिक माहौल में बड़ी रेखा खींच दी है. भाजपा या एनडीए इसकी काट नहीं खोज पा रहे हैं. फिर भी, चुनावी हवा को भाजपा अपने अनुकूल दिखाने की कोशिश कर रही है. पटना से लेकर दिल्ली तक के नेता इसी लहजे में बात-व्यवहार कर रहे हैं. लिहाज़ा मुख्यमंत्री के दावेदारों की भीड़ बहुत है. पार्टी का संकट है कि नाम सामने आते ही नाराज नेताओं व उनके समर्थकों को नियंत्रित कर पाना कठिन है. छोटे-छोटे पदों को लेकर तोड़-फोड़ और घात-भितरघात आम हो गई है, यह तो मुख्यमंत्री का सवाल है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार मे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में घमासान मचा है. विधानसभा चुनवों में इस राजनीतिक ध्रुव का नेता अर्थात् मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? भाजपा के कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं जिनमें कुछ तो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं. भाजपा के कुछ नेता अपने को भावी नेता (मुख्यमंत्री) के तौर पर पेश करने की जी-तोड़ कोशिश में हैं. सो जातीय आधार पर हो या अन्य किसी तरीके से. भाजपा की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी संकेत नहीं मिलने से हालात भ्रांति ही पैदा करते हैं. इस माहौल को उत्तेजक एनडीए के घटक राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी (रालोसपा) के सुप्रीमो और केन्द्रीय राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने बना दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी सार्वजनिक तौर पर पेश कर दी. इसके साथ ही इस मसले पर भाजपा और एनडीए के सारे अंतर्विरोध खुल कर सामने आ गए. उपेंद्र ने दो टूक शब्दों में कह दिया है: मुख्यमंत्री के सवाल पर एनडीए के सबसे बड़े घटक भाजपा में विवाद होने के कारण कोई नाम तय नहीं हो रहा है, लिहाज़ा मुझे इस पद का उम्मीदवार माना जाना चाहिए.

रालोसपा ने इस मसले पर एक प्रस्ताव भी पारित किया है और उसका मानना है कि कुशवाहा समाज को यह पद दिया जाना चाहिए. उपेन्द्र कुशवाहा की इस दावेदारी पर भाजपा की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. वैसे छोटे-बड़े सभी नेताओं ने इस पर कुछ न कुछ कहा है. पार्टी का पक्ष सामने आता इससे पहले पार्टी के दिग्गज डॉ.सी.पी, ठाकुर ने अपनी इच्छा मीडिया के जरिए जाहिर कर दी: मैं भी इस पद के लिए सक्षम हूं. अतिपिछड़े समुदाय के पुराने नेता डॉ. प्रेम कुमार भला कैसे पीछे रहते. मैं किसी के कम नहीं हूं, पिछले लंबे अर्से से विधायक हूं. इतना ही नहीं, चन्द्रमोहन राय ने कह दिया कि सुशील कुमार मोदी को आगे कर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले दो-ढाई दशकों में पार्टी नेतृत्व ने उन्हें ही प्रमोट किया है. लेकिन वह अपने बयान पर डटे नहीं रह सके, उनके सजातीय नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि इस मसले पर फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को करना है और उनका फैसला ही मान्य होगा. वस्तुत: नेता को लेकर बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी और केन्द्रीय मंत्री अनन्त कुमार ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया और बर्रे की जमात अब पार्टी की शान्ति को लहुलुहान कर चुकी है. इस घमासान में दो बातें खास हैं. एक, भाजपा के जिन नेताओं के नाम इस पद खास हैं, (यह कहना बेहतर होगा कि जो इसके लिए गंभीरता से लगे हैं) वे सभी खामोश हैं. दूसरी बात, लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान अनेक राजनीतिक असहजता के बावजूद चुप हैं, दिल्ली को साधने में लगे हैं. माना जा रहा है कि उपेन्द्र कुशवाहा को लोजपा सुप्रीमो का मौन समर्थन है. वह अपने अनुभव का लाभ उठा रहे हैं.

नेता पद के इस विवाद ने भाजपा- और इस नाते एनडीए- के चुनाव पूर्व राजनीतिक अभियान की दिशा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. बिहार की सत्ता की दहलीज पर खड़ी भाजपा (और एनडीए) के लालू प्रसाद- नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीतिक हमले का सिलसिला एकबारगी धीमा हो गया. भाजपा का विधानसभा क्षेत्रवार सम्मेलन चल रहा है और केन्द्रीय मंत्रियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में भाजपा नेता इस में भाग लेने रोज बिहार आ-जा रहे हैं. अब तक उनके राजनीतिक बयान बिहार में नीतीश कुमार के जंगलराज-2 के इर्द-गिर्द हुआ करते थे, पर अब हालात बदल गए हैं. एनडीए में नेता (मुख्यमंत्री) को लेकर उठा-पटक तेज होती जा रही है. भाजपा नेताओं के राजनीतिक बयान के अधिकांश सफाई देने में गुजर जाते हैं. वे कहते हैं एनडीए में नेता पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, सब विरोधियों की साजिश है. यह राजनीतिक ध्रुव अब नीतीश कुमार के जंगलराज-2 के मुहा-वरे का जितना भी वाचन करे, उसका अपना घर बंटा दिख रहा है. यह एक सच्चाई है कि चुनाव अभियान के औपचारिक शुरुआत के पहले ही नेता पद को लेकर नीतीश-लालू के जाल में भाजपा फंस गई है.

नीतीश कुमार के जनता परिवार गठबंधन के नेता चुने जाने का बाद भाजपा पर दबाव बढ़ गया था. फिर लालू प्रसाद ने सवाल दागा: बताओ, तुम्हार वंश कौन है या भाजाप निर्वंश है? और इसके बाद भाजपा फंसती चली गई, घर बंटता दिखने लगा. इस लिहाज़ से भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को लालू-नीतीश की जोड़ी ने गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया. जंगलराज के बदले एकता की रक्षा और उसकी ठोस और प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति भाजपा (एनडीए) की सबसे बड़ी जरूरत हो गई है. घर के इस तरह बंटे होने की भाजपा (और एनडीए) के समर्थक सामाजिक समूहों में चर्चा नीचे तक जा रही है. हालांकि इस उछल-कूद से, जैसा भाजपा के कुछ बड़े नेता मानते हैं, पार्टी पर राजनीतिक कुप्रभावों का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी, पर इस विवाद को बल मिलने से संकट तो निश्चय ही बढ़ेगा, इसके समर्थक सामाजिक समूहों के बीच भ्रांति बढ़ेगी. ऐसा भाजपा के नेताओं का भी मानना है.

वस्तुत: बिहार में विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भाजपा को कई पेंच को खोलना होगा. बिहार के नीतीश-लालू विरोधी इस राजनीतिक ध्रुव में कई परस्पर विरोधी राजनीतिक व्यक्तित्वों का मिलन हो रहा है. सत्ता की चाहत में पुराने धुर विरोधी नेता एक जगह आ तो रहे हैं, पर उन्हें यह भय बराबर सता रहा है कि उनके प्रतिद्वंद्वी को कहीं तरजीह न मिल जाए. उपेन्द्र कुशवाहा के हाल के दिनों के बयान अनायास नहीं हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के एनडीए में शामिल होने के साथ इस गठबंधन को एक बड़ा दलित नेता तो मिल ही रहा है, कुशवाहा समुदाय के दिग्गज शकुनी चौधरी भी इसे मिलेंगे, पर शकुनी चौधरी की मौजूदगी उपेन्द्र कुशवाहा को रास नहीं आ रही है. अब भाजपा के लिए इन दोनों में संतुलन कायम करना धर्मसंकट जैसा है. हाल के दशकों में देखा गया है कि कुशवाहा समाज के दो नेता बहुधा एक राजनीतिक गठबंधन में नहीं होते हैं. इस बार दो नेता एक साथ आ रहे हैं. इससे संकट गहरा गए तो किसे राजनीतिक लाभ मिलेगा, यह बगैर कहे ही समझा जा सकता है. इसी तरह एक दूसरा मसला है रामविलास पासवान और जीतनराम मांझी का. भाजपा को इस चुनाव में यह सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ है कि बिहार का दलित नेतृत्व पूरी तरह उसके साथ है. रामविलास पासवान तो गत संसदीय चुनाव से ही उसके साथ हैं, जीतनराम मांझी भी एनडीए में शामिल हो गए हैं. इन दोनों के साथ होने से पूरे के पूरे दलित वोट पर उसका सहज दावा बनता है, पर नीतीश कुमार के कारण सत्ता से बेदखल जीतनराम मांझी के प्रति बिहार के अतिपिछड़े सामाजिक समुदायों में सहानुभूति बढ़ी है. ये समुदाय गत विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ हैं, पर आज इनमें नीतीश को लेकर द्वेष-भाव ज्यादा है. इसके बरअक्स वे मांझी के साथ दिखते हैं. सो, मांझी का सामाजिक समर्थक आधार रामविलास पासवान की तुलना मे बड़ा दिखता है. लिहाज़ा भाजपा नेतृत्व मे मांझी को लेकर उत्साह का भाव अधिक है. ऐसे में मांझी से रामविलास पासवान खुद को असुरक्षित पा रहे हैं. इस और ऐसी असहजता की अभिव्यक्ति के रास्ते तलाशे जा रहे हैं. संभव है, आनेवाले दिनों में ऐसी राजनीतिक उछल-कूद के और नमूने मिले.

इस चुनाव में, यह लगभग तय है, भाजपा बतौर नेता किसी के नाम की घोषणा नहीं करेगी. उसके दल के भीतर के अपने कारण तो हैं ही, बिहार में इस दल के समर्थकों की सामाजिक संरचना भी. जनता परिवार गठबंधन, जिसके नेता नीतीश कुमार घोषित हैं, सूबे में चुनाव पूर्व राजनीतिक माहौल में बड़ी रेखा खींच दी है. भाजपा या एनडीए इसकी काट नहीं खोज पा रही है. फिर भी, चुनावी हवा को भाजपा अपने अनुकूल दिखाने की कोशिश कर रही है. पटना से लेकर दिल्ली तक के नेता इसी लहजे में बात-व्यवहार कर रहे हैं. लिहाज़ा मुख्यमंत्री के दावेदारों की भीड़ बहुत है. पार्टी का संकट है कि नाम सामने आते ही नाराज नेताओं व उनके समर्थकों को नियंत्रित कर पाना कठिन है. छोटे-छोटे पदों को लेकर तोड़-फोड़ और घात-भीतरघात आम हो गई है, यह तो मुख्यमंत्री का सवाल है. नाम सामने कर देने के बाद चुनाव में व्यापक पैमाने पर भीतरगात को नियंत्रित कर पाना असंभव जैसा हो जाएगा. लिहाजा जीती हुई बाजी के हाथ से निकल जाने की हरसूरत संभावना है, तो क्यों नहीं नरेन्द्र मोदी को मैदान में रखा जाए! नरेन्द्र मोदी के बिहार के चुनाव मैदान में पुतला बना कर रखने का एक और बड़ा कारण है. भाजपा के आंतिरक सूत्रों के अनुसार नेता पद के लिए जिन नामों पर भाजपा नेतृत्व गंभीर है, वे पिछले कई दशकों से भाजपा की राजनीति में सक्रिय रहे हैं. पर, उनके सामाजिक समूह को लेकर बहुत उत्साह से कुछ कहना कठिन है. हालांकि वे भाजपा की राजनीति के अंग रहे, पर मंडल की राजनीति के दौर में उनकी निष्ठा लालू प्रसाद से अधिक दिख रही थी. एनडीए की सत्ता में आने के बाद वे सामाजिक समूह फिर तेजी से भाजपा के साथ आए. इसके समानान्तर, बिहार की ऊंची दबंग जातियों के समूहों ने सामाजिक न्याय की राजनीति के नायकों से लोहा लेकर भाजपा का साथ दिया. संयोग से इन सामाजिक समूहों की वक़त अब भाजपा में घट गई है और पार्टी नेतृत्व, वह दिल्ली का हो या पटना का, मंडलवादी राजनीतिक को आगे बढ़ा रहा है. ऐसे में, पार्टी का संकट है कि नेता (मुख्यमंत्री) के नाम की वह घोषणा कैसे करे! मतदान केन्द्रों पर एनडीए को वोटों की रक्षा में तैनात मतदाताओं की सामाजिक संरचना के कारण नेता के नाम की सार्वजनिक घोषणा नहीं की जा सकती है.

बिहार में जनता परिवार के गठबंधन और उसके नेता नीतीश कुमार के लिए खुश होने के कई कारण हैं-चुनाव पूर्व के राजनीतिक माहौल की लगाम उनके हाथ आती दिख रही है. वह अपने राजनीतिक अभियानों से गठबंधन की लकीर को निरन्तर ज्यादा सुर्ख और मोटा बनाने कोशिश कर रहे हैं. बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी और केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार ने साफ कर दिया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने जिस तरह का सुशासन (गवर्नेंस) और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन दिया है, विधानसभा का चुनाव उन्हीं के आधार पर लड़ा जाएगा. अनन्त कुमार और उनके साथ बिहार भाजपा के नेता शब्द में यह कहने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार के सामने नरेन्द्र मोदी होंगे, लेकिन यह तो बाद की बात है. अभी तो नीतीश-लालू की जोड़ी ने भाजपा (एनडीए) के लिए जिस राजनीतिक एजंडे को पेश कर दिया है, वह उसी में उलझ गई है, नेता को लेकर विवाद को शांत करने में लगी है. इस लिहाज़ से नीतीश कुमार एक बार फिर आगे निकल गए दिख रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र
चुनावी हलचल

जनसंपर्क में सुजीत यादव

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे ही राजनीतिक दलों और नेताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है. ऐसा ही है कुछ मंजर फतुहा विधानसभा क्षेत्र में दिख रहा है. मौजूदा विधायक रामानंद यादव पर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. जिस तरह से युवा नेता सुजीत कुमार यादव लोगों के करीबी होते जा रहे हैं इससे काफी कुछ बदला-बदला सा दिख रहा है. एक बात तो तय है की फतुहा विधानसभा सीट का चुनाव रोमांचक होने वाला है. फतुहा विधानसभा क्षेत्र के दौरे में सुजीत लगातार चल रहे हैं और जनसम्पर्क कर रहे हैं. सबलपुर पंचायत, पूर्णडीह पंचायत, मौजियापुर पंचायत (मौजियापुर पंचायत जो वर्तमान विधायक का गृह गांव है), जल्ला सोनाव पंचायत, मौली पंचायत, फतुहा नगर परिषद में अभी तक दौरा कर चुके सुजीत लोगों का खूब भरोसा जीत रहे हैं. इस क्षेत्र के समाजसेवी नेता पूरी तरह से सुजीत के साथ में दिख रहे हैं. पूर्णडीह पंचायत के मुखदेव सिंह और अशोक सिंह यादव सुजीत के साथ में है. इनके आलावा सबलपुर पंचायत के श्याम बाबू यादव सुजीत के स्टार प्रचारक के तौर पर घर घर जाकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं. श्याम बाबू यादव के बारे में कहा जाता है कि वे यादव वोटर के मार्गदर्शक है.

– रजनीकांत पाण्डेय

नीतीश-लालू से ऊब चुकी जनता

बायसी महासम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वरुण कुमार सिंह ने जनता को सचेत किया कि लालू-और नीतीश कुमार बिहार में हो रहे विकास को अब रोकना चाहते हैं. एनडीए गठबंधन के द्वारा किए गए विकास को अब लालू जी रोड़ा लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कहा भी गया है कि संगत से गुण होत हैं संगत से गुण जात और जंगलराज के साथ मिलकर कहेंगे तो गुण तो आयेगा ही. दोनों नेता जाति-पाति की राजनीति के पुरोधा हैं. उन्होंने आगे आम जनता की मानसिकता को भी बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार के शासन को जनता पहचान चुकी है. भाजपा के सहयोग से सुशासन का पाठ पढ़ाने वाले अब जंगलराज वाला सुशासन लायेंगें. जनता लालू और नीतीश के शासन को देख चुकी है अब एनडीए के सुशासन को देखेगी. बायसी सम्मेलन में भारी भीड़ के साथ विशिष्ट अतिथि शाहनवाज हुसैन और प्रसिद्ध लोक गायक सुनील छैला बिहारी भी उपस्थित थे.■

– भारती

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

समस्या लिवर की और आप
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है लिवर। इसलिए कुछ भी खाने और पीने से पहले हमें एक बार सोचना जरूर चाहिए कि वह हमारे लिवर के लिए सही है या नहीं। हम बिना सोंचे-समझे कुछ भी खा लेते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं होता। खास तौर पर जंक फूड, फैटी भोजन, अधिक मसला, धूम्रपान, एल्कोहॉल का सेवन आदि न करें क्योंकि यह लिवर को कमजोर करती है। उपरोक्त बातें बतायी बांका के अनुभवी चिकित्सक डॉ मदन कुमार पाठक ने जो एम.बी.बी.एस है। डॉ मदन बताते है कि जंक फूड लिवर के लिए खतरनाक होते हैं। इसीलिए हमेशा ताजा, सही और स्वास्थ्य से भरपूर पौष्टिक खाने का ही प्रयोग करा चाहिए बाहर के खाने में प्रयोग हुआ तेल और मसाले में मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिवर व हृदय दोनों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसके आलावा धूम्रपान, एल्कोहॉल का सेवन से भी लिवर पर खतरा अधिक होता है। सिगरेट में मौजूद तंबाकू में टॉक्सिक केमिकल होते हैं। जिससे वह असल कार्य करने में देरी करता है। ये अशुद्ध केमिकल्स शरीर से बाहर नहीं निकल पाते व देर तक शरीर में रहने से नुकसान पहुंचाते हैं। एल्कोहॉल के सेवन पर डॉ बताते है की एल्कोहॉल लिवर के टॉक्सिक केमिकल्स को कमजोर करने में लग जाता है, तथा फैटी लिवर का कारण बनता है। लिवर जब शरीर में होने वाले एल्कोहॉल के नुकसान को कम करने में लग जाता है तो इससे बनने वाले केमिकल्स उसकी कोशिकाओं को कमजोर कर देते है। ज्यादा शराब के सेवन से धीरे-धीरे लिवर अपना काम करना बंद कर देता है। उन्होंने बताया की लिवर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए खानपान की आदत व जीवनशैली को सुधारना जरूरी है। हमे जंक फूड, फैटी भोजन, अधिक मसला, धूम्रपान, एल्कोहॉल का सेवन को नजर अंदाज करना चाहिए। हम जब भी भोजन करें तो फ्रेश और ताजा ही खाना खाएं तथा तरल पदार्थ का सेवन अधिक मात्रा में करें। ■ रजनीकान्त पाण्डेय
डॉ. एम.के. पाठक MBBS, BANKA
Carbo - XT Drops Susp. Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops. Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp. Silymarin, vitamin B Complex Calcium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml) Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp. Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma

पूर्णिया-किशनगंज-अररिया क्षेत्र

पुराने दिग्गजों में मचा है घमासान

2009 के चुनाव में जहां तस्लीमुद्दीन ने राजद के उम्मीदवार नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह का साथ दिया था वहीं पप्पू यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से दिलीप जयसवाल का साथ दिया था.

नीरज सिंह

जहां 2015 का विधान सभा चुनाव का समय नजदीक आते देख विभिन्न दलों के नेताओं के पाला बदलने एवं गठबंधन का खेल चालू हो गया है वहीं दूसरी तरफ विभिन्न दलों के नेता बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर पूर्णिया-किशनगंज-अररिया क्षेत्र को विधानसभा चुनाव का लिटमस परीक्षण साबित करने में जुटे हुए हैं. गठबंधन के कारण टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं का घात-प्रतिघात का खेल भी चालू हो गया है. मालूम हो कि 2009 के चुनाव में वर्तमान विधान पार्षद सह भाजपा के कोषाध्यक्ष व कद्दावर नेता दिलीप जायसवाल का मुख्य मुकाबला अररिया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष आफताब आलम उर्फ पप्पू अजीम के साथ हुआ था जो पूर्व मंत्री अजीमुद्दीन के पुत्र हैं. इससे पूर्व 2003 के चुनाव में पूर्व मंत्री अजीमुद्दीन ने पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं वर्तमान अररिया के सांसद तस्लीमुद्दीन के खासमखास राजद समर्थित उम्मीदवार त्रिलोकचन्द जैन को हराया था. त्रिलोकचंद जैन वर्तमान में भाजपा में हैं. 2009 के चुनाव में जहां तस्लीमुद्दीन ने राजद के उम्मीदवार नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह काा साथ दिया था वहीं पप्पू यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से दिलीप जयसवाल का साथ दिया था. अररिया की राजनीति में अजीमुद्दीन और तस्लीमुद्दीन के परिवारों के बीच पुस्तैनी राजनीतिक प्रतिदंद्धिता चलती है. वहीं राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव एनडीए के करीब आ रहे हैं. लेकिन वर्तमान में राजद, जदयू एवं कांग्रेस के बीच गठबंधन होने से सीमांचल का राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है और पूर्णिया-अररिया-किशनगंज विधान परिषद सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय होने की प्रबल संभावना है. अबतक भाजपा की तरफ से दिलीप जायसवाल, कांग्रेस, राजद, जदयू गठबंधन की तरफ से अरसद इमाम एवं बतौर निर्दलीय मो. अजीमुद्दीन चुनावी मैदान में आ चुके हैं. वहीं नामांकन के आखिरी तारीख तक दो-तीन निर्दलीय प्रत्याशियों के बढ़ने की प्रबल संभावना है वैसे रुस्तम खान, नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह जैसे तस्लीम समर्थक नेता राजद से तो अजय झा जदयू से टिकट की आस लगाये हुए थे लेकिन ऐन मौके पर सीट कांग्रेस के कोटे में चले जाने से ऐसे नेता बगावती मुद्रा में दिख रहे हैं. जहां तक डॉ. दिलीप जायसवाल की बात की जाय तो क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों में उनकी गहरी पैठ है. दोनों सम्प्रदाय के पंचायत प्रतिनिधियों के वे चहेते रहे हैं. दिलीप जायसवाल हमेशा पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों एवं मांगों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर प्रताड़ित होने वाले जनप्रतिनिधियों का साथ धरना प्रदर्शन एवं प्रशासनिक स्तर पर मांग के माध्यम से देते रहे हैं. दूसरी तरफ पूर्व सांसद व कद्दावार नेता उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह लोकसभा में अपनी हार से नीतीश से खार खाये हुए हैं. पप्पू सिंह ऐसा राजनीतिक समीकरण गढ़ने में जुटे हुए हैं जिसके तहत उनकी योजना सीमांचल में विधान पार्षद तो क्या विधान सभा में राजद, जदयू, कांग्रेस गठबंधन का खाता तक खुलने देने की नहीं है. इसी रणनीति के तहत धमदाहा के पूर्व राजद विधायक दिलीप यादव भाजपा में शामिल हुए. वहीं पप्पू यादव भी लालू एवं नीतीश पर कटाक्ष कर रहे हैं. दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों में पैठ बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का उदय सिंह एवं दिलीप जायसवाल के साथ सीमांचल का सघन दौरा हुआ. बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित दालकोला में भाजपा नेता अब्दुल जलील के आवास पर मुख्तार अब्बास नकवी उदय सिंह एवं दिलीप जयसवाल की उपस्थिति में अल्पसंख्यकों का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ. माना जाता है कि बंगाल भाजपा किसान मोर्चा के अब्दुल जलील करण दिघी विधान सभा सीट से भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार हैं. अब्दुल जलील शेरशाहवादी बिरादरी के आते हैं जिनकी खास पकड़ बिहार-बंगाल के सीमांचल में बसे अपने बिरादरी के लोगों पर है. अब्दुल जलील, दिलीप जयसवाल के विश्वासपात्र हैं. विधान पार्षद के चुनाव को लेकर दिलीप जयसवाल का कहना है कि इंसान का मजहब जमात से ऊपर उठकर इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है. मैंने पंचायत जनप्रतिनिधियों के मांगों को जिला से लेकर राज्य मुख्यालय तक सरकार के सामने रखा. प्रशासनिक प्रताड़ना में मैंने पंचायत प्रतिनिधियों को साथ लेकर जन आंदोलन किया, वहीं मेरे दरवाजे में प्रतिनिधियों के साथ आमलोगों के लिए खुले रहे. केन्द्र में भाजपा की सरकार के चलते विश्व में भारत की एक अलग छवि बनी है अतः राज्य में भाजपा को मौका मिलना चाहिए. निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मो. अजीमुद्दीन का कहना है कि 40 सालों तक वे यूथ कांग्रेस में थे इसके बाद समाजवादी पार्टी के जिला स्तर के कार्यकतर्स रहे. उनका मानना है भाजपा का रवैया दलित, मुस्लिम ईसाई विरोधी रहा है. दिलीप जयसवाल और कांग्रेस के अरशद इमाम हाई प्रोफाईल वाले नेता हैं. किसी को भी उनसे मिलना आसान नहीं है जबकि मैं सहज उपलब्ध होने वाला नेता हूं. डॉ. अरशद इमाम अब तक किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं. उन्होंने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से सिर्फ जनता का दोहन किया है. कांग्रेस उम्मीदवार अरशाद इमाम सीमांचल के शिक्षा जगत के चर्चित चेहरे हैं. उनका कहना है कि विकास मेरा मुख्य मुद्दा है.■

feedback@chauthiduniya.com

चकाई में अभी धुंधली है राजनीतिक तस्वीर

तरुण मिश्रा feedback@chauthiduniya.com

बिहार विधान सभा चुनाव की आहट के साथ ही चकाई में उठा पटक की राजनीति शुरू हो गई है. लम्बे समय से पार्टी में काम करने वाले नेताओं ने टिकट की आस में पटना और दिल्ली की दौड़ शुरू कर दी है. इन सब बातों के बीच बनते-बिगड़ते राजनीतिक गठबंधन ने कई दलों के नेताओं की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया. एक तरफ जहां भाजपा,जदयू, राजद एवं लोजपा के स्थानीय नेता टिकट की आस में अन्दर ही अन्दर चुनाव की तैयारी में लगे थे वहीं जदयू के राजद से गठबंधन ने एवं भाजपा-लोजपा गठबंधन के साथ हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा के आ जाने की घोषणा ने चकाई विधानसभा के पूरे गणित को ही बदल कर रख दिया. चकाई विधानसभा में मौजूदा समय में सुमित सिंह विधायक हैं जो नरेन्द्र सिंह के छोटे पुत्र हैं. सुमित जदयू से निकलकर हम में आए हैं. ऐसे में अगर गठबंधन मुर्त रूप लेता है तो भाजपा-लोजपा और हम के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वर्तमान विधायक सुमित सिंह का टिकट पक्का होता दिखाई पड़ रहा है. इस गठबंधन के पहले चकाई सीट पर एनडीए की तरफ से भाजपा एवं लोजपा दोनों अपना-अपना दावा ठोंक रहे थे. वहीं भाजपा के हम के साथ जाने की घोषणा ने लोजपा एवं भाजपा के नेताओं को अन्दर ही अन्दर झकझोर कर रख दिया है. एक तरफ जहां दिवंगत विधायक फाल्गुनी यादव के निधन के बाद उपजी संवेदना की नैया पर सवार होकर उनकी पत्नी चुनावी सागर को पार करने की उम्मीद में थीं वहीं लोजपा के विजय सिंह पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने के कारण इस सीट पर टिकट का दावा पक्का समझ रहे थे लेकिन इन सब बातों के बीच फिल्मी अंदाज में एनडीए में मांझी के प्रवेश ने सारे समीकरण को ही बदल कर रख दिया है.बात अगर राजद एवं जदयू गठबंधन की कि जाय तो वर्तमान विधायक के जदयू से हम में चले जाने के कारण जदयू एवं राजद ने अपने अपने दलों से नेताओं को उतारने का प्रयास तेज कर दिया है लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यहां सीट जदयू के खाते में जाने की संभावना ज्यादा है. दोनों ही दलों का कोई निर्विवाद नेता नहीं होने के कारण कई लोगों की महत्वकांक्षा हिचकोले लेने लगी है. ऐसे में इन दलों में भी सर्वमान्य नेता चुनना आसान नहीं होगा. वहीं कांग्रेस का मजबूत संगठन नहीं होने के कारण कांग्रेस का टिकट का दावा इस सीट पर कमजोर ही लगता है.

वहीं इन दो प्रमुख गठबंधन की बात छोड दें तो पिछले चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले बसपा के पृथ्वीराज हेम्ब्रम की क्या रणनीति होगी यह अभी पर्दे के पीछे ही है. वहीं राकपा के नेपाली सिंह की गतिविधि भी इस इलाके में एकाएक तेज हो गई है. वह भी इलाके में सघन जनसंपर्क अभियान में लगे हैं. वे भी चकाई की तस्वीर बदलने का दावा करते नजर आ रहे हैं. वे कहते हैं कि इससे पहले जनता की परेशानियों पर काम नहीं किया गया है. वे क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे.■

एक नाम के दो प्रत्याशी से चुनाव हुआ दिलचस्प

मनोरमा देवी | अनुज सिंह | मनोरमा देवी | रिंकू यादव | रीता वर्णवाल

सुनील सौरभ

बिहार विधान परिषद के गया-जहानाबाद-अरवल स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से एक ही नाम की दो महिला प्रत्याशी होने से चुनाव दिलचस्प हो गया है. जदयू-राजद-कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी है, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी मनोरमा देवी नाम की एक महिला प्रत्याशी होने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. भाकपा माले की प्रत्याशी रीता वर्णवाल तथा निर्दलीय मनोरमा देवी को छोड़कर तीन अन्य प्रत्याशी काफी सम्पन्न है. निर्वतमान विधान पार्षद अनुज कुमार सिंह इस बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में हैं, जबकि पिछली बार जदयू-भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे. जदयू की प्रत्याशी पूर्व विधान-पार्षद मनोरमा देवी पिछली बार राजद की प्रत्याशी थी. निर्दलीय प्रत्याशी कुमार नागेन्द्र उर्फ रिंकू यादव राजद के बेलागज विधायक डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव के रिश्तेदार है जबकि राल-ोसपा के विधान पार्षद डॉ. संजीव श्याम सिंह इनके बिजनेस पार्टनर हैं. लेकिन बताते हैं कि राजद विधायक डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी मनोरमा देवी के साथ हैं तो रालोसपा विधान पार्षद डॉ. सजीव श्याम सिंह गठबंधन धर्म के नाते भाजपा प्रत्याशी के साथ हैं. ऐसे में यहां विधान परिषद का चुनाव दिलचस्पी का कारण बन गया है. अंतिम समय में मनोरमा देवी नाम की एक महिला का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप मे चुनाव मैदान में उतरना भी गया की प्रसिद्ध बैठकबाजी वाली राजनीति का हिस्सा बताया जा रहा है. जिससे कि एक ही तरह के नाम से मतदान करने वाले मतदाता भ्रम में पड़े. जदयू-प्रत्याशी मनोरमा देवी विधान पार्षद रह चुकी हैं. यह गया जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके बिन्देश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिन्दी यादव की पत्नी है. जबकि भाजपा प्रत्याशी अनुज कुमार सिंह गया जिला परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं. यहां से पिछले चुनाव में उन्होंने जदयू-भाजपा प्रत्याशी के रूप में राजद प्रत्याशी मनोरमा देवी को हराया था. भाकपा माले की प्रत्याशी रीता वर्णवाल अपने पति निरंजन कुमार के साथ भाकपा माले की राजनीति में सक्रिय हैं. नामांकन के बाद सभी प्रत्याशी अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के लिए रणनीति में लग गये हैं. गया-जहानाबाद-अरवल के 8108 मतदाता कुल 36 केन्द्रों पर अपने मत देगें. कहने के लिए यह चुनाव बहुत ही साधारण है. लेकिन जीत के लिए करोड़ों का वारा-न्यारा करना पड़ता है. जो प्रत्याशी चार हजार मतदाता का प्रमाण पत्र अपने हाथ में ले लेंगे, उनकी जीत निश्चित हो जाएगी. इस कार्य के लिए सक्रिय होने वाले लोगो को भी वोट एकजुट करने का पुरस्कार देने की परंपरा है. दलीय आधार पर यह चुनाव होता जरूर है, लेकिन मजबूत अर्थिक स्थिति वाले प्रत्याशी ही सफलता प्राप्त कर पाते है, इन दिनों तीन जिलों की गलियों-चौराहों पर मतदाताओं की कीमत आंकी जा रही है. इस चुनाव मे एक ही नाम की दो प्रत्याशी होने से लोगों में की नजर इस बात पर है कि किसने निर्दलीय प्रत्याशी मनोरमा देवी का नामांकन कराया और किस मकसद से? सभी प्रत्याशी एक-एक मत के लिए, गांवों की गलियों की खाक छान रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

जीत की हैट्रिक या परिवर्तन की बयार

कुमार विनोद/संजय कुमार

इंद्रकांत झा | सुनील कुमार सिंह | यदुवीर प्रसाद

आगामी विधान परिषद चुनाव के नामांकन का सिलसिला खत्म हो गया है और 7 जुलाई को वोट डाले जाने हैं तो चुनावी मैदान में सियासत के दावेदार जोर आजमाइश कर रहे हैं. मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है.

प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कायम होने के बाद सर्वप्रथम दरभंगा में आरजेडी प्रत्याशी मिश्रीलाल यादव त्रिकोणीय मुकाबले में विजयी हुए थे. इसके बाद भी इसी प्रत्याशी को सफलता मिली. अब निवर्तमान एमएलसी मिश्रीलाल यादव अपनी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राजद और जदयू गठबंधन को अपवित्र सम्बंध कहने वाले बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह इस बार परिवर्तन की बयार बहाने के तैयार हैं. अब जबकि आगामी विधान परिषद चुनाव के नामांकन का सिलसिला खत्म हो गया है और 7 जुलाई को वोट डाले जाने हैं तो चुनावी मैदान में सियासत के दावेदार जोर आजमाइश कर रहे हैं. मुख्य मुकाबला इन्ही दोनों के बीच माना जा रहा है. मगर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुवीर कुशवाहा के बगावती तेवर ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह की परेशानी को बढ़ा दिया है. वैसे कुल मिलाकर 10 प्रत्याशियों के मैदान में आ जाने से निर्दलीय प्रत्याशी ने मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया. राजद के मिश्री लाल यादव जो कि पिछले लगातार 12 वर्षों से विधान पार्षद के रूप में स्थापित जनप्रतिनिधियों का नेतृत्व किया है उनसे मतदाता 12 वर्ष का हिसाब भी मांग रहे हैं, वहीं राजद, जदयू एवं कांग्रेस का एक खेमा उनकी उम्मीदवारी पर प्रश्न चिन्ह लगाकर नाराज चल रहा है. मिश्री लाल यादव, विधान पार्षद से पहले मुखिया, राजद के जिला अध्यक्ष एवं एक अच्छे अधिकवक्ता भी रहे हैं. विधान पार्षद के अभियंता पुत्र धीरज यादव की कारगुजारी के कारण कई बार उन्हें अपमानित भी होना पड़ा था, तब पुत्र मोह के कारण पुत्र को राजनीति में अपने साथ करके राजनीतिक वंशवाद का परिचय प्रारंभ किया. प्रखण्डों में जनप्रतिनिधि भवन, एवं कुछ वार्ड सदस्यों को चापाकल देकर उन्होंने स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति व वार्ड सदस्यों को लुभाने का काम किया है. मगर चुनावी पंडितों का मानना है कि इस बार अगर सब कुछ वर्तमान जैसा रहा तो परिवर्तन निश्चित होगा. वैसे चुनाव में नोटों का खेल सर्वव्यापी है जिसका असर यहां भी देखा जा सकता है. उनके विरोधियों ने मिश्री लाल यादव पर आरोप लगाने शुरू किया है कि अपने गांव में जिस सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया उसमें एसी लगा कर अपना आराम कक्ष बनवाया है. अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पुत्री रेखा कुमारी को स्कूल में नियुक्त करवाया. दूसरी तरफ सुनिल कुमार सिंह का भी राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है. 2001 में बिरौल पंचायत के मुखिया फिर 2006 से लगातार बिरौल प्रखण्ड के उपप्रमुख रहे हैं. वहीं युवा निर्दलीय प्रत्याशी यदुवीर प्रसाद कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से बगावत कर अपने आप को चुनाव में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि यह पार्टी विरोधी कार्य नहीं है, क्योंकि पार्टी ने कहीं भी इसका विरोध नहीं किया है. उनको आशा है कि वोटर जात-पात से उठकर वोट करेंगे. इस चुनाव में कुछ निर्दलीय प्रत्याशी वोट कटवा के रूप में अपने को स्थापित करेंगे.

निर्दलीय प्रत्याशी इन्द्र भूषण झा एक मजबूत व्यापारी घराने से आते हैं. अब देखना होगा राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा यह नहीं कहा जा सकता ऐसी स्थिति में अब यह देखना है कि मिश्री लाल यादव हैट्रिक लगा पाते है या परिवर्तन के बयार में नये सदस्य को विधान परिषद का ताज मिलता है.■

feedback@chauthiduniya.com

बखरी में जोर आजमाइश शुरू

सुरेश चौहान

बेगूसराय की बखरी विधान सभा सीट आरक्षित है. बखरी विधानसभा क्षेत्र वामपंथ का गढ़ माना जाता है. इस विधान सभा सीट पर सर्वाधिक बार भाकपा का कब्जा रहा है, गत विधान सभा चुनाव में भाजपा-जदयू गठबंधन में यह सीट भाजपा को मिली थी. भाजपा ने रामानन्द राम को चुनाव मैदान में उतारा था, भाजपा-जदयू की सम्मिलित ताकत के बल पर रामानन्द राम की जीत हुई थी. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का समीकरण बदल चुका है, भाजपा के साथ लोजपा एवं रालोसपा का गठबंधन हुआ है, दूसरी ओर जदयू का राजद कांग्रेस एवं राकांपा के साथ गठबंधन हुआ है. वहीं भाकपा, माकपा एवं भाकपा (माले) पूर्व की भांति एक साथ हैं.

अनिल भारती | गौतम सदा | कैलाश सदा | रामानंद राम | रामशंकर पासवान | रामविनोद पासवान | सूर्य कांत पासवान

भाजपा एवं जदयू दोनों का समीकरण बदला है. गत विधान सभा चुनाव में जहां दोनों साथ थे, अगामी चुनाव में दोनों एक दूसरे के विरोध में चुनावी मैदान में उतरेंगे. वर्तमान विधायक पर पिछले दिनों पार्टी की बखरी मंडल की बैठक में सदस्यों ने कई आरोप लगाए. सदस्यों ने सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया. इस पारित प्रस्ताव की प्रति पार्टी के जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय संगठन को भेज दिया गया, ऐसी परिस्थिति में यदि राजग यह सीट भाजपा को देती है तो रामानन्द राम के अलावा अनिल भारती एवं रामशंकर पासवान प्रत्याशी के प्रबल दावेदार होंगे. अनिल भारती भाजपा के ग्रासरूट से जुड़े निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्त्ता हैं. वे भाजपा के जिला महामंत्री एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं. रामशंकर कर्मठ कार्यकर्त्ता एवं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं. यदि राजग यह सीट लोजपा को देती है तो राम विनोद पासवान एकमात्र प्रबल दावेदार होंगे. राम विनोद पासवान बखरी विधान सभा सीट से भाकपा के विधायक रह चुके हैं, सम्प्रति वे भाकपा से नाता तोड़कर लोजपा का दामन थाम चुके हैं.

गत विधान सभा चुनाव के बाद भाकपा का जनाधार बढ़ा है, यों भी भाकपा सर्वहारा की पार्टी मानी जाती है. गठबंघन द्वारा अगामी विधान सभा चुनाव में भाकपा के सूर्यकान्त पासवान को प्रत्याशी बनाना लगभग तय है. जदयू-राजद-कांगेस-राकांपा गठबंधन सीट यदि कांग्रेस को देता है तो पूर्व विधान सभा प्रत्याशी गौतम सदा, राम स्वरूप पासवान एवं लखन पासवान प्रबल दावेदार होंगे. गौतम सदा गत विधान सभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, राम स्वरूप पासवान एवं लखन पासवान पुराने निष्ठावान कांग्रेसी हैं और पार्टी संगठन के कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं. यदि यह सीट राजद को दी जाती है तो कैलाश सदा प्रमुख दावेदार होंगे. कैलाश सदा राजद के महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र
चुनावी हलचल

हमारी जीत तय

रहुई प्रखण्ड के एक निजी विद्यालय के प्रांगण में जदयू राजद कांग्रेस व एनसीपी गठबंधन का सम्मेलन बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव ई. सुनिल कुमार के अगुआई में व ठाकुर श्याम नंदन सिंह की अध्यक्षता में किया गया. इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार, राजद की पूर्व प्रत्याशी आफरीन सुल्ताना, नदीम जफर गुलरेज, एमएलसी हीरा बिन्द, जिला परिषद सदस्य अस्थामा कंचन देवी,प्रमुख नीतीश चौधरी, उपप्रमुख अशोक प्रसाद,रामानंद प्रसाद,नीरज भान कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस अवसर पर नालंदा के सांसद कौशलेन्द्र कुमार ने कहा कि आज नीतीश कुमार जी की चर्चा आज बिहार ही नही पूरे देश में विकास पुरुष के रूप मे जाने जाते है. इस चुनाव मे चुने हुए त्रिस्तरिय पंचायत प्रतिनिधि ही वोटर होते हैं. सभी प्रतिनिधि समझदार व जागरूक है. रीना जी एक सामाजिक व साफ छवि की उम्मीदवार हैं.■

– कुमुद रंजन

जीत सुनिश्चित होने का दावा

एमएलसी चुनाव में नामांकन करने के साथ ही रालोसपा प्रत्याशी अभिषेक वर्मा अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा ठोंक रहे है. साथ ही जनप्रतिनिधियों से संबंधित समस्या को जानने के लिए क्षेत्र में तूफानी दौरे पर है. भागलपुर-बांका एमएलसी चुनाव में जहां वर्तमान एमएलसी मनोज यादव जदयू से, संजय यादव तथा पूर्व सांसद चुनचुन यादव के पुत्र संजय यादव मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष निर्दलीय से अपनी अपनी ताकत आजमाने में लगे है. हालांकि चुनाव इस बार दिलचस्प होने का अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि एक ओर जहां मनोज यादव व्यक्तिगत छवि से जाने जाते है व संजय यादव की भी पहचान कम नहीं है वही अभिषेक वर्मा अपने स्वच्छ छवि व ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते है. अभिषे वर्मा ने बताया की जनप्रतिनिधियों को वेतन भत्ता उचित व समय पर दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है साथ ही जनता व प्रतिनिधियों से जुड़े तमाम समस्याओं का भी जल्द निदान किया जाएगा. जीत के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया की जीत हमारी सुनिश्चित है बाकि सब प्रत्याशी चुनाव में दूसरे स्थान पर आने की होड़ में है प्रथम स्थान आने के लिए तो वो लोग सपने में भी नहीं सोच रहे हैं.■

– नमन

आदिवासियों और ईसाइयों को एकजुट करने में जुटी एनपीपी

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

आखिरकार भाजपा और एनपीपी के बीच बिहार चुनाव साथ-साथ लड़ने पर समझौता हो ही गया. दोनों ही दलों के नेताओं ने महसूस किया कि बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाने के लिए एक तरह की सोच रखने वाली पार्टियों को एक साथ आना बेहद जरूरी है. दिल्ली में अमित शाह, पीए संगमा और संजय वर्मा के बीच बातचीत में साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई और यह तय हुआ कि सीटों पर जुलाई के महीने में बात होगी. एनपीपी और भाजपा की बातचीत काफी लंबे समय से चल रही थी. तालमेल का मुद्दा निपटाने के बाद एनपीपी 16 अगस्त को दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा सम्मेलन पटना में करने जा रही है. इस सम्मेलन में खुद एनपीपी प्रमुख पी ए संगमा, अरविंद नेताम और किरोड़ीलाल मीणा शिरकत करेंगे. कुछ जानकार का मानना हैं कि एनपीपी की रणनीति है.आदिवासी, ईसाई, सिख, दलित और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने की है.16 अगस्त का कार्यक्रम इसी संदर्भ में किया जा रहा है. इस सम्मेलन में लगभग दस हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है. आदिवासियों को संगठित करने की जिम्मेदारी मानस लकड़ा और सुमीत सोरेन को सौपी गई है. ईसाइयों के बीच माइकल सैम्यूल काम करेंगे और सिख के बीच हरविंदर सिंह काम करेंगे. इसके अलावा अल्पसंख्यक मुसलमानों को संगठित करने की जिम्मेदारी इस्मान हलाल खोर को सौपी गई है. एनपीपी के प्रदेश प्रमुख संजय वर्मा कहते हैं कि 20 जून से हमारा विधानसभा स्तर पर सम्मेलन शुरू है. हमलोग जिला और प्रमंडल स्तर पर भी अपने लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं. वर्मा का दावा है कि एनपीपी का 16 अगस्त वाला कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा. उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है, और हमारी पार्टी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.■

गया में कांटे की टक्कर के आसार

प्रेम कुमार | राजू वर्णवाल

ऋषि लाल feedback@chauthiduniya.com

बिहार विधान सभा चुनाव के मद्देनजर गया शहर विधान सभा क्षेत्र में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है. मुख्य मुद्दा इस बार भी वही है पानी, बिजली, शहर का यातायात व्यवस्था में सुधार. इस विधान सभा क्षेत्र का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि भाजपा के प्रेम कुमार चार दफा गया शहर विधान सभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं और दो बार मंत्री भी रह चुके हैं, फिर भी गया की पुरानी मांगे जस की तस है. प्रेम कुमार अभी से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की ताल ठोंक रहे हैं. लेकिन हकीकत यह है कि प्रेम कुमार की राह इस बार गया में आसान नहीं दिख रही है. वह प्रतिकूल परिस्थितियों में घिरे नजर आ रहे हैं. ऐसे में अगर महागठबंधन से राज कुमार उर्फ राजू वर्णवाल निषाद मैदान में कूद पड़े तो प्रेम कुमार के लिए चुनौती और भी कड़ी हो सकती है.

क्षेत्र का राजनीतिक व समाजिक समीकरण राजू के अनुकूल माना जा रहा है. 2010 के चुनाव में प्रेम कुमार का मुकाबला जलालुद्दीन अंसारी सीपीआई उम्मीदवार से था. राजनीतिक हलकों में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जलालुद्दीन अंसारी के मैदान में उतरने से एक वर्ग विशेष के मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो जाया करता है जिसका लाभ भाजपा विधायक प्रेम कुमार को मिल जाता है. जब-जब जलालुद्दीन अंसारी या मंसूद मंजर सीपीआई पार्टी से मैदान में उतरेंगे. तब-तब भाजपा विधायक प्रेम कुमार की जीत होगी. मसूद मंजर फरवरी 2005 के चुनाव में 48099 मतों से हारे थे.

वहीं दूसरी तरफ अतिपिछड़ा आयोग के सदस्य प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी भी गया शहर के विधान सभा क्षेत्र के जदयू उम्मीदवार हो सकते हैं. चालीस हजार चन्द्रवंशी समाज के वोटों को लेकर प्रेमकुमार और प्रमोद कुमार में कड़ी टक्कर हो सकती है.■

पिछले अंक से आगे SBI PO PHASE 1 REASONING TEST

सुबोध कुमार, Director S.T.C., Motihari

11. E का पसंदीदा खेल कौन सा है:–
a) क्रिकेट b) बैडमिंटन c) बास्केट बाल d) लान टेनिस e) n.t
12. कर्मचारी–विभाग–पसंदीदा खेल का कौन सा संयोजन सही है:–
a) E-प्रशासन–क्रिकेट b) F- कार्मिक–लान टेनिस c) H-विपणन–लान टेनिस d) B-प्रशासन–टेबुल टेनिस e) n-t
13. G का पसंदीदा खेल कौन सा है:–
a) क्रिकेट b) बैडमिंटन c) बास्केट बाल d) लान टेनिस e) n.t

Input : Shop 17 table 20 53 oven desk 39
चरण I : 17 shop table 20 53 oven desk 39 II : 17 table shop 20 53 oven desk 39
III : 17 table 20 shop 53 oven desk 39 IV : 17 table 20 shop 39 53 oven desk
V : 17 table 20 shop 39 oven 53 desk

नीचे दिये गये Input के लिये उपर्युक्त चरण का पता लगायें

14. एक इनपुट का चरण II है. 15 yes 62 51 48 talk now gone चरण VI निम्न में से कौन सा होगा.
1. 15 yes 48 talk 51 now gone 62 2. 15 yes 48 talk 51 62 now gone
3. 15 yes 48 talk 51 now 62 gone 4. ऐसा कोई चरण नहीं होगा.
5. उपरोक्त में से कोई नहीं.
15. एक इनपुट का चरण III है. 21 victory 30 joint 64 47 all gone इसे पूरा करने में कितने चरण लगेंगे.
1. तीन 2. चार 3. छह 4. सात 5. इनमें से कोई नहीं.
16. Input 89 bind 32 goal house 61 12 joy- इसे पूरा करने में कितने चरण लगेंगे.
1. चार 2. पांच 3. छह 4. सात 5. इनमें से कोई नहीं.
17- Input save 21 43 78 them early 36 for- निम्न में कौन अंतिम से पहला चरण होगा.
1. VI 2. VII 3. VIII 4. V 5. इनमें से कोई नहीं.
18. कथन: आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धी के सामने विरोध प्रकट करने के लिये बहुत से सक्रीय राजनीतिक प्रतिभागियों ने प्रदर्शन कर व्यस्ततम समय में शहर में वाहनों के अवागमन को रोकने का निर्णय लिया है. कार्यवाहियां: A– सरकार को तत्काल देश में हर प्रकार के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये. B– शहर में वाहनों के आवागमन में सहायता के लिये शहर के पुलिस प्राधिकरण को शहर के सभी जगह अतिरिक्त बल तैनात कर देना चाहिये. C) राज्य प्रशासन को शहर में रहने वाले ज्ञात अपराधियों की निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिये.
1. केवल A 2. केवल B 3. केवल C 4. A और B दोनों 5. n.t
19. पिछले तीमाही के दौरान हुई भारी हानि के कारण एक बड़े प्राईवेट बैंक ने अपने एक तिहाई कर्मचारियों की छटनी का निर्णय लिया है. कार्यवाहिया : A– सरकार को एक अधिसूचना जारी कर आम जनता को इस बैंक के साथ सभी लेन–देन रोक देने को कहना चाहिये. B– सरकार को इस बैंक को अपने कर्मचारियों की छटनी नहीं करने के निर्देश देने चाहिये. C– सरकार को देश के केन्द्रीय बैंक को इस बैंक की गतिविधियों की छानबीन आरंभ कर रिपोर्ट देने के लिये कहना चाहिये.
1. कोई नहीं 2. केवल A 3. केवल B 4. केवल C 5. A और C
20. M, K की बहन है. D, K का भाई है. F, M की मां है. K का F से क्या संबंध है.
a) पुत्र b) पुत्री c) पुत्र या पुत्री d) जानकारी अधूरी है. E) इनमें से कोई नहीं.
21. नीचे दिये गये पांच में से चार एक समान हैं तथा एक समूह की रचना करते हैं. कौन सा उस समूह में नहीं आता है –
a) 35 b) 80 c) 45 d) 60 E) 75
निर्देश : 1. केवल I उत्तर देने के लिये पर्याप्त है. 2.– केवल II उत्तर देने के लिये पर्याप्त है. 3. या तो I या III उत्तर देने के लिये पर्याप्त है. 4. I या II मिल कर भी उत्तर देने के लिये पर्याप्त नहीं हैं. 5. I और II दोनों मिल कर उत्तर देने के लिये पर्याप्त हैं.
22. जोजेफ सप्ताह के किस दिन पैदा हुअ था.
I) जोजेफ का जन्म दिन उसकी बहन के जन्म दिन से एक दिन पहले है.
II) जोजेफ सप्ताह के तीसरे दिन पैदा हुआ था.
23.– M, P, D, K और R एक वृत के चारों ओर मध्य–बिंदु की ओर मुख किये बैठे हैं. P के तुरंत बाद कौन है.
I- M और R के बीच D बैठा है.
I- R के तुरंत बाद K नहीं है.

एकजुटता का मरहम है महागठबंधन

लालू यादव ने अपने पुराने अंदाज में राजद चले गांव-गांव बीजेपी करे कांव-कांव का नारा लगाते हुए कार्यकर्ताओं की भीड़ व जोश देखकर अपनी राजनीतिक कर्मभूमि छपरा से भाजपा को ललकारा. इस प्रकार अपने घंटे भर के संबोधन में लालू ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकताओं को कमर कसकर तैयार रहने का आह्वान किया. उन्होंने कार्यकताओं को खूब हंसाया और चेताया भी. उन्होंने कहा कि गत लोकसभा चुनाव इधर-उधर ताक झांक करने का नतीजा है कि हार हुई. लालू ने कहा कि लालू नीतीश एक हो गइल और भाजपा के सफाई हो गइल.

सुजीत कुमार

लंबे अर्से बाद छपरा की धरती पर राजद सुप्रीमो से लेकर महागठबंधन के बड़े नेताओं के लिए जुटी भीड़ हौसला अफजाई के लिए काफी थी. यह भीड़ न सिर्फ लालू प्रसाद को देखने-सुनने आई थी बल्कि आने वाले विधान सभा चुनाव के लिए एक संदेश लेने और देने आई थी. हालांकि मौसम ने राजनीति की तरह कुछ देर तक तपाया तो ठंडक का एहसास भी दिलाया.

जैसे ही लालू यादव मंच पर पहुंचे तो विधान परिषद चुनाव में, छपरा,सिवान और गोपालगंज प्रत्याशियों की जीत का संकल्प दिलाया गया और बात अगामी विधान सभा चुनाव तक पहुंच गई. विधान परिषद की जीत को विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बताया गया. नीतीश को भावी मुख्यमंत्री पेश करते हुए लालू यादव ने कहा कि रामविलास मौसम वैज्ञानिक है. उनको पहले ही एहसास हो जाता है कि कहां बारिश होने वाली है . लालू ने लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए लोक लुभावन वायदों की याद दिलाई साथ ही काला धन से लेकर खाते में लाखों जमा होने के सपनों का हवाला दिया.

लालू यादव ने अपने पुराने अंदाज में राजद चले गांव-गांव बीजेपी करे कांव-कांव का नारा लगाते हुए कार्यकर्ताओं की भीड़ व जोश देखकर अपनी राजनीतिक कर्मभूमि छपरा से भाजपा को ललकारा. इस प्रकार अपने घंटे भर के संबोधन में लालू ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकताओं को कमर कसकर तैयार रहने का आह्वान किया. उन्होंने कार्यकताओं को खूब हंसाया और चेताया भी. कहा कि गत लोकसभा चुनाव इधर-उंधर ताक झाक करने का नतीजा है कि हार हुई. लालू ने कहा कि लालू नीतीश एक हो गइल और भाजपा का सफाई हो गइल. यादव पोलिटिकल कास्ट है और भाजपा निरबंशी है. उक्त बातें लालू प्रसाद ने सारण प्रमण्डल छपरा जिला अन्तर्गत रामजयपाल कॉलेज परिसर में राजद के महागठबंधन प्रमण्डलीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कही. मौके पर पार्टी के पूर्वमंत्री बसावन भगत, इदित राय, भुवनेश्वर चौधरी, चन्द्रिका राय, मढौड़ा व छपरा विधायक जितेन्द्र राय, रंधिर सिंह सहित जाने- माने राजद के कई नेता मौजूद थे. प्रमण्डलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजद के बरिष्ठ नेता, महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने कहा कि गणेश परिक्रमा करने वाले कार्यकर्ताओं से सावधान और जमीनी लोगों की सुधि लेने का संदेश दिया. प्रभुनाथ की यह बात लोगों के दिल तक पहुंची और तालियां भी बजी. उन्होंने याद दिलाया कि 15 साल तक सत्ता में रहे लालू के इशारे पर प्रधानमंत्री चुनने की ताकत रहने के बावजूद आज मात्र 24 विधायकों की ताकत बची है. यह संकट है और संकट की घड़ी में परिवार की बैठक बुलाई गई है. बिहार विकास के रास्ते पर चल रहा था और इसे अवरुद्ध किया जा रहा है. उन्होंने स्वीकार भी किया कि कैसे नौजवानो ने फैलाये गये नारे के जद में आकर बड़े-बड़ों के कंधों का मैल उतार दिया. उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आयेंगे का नारा देकर सत्ता में आई भाजपा ने सबके लिए बुरा दिन ला दिया है.■

feedback@chauthiduniya.com

गोपालगंज में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

संजय

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर गोपालगंज में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस चुनाव को ट्रायल समझा जा रहा है. गोपालगंज राजद सुप्रीमो लालूप्रसाद का गृह जिला है. अब ऐसे में निकाय चुनाव लालूप्रसाद के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है. वहीं दूसरी तरफ जिले से पूर्व सांसद एवं लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव काली प्रसाद पाण्डेय के छोटे भाई आदित्य नारायण पाण्डेय के चुनाव मैदान में होने से काली प्रसाद पाण्डेय ने भी इसे प्रतिष्ठा की सीट बना लिया है.

गोपालगंज की इस सीट से जदयू के सुनील कुमार सिंह लगातार दो बार चुनाव में विजयी रहे हैं. इस बार टिकट नहीं मिलने से सुनील सिंह चुनाव मैदान में नहीं हैं. हालांकि इसके पूर्व राजद की कभी जीत यहां नहीं हुई है. जदयू से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा पहली बार चुनाव लड़ रही है. भाजपा प्रत्याशी आदित्य नारायण पिछले चुनाव में राजद प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. उन्हें भाजपा- जदयू उम्मीदवार सुनील सिंह से मुंह की खानी पड़ी थी. आदित्य नारायण पाण्डेय एक बार एमएलसी एवं एक बार एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं. इस बार के निकाय चुनाव में आदित्य के सामने राजद के महंत सत्यदेव दास हैं. उल्लेखनीय है कि निकाय चुनाव में सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, बी.डी.सी. मुखिया एवं वार्ड पार्षद कुल 3831 मतदाता हैं. उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए सभी प्रत्याशी हर संभव प्रयास कर रहे हैं. दोनों दलों के प्रत्याशी में पैसे खर्च करने में कोई पीछे नहीं है. भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष लखन कुमार तिवारी ने पार्टी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित मानते हुए कहा कि एनडीए हर हाल में जीतेगी.

भाजपा प्रत्याशी आदित्य नारायण पाण्डेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरह सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखता हूं. इस लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदाता मेरे साथ में खड़े हैं. आदित्य ने आपदा के समय में सहायता के लिए आपदा कोष की स्थापना करने की बात कही. उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों को भी वह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक विधायक या सांसद को मिलती हैं. पिछली बार चुनाव हारने के बाद भी मैं घर नहीं बैठा हमेशा जनता के सम्पर्क में रहा.■

feedback@chauthiduniya.com

स्थानीय निकाय चुनाव मुंगेर

कठिन लड़ाई में फंसे हैं सारे सूरमा

महागठबंधन के सभी घटक दल के सक्रिय कार्यकर्ता पुरानी बातों को भूलकर संजय प्रसाद की जीत निश्चित करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह कर रहे हैं. इसके अलावा राजद सांसद जयप्रकाश यादव जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी गजानंद शाही पूर्व विधायक प्रहलाद यादव, फुलेना सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष, सदस्य तथा महागठबंधन में विश्वास रखने वाले पंचायत प्रतिनिधि संजय प्रसाद सिंह के साथ हैं, इसलिए उनकी जीत को कोई काट नहीं सकता.

विनायक मिश्र

मुंगेर -जुमुई -शेखपुरा -लखीसराय स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. चौक चौराहे से लेकर गांव के चौपालों में हार जीत का गणित समझाया जा रहा है. संजय प्रसाद और पंकज एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं. मुकेश यादव भी इस चुनावी जंग में जीत हासिल करने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं. मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 की बहस पर गौर किया जाए. लोग कह रहे हैं कि यहां का चुनाव आमने-सामने का है. यूपीए महागठबंधन का मुकाबला सीधे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के साथ है. इस विधानसभा परिषद चुनाव में यहां से कुल ग्यारह प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं. लखीसराय, तेतरहट चौक पर दो प्रत्याशियों के बारे में चर्चा हो रही थी. एक पक्ष ने कहा की संजय प्रसाद की जीत निश्चित है. बहस के भागीदार गीता बाबू ने कहा कि संजय प्रसाद राजद, जदयू, कांग्रेस, सपा, कम्युनिस्ट समर्थित उम्मीदवार हैं. महागठबंधन के सभी घटक दल के सक्रिय कार्यकर्ता पुरानी बातों को भूलकर संजय प्रसाद को जीत निश्चित करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह कर रहे हैं. इसके अलावा राजद सांसद जयप्रकाश यादव जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी गजानंद शाही पूर्व विधायक प्रहलाद यादव, फुलेना सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष, सदस्य तथा महागठबंधन में विश्वास रखने वाले पंचायत प्रतिनिधि संजय प्रसाद सिंह के साथ हैं, इसलिए उनकी जीत को कोई काट नहीं सकता. इस पर बहस के एक श्रोता बिफर गए कहा देखते हैं, महागठबंधन क्या रंग लाता है? जिस महागठबंधन के कार्यकाल में पंचायत प्रतिनिधि उपेक्षित रहे और झूठे मुकदमों का शिकार बने. क्या इस दंश को झेलने के बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधि महागठबंधन में विश्वास करेंगे? तभी संजय प्रसाद की चुनावी गाड़ी पार्टी समर्थित दलों के झंडों को लगाए बहस स्थल के करीब पहुंची. लोगों में बहस का बढ़ा तापमान खिसक गया और सभी लोग मौन धारण करके अपने भाव को बदल डाला और संजय प्रसाद सिंह के पक्षकार होने के संकेत देने लगे. राजद विधान पार्षद की चुनावी अभियान की अगुवाई करने वाले गोपेश कुमार ने बताया की संजय प्रसाद ने सरकार से लदकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को सम्माजनक वेतन और भत्ता दिलाया. प्राप्त विकास मत की राशि को सामुदायिक विकास योजनाओं पर खर्च किया. इस बार मौका मिलने पर पंचाट के प्रतिनिधियों को हर अपेक्षा और पूरी की जाएगी.

पिछली बार मुंगेर, लखीसराय, जमुई एवं शेखपुरा विधान- परिषद स्थानीय प्रधिकरण निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 से कांग्रेसी उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने वाले पंकज कुमार सिंह कम उम्र के होने की वजह से तबके चुनाव में स्क्रूटनिंग के क्रम में छूट गए थे. इस बार भी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया है. महागठबंधन में कांग्रेस में शामिल हो जाने की वजह से वे कांग्रेसी प्रत्याशी नहीं

पंकज कुमार सिंह कम उम्र के होने की वजह से पिछले चुनाव में स्क्रूटनिंग के क्रम में छूट गए थे. महागठबंधन में कांग्रेस के शामिल हो जाने की वजह से वे इस बार कांग्रेसी प्रत्याशी नहीं हो सके फिर भी वे निर्दलय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं.

हो सके फिर भी अटल निश्चय और अपनी कर्मठता तथा युवा शक्तियों के सहयोग एंव सहानुभूति के बदौलत वे इस बार 2015 का विधान परिषद का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं. अपने नाम के आगे निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से पहली वरीयता करने के लिए पंकज कुमार सिंह जी-जन से लगे हैं. लखीसराय जिला के रहुआ गांव में जन्मे पंकज को राजनितिक कौशल की दक्षता दिल्ली में प्राप्त हुई है.दिल्ली में प्राप्त राजनीतिक अनुभव को वे निवार्चन क्षेत्र के प्रतिनिधियों को बताना चाहते है कि बिहार के उच्च सदन में पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे प्रतिनिधियों को पेंशन दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे, मुखिया को लोकसेवा का पूर्ण अधिकार और सुविधा दिलाएंगे, प्रतिनिधियों को झूठे मुकदमों में फंसाने पर अंकुश लगाने का पूर्ण सार्थक प्रयास करेंगे .वर्तमान एमएलसी का पांच साल का कार्यकाल विवादस्पद रहा है. प्रतिनिधियों के बीच उनकी उपस्थिति शून्य रही है. इसके विपरीत पंचायत प्रतिनिधि सौ फीसदी उपस्थित रहे हैं. अपनी जीत के बारे में उन्होंने बताया की जमुई क्षेत्र के एक कद्दावर नेता का उन्हें आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, लखीसराय जिले के पंचायत प्रतिनिधि उन्हें धरती पुत्र समझ प्रथम वरीयता दे रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

06 जुलाई –12 जुलाई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

जगेंद्र के परिवार को मुख्यमंत्री ने 30 लाख देकर चुप करा दिया

दबाव का समाजवादी पैंतरा

प्रभात रंजन दीन

जिंदा जला कर मारे गए पत्रकार जगेंद्र सिंह के परिवार को 30 लाख रुपये और दो सदस्यों को नौकरी देने की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जैसे ही घोषणा की वैसे ही फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी आ गई कि जगेंद्र ने ही खुद को आग लगाई थी. यूपी के डीजीपी को भी जैसे पहले से पता था, इसीलिए वे पहले से ही बोल रहे थे कि पत्रकार जगेंद्र सिंह ने आत्महत्या की है. मुख्यमंत्री को भी यह बात पहले से पता थी, इसीलिए वे राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे. इसीलिए सपा महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव शुरुआत से ही राममूर्ति का बचाव कर रहे थे. सपा प्रवक्ता शिवपाल यादव पत्रकारों को बुलाकर पत्रकार की हत्या के आरोप से राममूर्ति को बरी कर रहे थे. पुलिस पत्रकार हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर से आपराधिक छेड़छाड़ कर रही थी. पत्रकार की लाश का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट लगातार बदल रहे थे और रीढ़हीन मीडिया पत्रकार जगेंद्र सिंह को पत्रकार मानने से ही इनकार करने का प्रहसन खेल रहा था. पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या का इस तरह नियोजित पटाक्षेप हो गया. इस एक प्रकरण ने समाज को दिखाया कि लोकतांत्रिक सत्ता कितनी लोकतांत्रिक और मानवीय है और लोकतंत्र के पुर्जे कहां–कहां किस हालत में खड़े, पड़े और सड़े हैं.

लखनऊ के फॉरेंसिक प्रयोगशाला में ईश्वरत्व के गुण आ गए हैं. तभी प्रयोगशाला के कालद्रष्टाओं को यह दिख गया कि जगेंद्र को जलाया नहीं गया बल्कि उन्होंने ही खुद को आग लगाई थी. जगेंद्र की फॉरेंसिक रिपोर्ट का जो निष्कर्ष (खबर लिखे जाने तक) सामने आया है, वह जांच का निष्कर्ष कम, वीभत्स चुटकुला अधिक लगता है. लखनऊ फॉरेंसिक लैब के विशेषज्ञों ने बताया है कि जगेंद्र ने खुद को आग लगाई थी, क्योंकि उनकी छाती के बाईं तरफ आग से जलने के निशान पाए गए हैं. इन विद्वत विशेषज्ञों का तर्क है कि जगेंद्र का दाहिना हाथ सुरक्षित है और बायां हाथ जला है. अगर किसी ने जलाया होता तो दोनों हिस्सों में आग लगी होती. जगेंद्र दाहिने हाथ से काम करता था, इसलिए एक्सपर्ट्स ने यह कह दिया कि उन्होंने खुद ही आग लगाई थी. ऐसे भोथरे और बेहूदे तर्क देकर इतने गंभीर मामले की न्यायिक प्रक्रिया की ऐसी–तैसी करके रख दी गई. अब फॉरेंसिक जांच की विधिक भाषा में बात करें. कोलकाता और आगरा के फॉरेंसिक वैज्ञानिक कहते हैं कि दबिश, हमले और पकड़–धकड़ की आपाधापी के बीच किसी पर पेट्रोल उड़ेलने और आग लगाने से शरीर का कोई भी हिस्सा जल सकता है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सब्जेक्ट (जिसे आग लगाई गई) के कपड़ों पर उसे पकड़ने वालों की उंगलियों के निशान. जलने के बावजूद सब्जेक्ट के बचे हुए कपड़े के टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए ले जाया जाता है. दूसरे, खुद को आग लगाने पर बाकी लोग सब्जेक्ट को बचाने की कोशिश करते हैं. फॉरेंसिक जांच में सब्जेक्ट को बचाने की सारी प्रक्रिया की सूक्ष्म पड़ताल की जाती है. इसमें दुर्घटनास्थल पर खड़े लोगों के कपड़े और बचाव के लिए इस्तेमाल में लाए गए सामान (कंबल या कोई अन्य कपड़ा) को फौरन फॉरेंसिक जांच के लिए हासिल किया जाता है. खुद को आग लगाने या लोगों द्वारा हत्या के इरादे से तेल उड़ेलकर आग लगाए जाने, दोनों स्थितियों में पेट्रोल के जार, कैन या पीपे को जब्त कर उस पर बने उंगलियों के निशान की गहराई से जांच और मौजूद लोगों की उंगलियों के निशान से उसका मिलान कराया जाता है. सब्जेक्ट के साथ मौके पर मौजूद सारे लोगों की उंगलियों के निशान लिए जाते हैं. मृतक के जले हुए कपड़ों पर उंगलियों के निशान की जांच के लिए वैक्यूम मेटल डिपॉजिशन टेकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. हत्या के इरादे से किसी पर तेल छिड़क कर जलाए जाने के अपराध में दुर्घटना स्थल पर सब्जेक्ट को घसीटे जाने, उसे पकड़ कर दबोचे जाने, उसके साथ हाथा–पाई किए जाने के निशान सब्जेक्ट के शरीर के साथ–साथ मौके पर भी पाए जाते हैं. फॉरेंसिक जांच में इन सारी स्थितियों को शामिल किया जाता है. यहां तक कि घटना के समय सब्जेक्ट और बाकी लोग क्या बोल रहे थे, इसकी भी सूक्ष्म पड़ताल की जाती है. फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया में फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, क्लीनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट, फॉरेंसिक सोरोलॉजी एक्सपर्ट, फॉरेंसिक केमिस्ट और लैंग्वेज एक्सपर्ट/टैक्सिकोलॉजिस्ट, सब अपनी–अपनी जांच आधारित राय देते हैं. सब की राय अलग–अलग रहती है, बाद में वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा उसके गहन विश्लेषण के बाद अंतिम निष्कर्ष निकाला जाता है. विचित्र किंतु सत्य यह है कि जगेंद्र प्रकरण में फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी उपरोक्त शर्तें पूरी ही नहीं की गईं. फिर जांच कैसे पूरी हो गई और जांच का नियोजित निष्कर्ष कैसे परोस दिया गया? यह अहम सवाल सामने है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक इसकी गोपनीयता बनाए रखना कानून की शर्त होती है. इसका ख्याल फॉरेंसिक लैब ने नहीं रखा. जब प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने ही इसका ख्याल नहीं रखा तो, पुलिस का फॉरेंसिक लैब क्या रखेगा! महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि लखनऊ फॉरेंसिक लैब के पास अपेक्षित तकनीकी सुविधाएं और विशेषज्ञता उपलब्ध ही नहीं है.

अब आते हैं जगेंद्र के शव के अन्त्यपरीक्षण (पोस्टमॉर्टम) के साथ किए गए खिलवाड़ पर. इस बात की जांच कौन करेगा कि जगेंद्र की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तीन–तीन बार क्यों बदली गई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कई तकनीकी खामियां पाई गई हैं. डॉक्टरों ने पोस्टमॉर्टम के दौरान तीन बार मौत के कारण बदले. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ओवर राइटिंग और काट–छांट की गई. शाहजहांपुर के अस्पताल से लेकर लखनऊ में पोस्टमॉर्टम होने तक जगेंद्र के जलने का प्रतिशत भी बढ़ता गया. फॉरेंसिक जांच में भी ऐसे ही कई पोल दिखे हैं, जिनका खुलना बाकी है. अस्पताल से लेकर पुलिस तक, सब पहले ही यह कहने लगे थे कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट में जगेंद्र की मौत को खुदकुशी साबित करने जा रहे हैं. जगेंद्र का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने पहले उनकी मौत का कारण सेप्टीसीमिया लिखा फिर बाद में उसे बदल कर कॉर्डियो रेस्पिरेटरी इन्फारकेशन बताया. तीसरी बार डॉक्टरों ने जगेंद्र की मौत की वजह सेप्टीसेमिया के चलते पल्मॉनरी फेल्योर बताया. फॉरेंसिक लैब ने जगेंद्र की मौत होने और उसके पहले की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मौत की वजह रीनल शटडाउन माना है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक जगेंद्र की किडनी खराब हो गई थी. उसमें यूरिया का स्तर दोगुने से ज्यादा हो गया था. जगेंद्र के शरीर में जगह–जगह पस पड़ गया था और उनमें इन्फेक्टेड खून पाया गया. लिहाजा, फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने माना कि सेप्टीसेमिया और रीनल फेल्योर जगेंद्र की मौत का कारण बना. लेकिन जगेंद्र की मौत उन्हें जिंदा जला डालने की वजह से हुई, यह बताने से सभी मुकर गए.

पत्रकार जगेंद्र की हत्या को आत्महत्या साबित करने पर तुली उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस स्वाभाविक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जगेंद्र ने जब आत्महत्या ही की थी, तो 30 लाख का मुआवजा और परिवार के दो–दो सदस्यों को सरकारी नौकरी दिए जाने की अनुकंपा आखिर क्यों की गई? सियासतदान खुद को अत्यंत बुद्धिमान और नागरिकों को अत्यंत मूर्ख समझते हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से जगेंद्र के परिवार को 30 लाख रुपये और दो सदस्यों को सरकारी नौकरी दिए जाने की सदाशयता में और हत्यारोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के गुर्गों द्वारा जगेंद्र के परिवार को 20 लाख रुपये और सरकारी नौकरी देने की पेशकश में क्या फर्क है? दोनों बातें जगेंद्र के परिवार को प्रलोभन के दबाव में लेकर मामला वापस लेने के तिकड़म से ही जुड़ी हैं. 30 लाख रुपये और दो–दो सदस्यों को सरकारी नौकरी देख कर जगेंद्र के पिता सुमेर सिंह अब भले ही कुछ न बोलें, लेकिन अब तक वे यही कहते रहे हैं कि हत्या के आरोपी राममूर्ति वर्मा के जन–संपर्क अधिकारी और कुछ अन्य लोगों ने पैसे और नौकरी की पेशकश रखते हुए केस वापस लेने की हिदायत दी थी. जगेंद्र सिंह के बेटे राहुल ने भी कहा था कि मंत्री के लोगों ने मां और दादी को बुलाकर 20 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया था. मुख्यमंत्री ने इतना जरूर किया कि 20 के बजाय 30 लाख रुपये और एक के बजाय दो नौकरियां दे दीं. मुख्यमंत्री ने यह भी कृपा की कि जगेंद्र के परिवार की जमीन जो किसी दबंग के कब्जे में थी, उसे भी छुड़वाने का जिला प्रशासन को आदेश दे दिया. जगेंद्र के बेटे राहुल ने तब यह भी कहा था कि आखिरकार मेरे पापा को ही दोषी साबित कर दिया जाएगा. राहुल ने कहा था कि पुलिस सारे सबूत मिटा देगी और उल्टे मेरे पापा को ही दोषी बना देगी. इसीलिए हम मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. अब जगेंद्र के परिवार वालों ने यह मांग वापस ले ली है. अब मंत्री भी बच जाएगा और जगेंद्र की आत्मा भी धन्य हो जाएगी. जगेंद्र हत्याकांड ने सियासतदानों के असली रिश्ते का भी खुलासा किया है. सपा नेता राममूर्ति वर्मा की करतूतों पर लीपापोती में सपाइयों के साथ बसपाई भी लगे थे. बसपा के दो विधान परिषद सदस्यों की मुख्यमंत्री से हुई अंतरंग मुलाकातों ने भी पत्रकार हत्याकांड में खूब रंग दिखाया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जब रिपोर्ट अधूरी थी, तो सार्वजनिक क्यों किया

जब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट अधूरी थी तो वह सार्वजनिक कैसे हो गई? फॉरेंसिक-लैब के साथ-साथ राजनीतिक-लैब और पुलिस की चाटुकारिता-लैब सब तरफ से एक ही आवाज कैसे आने लगी कि पत्रकार जगेंद्र ने खुद को आग लगा ली थी? उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एके जैन को शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने मर्यादित तरीके से कहा कि फॉरेंसिक जांच की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के तरीके के बारे में कुछ कहा जा सकेगा. उन्होंने कहा कि हमें फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का एक ही हिस्सा मिला है. हम उसके दूसरे हिस्से का इंतजार कर रहे हैं. उसके बाद ही घटना की परिस्थितियों के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एके जैन इसके पहले ही यह कह चुके थे कि शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह ने खुद को आग लगा ली थी.

यूपी का अलग कानून, यहां डेथ स्टेटमेंट का महत्व नहीं

पत्रकार जगेंद्र हत्याकांड में यह साबित हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कानून अलग है. भारतीय संविधान के आलोक में बने कानून और उसके प्रावधानों की यूपी में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं. भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उत्तर प्रदेश में कोई महत्व ही नहीं है. कानून में डेथ स्टेटमेंट (मृत्यु पूर्व के बयान) को सबसे अहम माना जाता है. वह भी अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष बाकायदा रिकॉर्ड किया गया हो तो उसे साक्ष्य का सबसे ठोस पक्ष माना जाता है. पत्रकार जगेंद्र ने बूरी तरह जले होने के बावजूद मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए अपने बयान में राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के गुर्गों और पुलिस वालों द्वारा जलाए जाने की बात कही थी. इसके बाद लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद आईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के समक्ष भी जगेंद्र सिंह ने यही बयान दिया था. इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी शासन और प्रशासन को भेजी गई थी, लेकिन जगेंद्र के डेथ स्टेटमेंट को कोई अहमियत नहीं दी गई. जगेंद्र चीखता-चीखता मर गया कि मंत्री के लोगों ने पुलिस के साथ मिल कर उसे जिंदा जलाया है, लेकिन जगेंद्र की चीख शासन और नतमस्तक प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंची, जबकि पूरे प्रदेश और देश ने जगेंद्र की चीख सुनी और वह दारुण वीडियो रिकॉर्डिंग देखी. इन्हीं वजहों से जगेंद्र के परिवार को दी गई सरकारी मदद पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. अब तो नौकरशाह भी सत्ता-अराजकता के खिलाफ मुखर होकर सामने आ रहे हैं. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी व सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव एसपी सिंह और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा कि यह सरकारी कार्रवाई न्याय को खरीदने जैसा कदम है. प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए जांच को बेवजह लम्बा खींचा जा रहा है. इन अधिकारियों ने भी कहा कि अगर जगेंद्र के परिवार को मुआवजा पाने के योग्य माना जा रहा है, तो यह निश्चित है कि सरकार जानती है कि मंत्री और पुलिस वाले ही असली अपराधी हैं. लिहाजा, तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए न कि उसकी लीपापोती की जानी चाहिए. नौकरशाहों का भी कहना है कि राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को मंत्री के पद से हटाकर उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए था.

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

दुनिया पर छाया है मलिहाबादी दशहरी और चौसा का स्वाद

आमों पर रंग बिखेरने की तैयारी

सुरेन्द्र कुमार

लखनऊ के प्रसिद्ध मलिहाबाद क्षेत्र में आम की विभिन्न प्रजातियों की रंगीन किस्मों को तैयार करने व उन्हें और आकर्षक बनाने की दिशा मे क्षेत्र के प्रमुख आम उत्पादक समय-समय पर नई तकनीकी निकालने में प्रयासरत हैं. उनका मानना है कि अगर रंगीन प्रजातियों के आम के बाग विकसित हों तो दशहरी के लिए प्रसिद्ध मलिहाबाद आम फलपट्टी क्षेत्र रंगीन आमों के लिए भी मशहूर होगा. साथ ही इसका व्यावसायीकरण भी बढ़ेगा. पद्मश्री कलीम उल्ला खां बताते हैं कि हुस्नआरा प्रजाति के आम को उनके पूर्वज दो सौ वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से दो पौधे लाकर यहां रोपे थे. जिनको मदर प्लान्ट के रूप मे विकसित कर धीरे-धीरे सैकड़ों पौधे तैयार किये गये. इन पौधों को क्षेत्र की अन्य नर्सरियों ने अपनी पौधशाला में रोपित कर पौधों का उत्पादन शुरू किया. इस आम की लालिमा को वह दशहरी में लाने के लिए विभिन्न तरीके अपना रहे हैं. जिसमें उन्हें आगामी समय में सफलता अवश्य मिलेगी. सुर्खा जैसे अनेक लालिमा लिये हुये आमों की प्रजातियों को पूर्वजों ने ही विकसित किया था.

भाग्यवान नर्सरी के मालिक अहसन अजीज खां कहते हैं कि सुर्खा वर्मा व हुस्नआरा आदि प्रजातियों में गुठली छोटी करने व गूदा बढ़ाने के लिए वह अपनी नर्सरी में प्रयासरत हैं. रंगीन आम की प्रजातियों के पौधों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी नर्सरी का एक भाग सुरक्षित कर उसमें मदर प्लान्ट लगवाये हैं. जिनसे प्रतिवर्ष कई हजार पौध तैयार करेंगे.

मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व बागवानी बोर्ड के निदेशक इंसराम अली का कहना है कि फलपट्टी क्षेत्र के निवासियों के खाने कमाने का एक मात्र जरिया आम ही है. सरकारी उपेक्षा के चलते आम की कीमतों में निरन्तर कमी आती जा रही है. अतिवृष्टि व बढ़े जाला कीट के कारण इस वर्ष आम अपना साइज नहीं पकड़ सका. आम उत्पादकों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की फैक्ट्री स्थापित करनी चाहिए. जिससे आम से संबंधित विभिन्न उत्पाद यहां तैयार हो सकें. इससे आम उत्पादकों को लाभ के साथ बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा. इसके अलावा इस क्षेत्र को मैंगो टूरिज्म के रूप में विकसित कर आम के बागों में छोटी-छोटी झोपड़ियां बनवानी चाहिए, जैसे कि केरल में नारियल के बागों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. चार साल पहले उन्होंने प्रयास कर मलिहाबादी दशहरी को पेटेन्ट कराया था. लेकिन सरकारी उपेक्षा से इसका लाभ फलपट्टी क्षेत्र के बागवानों को नहीं मिल पा रहा है.

रंगीन प्रजातियों के आम बिखेरने लगे छटा

फलों का राजा आम धीरे-धीरे अपनी रौनक पर आता जा रहा है. दशहरी आम के साथ अन्य रंगीन प्रजातियों के आम भी पकने शुरू हो गए हैं. आकर्षक रंग रूप व स्वाद से भरपूर इन आमों के शौकीन इन्हें ढूंढने के लिए स्थानीय मंडी सहित आम के बागों में चक्कर लगाने लगे हैं. काफी ऊंचे दामों पर बिक रहे रंगीन किस्मों के आम व बहुत कम मात्रा में निकल रही डाल की पकी दशहरी सुबह मंडी आते ही शौकीनों व आम के चाहने वालों के कब्जे में हो जाती है. जो शौकीन डाल का पका आम खरीदने के लिए देर से मंडी पहुंचते हैं, उन्हें बैरंग वापस होना पड़ रहा है.

भारतवर्ष में मलिहाबादी दशहरी अपना अलग ही स्थान रखती है. यह अपने रंग, रूप, मिठास व खुशबू के लिए प्रसिद्ध है. वर्तमान में यह पेड़ों पर पकना शुरू हो गया है. हलांकि बाजार में अभी पूरी तौर पर उपलब्ध नहीं है. पाल का दशहरी आम बाजारों पर छाया है. अभी डाल में पके दशहरी आम का साइज छोटा है. जिसमें सुन्दरता व होने वाला लाजवाब स्वाद बरसात न होने के कारण नहीं है. कम मात्रा में डाल में पक रहे दशहरी आम के भाव आसमान छू रहे हैं. एक सप्ताह बाद भरपूर मात्रा में डाल का पका दशहरी आम बाजार में आने से इसके दामों मे गिरावट होने की संभावना है. जो पाल का पका दशहरी आम बाजारों में है, वह कुछ दिनों बाद बाजार से गायब हो जायेगा. हलांकि आम के बागों से 40 प्रतिशत कच्चा दशहरी आम टूटकर बिक्री के लिए दिल्ली, मुम्बई, इटावा, झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर, हरदोई, जालन्धर व दुबग्गा सहित विभिन्न मंडियों में जा चुका है. बाहर की मंडियों में बिक्री के लिए कच्ची दशहरी का जाना लगातार जारी है.

हुस्नआरा, रटौल, सुर्खा वर्मा, सुर्खा झाखड़बाग, गुलाबखास, टॉमी एटकिन्स व संसेशन जैसे नाम के आम भी पकना शुरू हो गये हैं. रंगीन प्रजाति के आम पकने के बाद ज्यादा टिकाऊ नहीं रहते. इसलिए आम उत्पादक अपने बागों में इन प्रजातियों के पेड़ तैयार नहीं करते. उपहार में देने या स्वयं के प्रयोग के लिए शौकीन बागवान अपने बाग में एक-दो पेड़ ही रखे हुए हैं. यह आम अपना आकर्षक रंगीन रूप लिये हुए सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. यह रंगीन किस्म के आम बहुत ही नाजुक होते हैं. पकने के बाद दो या तीन दिन ही इनका भंडारण किया जा सकता है. व्यावसायिक न होने के कारण फलपट्टी क्षेत्र मे रंगीन आमों का उत्पादन अल्प मात्र ही है. कम उत्पादन के चलते दशहरी की अपेक्षा इन रंगीन आम के दाम दोगुना से अधिक हैं. इसीलिए तोहफे के रूप में इन्हें भेंट किया जाता है. जहां कहीं रंगीन आम मिल रहा है, वह 800 रुपये प्रति पेटी की दर से बिक रहा है.

मलिहाबाद से ऑनलाइन दशहरी

लखनऊ के दशहरी आम की ऑनलाइन खरीदारी रंग ला रही है. शुरुआत में दशहरी के लिए बड़े शहरों से ही ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अलावा दक्षिण भारत और कई मार्केटिंग कंपनियां भी ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए सीधे मलिहाबाद से दशहरी आम मंगवा रही हैं.

आम की ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत आईआईटीयन प्रदीप कुमार सोनकर ने की थी. उन्होंने देखा कि किसानों को आम के सही दाम नहीं मिलते और वे कार्बाइड का भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. तब उन्होंने मलिहाबाद के अपने दोस्त अमित यादव के साथ किसानों को जागरूक करने की सोची. दोनों ने रहमानखेड़ा उपोष्ण बागवानी संस्थान से सहयोग लिया. संस्थान ने दोनों को कई बड़े आम उत्पादकों से मिलवाया. फिर मैंगोबागडॉटकॉम वेबसाइट शुरू की और इसके जरिए आम की बिक्री होने लगी. ऑनलाइन खरीद से किसानों को आम की करीब दोगुनी कीमत मिलती है. कोई बिचौलिया न होने से किसानों को भी लाभ है और कंपनी का मुनाफा भी निकल आता है. ग्राहकों भी अच्छे आम सही दाम पर मिलते हैं. अब तो बिग बाजार, स्पेंसर और वॉलमार्ट भी उनसे दशहरी आम खरीद रहे हैं. आम की डिलीवरी के लिए लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई सहित कई शहरों में सेंटर बनाए गए हैं. वे कुरिअर के जरिए लोगों तक आम पहुंचा देते हैं.

आनंद का फल और पुण्य का वृक्ष है आम

आम की गणना भारत के प्राचीनतम फलों में की जाती है. इस बात का पर्याप्त प्रमाण मिलता है कि आम के विषय में लोगों को छह हजार वर्ष से इसकी उपजाई जाने वाली प्रजातियों के विषय में जानकारी थी. भारत में आम का महत्व महज एक स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक फल के रूप में ही नहीं है, बल्कि प्राचीनकाल से ही आम का वृक्ष भारतीय संस्कृति, धर्म, सौन्दर्य, शैक्षिक एवं आर्थिक जीवन से जुड़ा रहा है. धार्मिक ग्रंथों में आम ब्रह्म का रूपांतर माना जाता है. आम की पत्तियां धार्मिक कर्मों, पुण्य और सरस्वती एवं शिव की पूजा अर्चना और सूखी टहनियां हवन की पवित्र अग्नि को प्रज्जवलित करने के लिए प्रयोग में लायी जाती हैं. वाल्मीकि रामायण, रामचरित मानस, महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में कई स्थानों पर इसका उल्लेख मिलता है. आम के प्रदत्त महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्राचीन कलात्मक कृतियों अजंता-एलोरा की गुफाओं और बौद्धस्तम्भों में चित्रकारी में आम का महत्व दिखता है. मध्यकालीन युग में भी आम की लोकप्रियता का उल्लेख है. मुगल बादशाह अकबर ने बिहार के दरभंगा में आम का एक बाग लगवाया था, जिसमें एक लाख वृक्ष लगाये गये थे. वह एक लाख बाग के नाम से अभी भी जाना जाता है. आइने अकबरी नामक ग्रंथ में आम की किस्मों तथा उनके गुणों का विस्तृत वर्णन मिलता है. आज आम की खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित मलिहाबाद क्षेत्र आम के लिए विख्यात है. भारत में आम की लगभग एक हजार से भी अधिक किस्में उपजाई जाती हैं.

-मृत्युंजय दीक्षित

घर में टोटा, विदेश का कोटा

इस बार मलिहाबाद के दशहरी और चौसा आम का स्वाद रूस के चखाए जाने की तैयारी है. मंडी परिषद दशहरी और चौसा आम को रूस के बाजारों में उतारने जा रहा है. इसके लिए राजधानी के मलिहाबाद स्थित मैंगो पैक हाउस में तैयारियां शुरू हो गई हैं. मंडी परिषद की एक्सपोर्ट सेल को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है, जो विदेशों के कारोबारियों से संपर्क कर उनसे डिमांड ले रहे हैं. पहले चरण में दशहरी का निर्यात किया जाएगा और उसके बाद सहारनपुर और लखनऊ का चौसा भी रूस भेजा जाएगा.

मंडी परिषद ने पिछले साल दुबई और सऊदी अरब समेत खाड़ी के अन्य देशों में आम का काफी निर्यात किया था. कुछ टन आम आस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और सिंगापुर भी भेजे गए थे. इन देशों को उत्तर प्रदेश से 170 टन से अधिक आम का निर्यात किया गया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया बनाम आरटीओ चुन्नीलाल

सन्तोष देव गिरि

उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया का विवादों से जुड़ा नाता खत्म नहीं हो रहा है. 20 साल पुराने एक मामले में अभी उन्हें न्यायालय द्वारा राहत मिले कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक और ताजा मामला उनके गले की फांस बन गया है. राज्यमंत्री एवं मिर्जापुर सदर सीट से विधायक कैलाश चौरसिया की हालत इन दिनों बिल्कुल पेड़ से गिरे तो खजूर पर अंटके जैसी हो गई है. इस मामले को लेकर राज्यमंत्री के गृह जनपद की राजनीति गरमा उठी है. राज्यमंत्री के खिलाफ तहरीर दर्ज न होने से परिवहन कर्मी आक्रोशित हैं, तो विपक्षी दलों सहित अन्य ने इसे राज्यमंत्री और सत्तापक्ष की दबंगई करार दिया है. कुछ संगठन राज्यमंत्री के पक्ष में पूरी तरह से डट कर खड़े हैं.

दरअसल ताजा मामला परिवहन अधिकारी मिर्जापुर के संभागीय चुन्नीलाल प्रजापति से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि राज्यमंत्री ने संभागीय परिवहन अधिकारी को अपने जनसम्पर्क कार्यालय में बुलाकर रुटीन रिश्वत की मांग की और इनकार करने पर उन्हें न केवल अपमानित किया बल्कि मारा पीटा भी. वाकया 12 जून का है. संभागीय परिवहन अधिकारी चुन्नीलाल प्रजापति के मुताबिक 12 जून को पूर्वाहन राज्यमंत्री के पीआरओ अरविंद श्रीवास्तव ने फोन कर उन्हें राज्यमंत्री के रेलवे स्टेशन स्थित जनसम्पर्क कार्यालय पर बुलाया. वहां जाने पर राज्यमंत्री ने दिनेश कुमार मालवीय को संभागीय परिवहन कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के बतौर कार्यभार ग्रहण नहीं करने देने का निर्देश भी दिया. संभागीय परिवहन अधिकारी चुन्नीलाल प्रजापति ने राज्य मंत्री को यह बताया कि इस सिलसिले में उच्च न्यायालय का आदेश है. लिहाजा, वे उनका आदेश मानने में असमर्थ हैं. इस पर राज्यमंत्री ने उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति दिखलाने को कहा. उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति देखते ही राज्यमंत्री बिफर पड़े और उसे फाड़ कर आरटीओ के मुंह पर फेंक दिया और मालवीय को किसी भी कीमत पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने देने की हिदायत दी. आरटीओ ने फिर असमर्थता जताई. इस पर गुस्साए राज्यमंत्री ने कहा कि मुझे तुम्हारे आफिस से पहले पैसा मिलता था, वह मुझे मिलना चाहिए. आरटीओ द्वारा मना करने पर वह गाली-गलौज करने लगे. जब उनके इन असंसदीय शब्दों को प्रतिरोध किया गया तो राज्यमंत्री के साथ ही उनके चहेते अरविंद श्रीवास्तव भी गाली-गलौज करने लगे और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिल कर आरटीओ चुन्नीलाल को मारने-पीटने लगे. पैसा न देने पर अंजाम बुरा होने की धमकियां भी दी गईं. चुन्नीलाल ने खुद ही इसकी पुष्टि की.

आरटीओ चुन्नीलाल प्रजापति ने इस सम्पूर्ण प्रकरण के बारे में विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया और उसी दिन कटरा कोतवाली पुलिस में राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया, डॉ. अरविंद श्रीवास्तव एवं एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी. लेकिन विडंबना यह है कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोतवाली में आरटीओ की तहरीर दर्ज नहीं की गई. हैरत यह है कि पुलिस तहरीर मिलने से ही इंकार कर रही है. जिले के आला अधिकारी भी इस मसले पर कुछ बोलने से बच रहे हैं. मामला राज्यमंत्री से जुड़ा हुआ है इसलिए कानून ठेंगे पर है. इससे विभागीय कर्मचारियों का आक्रोश गहराता जा रहा है. हड़ताल, काली पट्टी बांध कर विरोध जताने के साथ ही बैठक कर कर्मचारी आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं. संभावना जताई जा रही है कि इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी न केवल जिला बल्कि प्रदेश स्तर पर भी कार्य बहिष्कार जैसा कदम उठा सकते है. राज्यमंत्री पर कार्रवाई को लेकर संभागीय कर्मी किसी भी समझौते के मूड में नहीं है.

उधर राज्यमंत्री एवं नगर विधायक ने भी अपने पक्ष में लोगों को खड़ा करने के साथ संभागीय परिवहन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर उन्हें घेरने की रणनीति तैयार कर ली है. राज्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री को भी इस सम्पूर्ण प्रकरण से अवगत कराते हुए संभागीय परिवहन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और मोटर मालिकों से लेकर अन्य लोगों से की जा रही लूट के बारे में विस्तार से बताया है. संभागीय परिवहन अधिकारी चुन्नीलाल प्रजापति का कहना है कि जिस तरह से उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपमानित कर उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया उससे उन्हें काफी ठेस पहुंची है. राज्यमंत्री मुझसे वह कार्य कराना चाहते थे, जिसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, दूसरे वह पैसा देने के लिए कह रहे थे, क्या वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? आरटीओ ने बताया कि उन्होंने इस सम्पूर्ण प्रकरण से प्रदेश के परिवहन मंत्री सहित विभाग और शासन के उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया है और समुचित कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन ही कटरा कोतवाली में लिखित तहरीर दी गई, साथ ही डाक द्वारा भी तहरीर प्रेषित की गई है.

कहीं मामला पैसे का तो नहीं!

आरटीओ बनाम राज्यमंत्री के बीच छिड़े जंग को लेकर चर्चा है कि कहीं मामला पैसों को लेकर तो नहीं है. संभागीय परिवहन कार्यालय मालदार विभाग है. ऐसे ही नहीं राज्यमंत्री ने विभाग से पैसे की मांग की (जैसा कि आरोप है). कनिष्ठ लिपिक को ढाल बनाकर मामले को तूल दिया जा रहा है. हालांकि जहां तक भ्रष्टाचार का मसला है, तो संभागीय परिवहन विभाग ही अकेला नहीं है, जिले के कई ऐसे विभाग हैं, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं. कई ऐसे चेहरे भी हैं जो एक ही विभाग में लम्बे अर्से से कुंडली मारे बैठे हैं और राजनीति में भी लिप्त हैं. स्वास्थ्य विभाग इसमें अव्वल है. भ्रष्टाचार से लोगों की ऊब का ही नतीजा है कि मोटर ऑपरेटर यूनियन से लेकर व्यापारी संगठनों और स्थानीय नागरिक तक परिवहन विभाग के विरोध में खड़े हैं.

पहले से बदनाम चौरसिया का नाम

मिर्जापुर नगर विधायक और बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया व उनके समर्थकों का आतंक जिले में इस कदर बढ़ा है कि लोगों में दबी जुबान ही सही, तीखी प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है. आरटीओ की ही भांति राज्यमंत्री के समर्थक वाणिज्यकर कार्यालय में भी दो-दो हाथ कर चुके हैं. वाणिज्य कर कार्यालय के ज्वाइंट कमिश्नर एसपी सिंह ने तीन महीने पूर्व ही जिलाधिकारी और कमिश्नर सहित विभाग के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जब भी कोई कर चोरी का मामला पकड़ा जाता है, तो उसमें मंत्री का फोन आ जाता है और छोड़ने को कहा जाता है. ऐसे ही एक मामले में उन्हें पिछले वर्ष अपमानित होना पड़ा था. मंत्री और उनके समर्थकों ने उनके साथ हाथापाई भी की थी. वह मामला भी दबा रह गया था. लेकिन जब आरटीओ प्रकरण उजागर हुआ तो वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारी भी मुखर होकर विरोध करने में जुट गए हैं. 20 साल पहले डाकिये को मारने-पीटने के मामले में अदालत की ओर से सजा दिए जाने का मामला तो पूरा प्रदेश जानता ही है.

छोट-मोटे कई और मामले हैं जिनमें कैलाश चौरसिया पर आरोप लगते रहे हैं. कुछ मामले न्यायालय तक पहुंचे तो कुछ पुलिस ने दबा दिए. कुछ चर्चित मामलों में 12 जुलाई 2012 को मिर्जापुर के सिंचाई डाक बंगले में कमरे के आरक्षण को लेकर विवाद गरमा गया था. चौरसिया पर सीधा आरोप लगा था कि जब जनपद में इनका अपना भव्य आवास है तो मंत्री के नाम पर डाक बंगले में कमरा बुक कराने का क्या औचित्य है. दूसरा मामला मिर्जापुर नगर के त्रिमोहानी स्थित मंदिर से जुड़ी एक जमीन के मसले से सम्बद्ध है. मंदिर के ट्रष्टी ने कैलाश चौरसिया परिवार पर मंदिर की सम्पत्ति और जमीन हथियाने का आरोप लगाया था. जमीन से जुड़ा एक मामला जनपद के फतहां इलाके का भी है, जहां एक सिख परिवार की करोड़ों की जमीन मंत्री ने अपने परिवार के लोगों के नाम करा दी थी. लेकिन वे सत्ताधारी दल के चौरसिया हैं, इसलिए कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता. ■

feedback@chauthiduniya.com

26 साल में भी पूरा नहीं हुआ चिकित्सालय का निर्माण

आधे-अधूरे का उद्घाटन कराने की हड़बड़ी

चौथी दुनिया ब्यूरो

अयोध्या-फैजाबाद को मेडिकल कालेज का ख्वाब देखते हुए करीब तीन दशक बीत चुके हैं. दर्शन नगर चिकित्सालय की कवायद 26 साल पहले 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने शुरू की थी. उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया था. उस समय इलाके के लोगों को यह स्वप्न दिखाया गया था कि यह चिकित्सालय 500 शैय्याओं वाला होगा और उसमें तमाम आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी. मेडिकल कालेज के लिए इतनी क्षमता का चिकित्सालय होना अनिवार्य है. लेकिन सियासी मकड़जाल में फंस कर 500 शैय्याओं का यह चिकित्सालय 300 शैय्याओं पर सिमट कर रह गया. 26 साल से निर्माणाधीन इस चिकित्सालय का निर्माण अभी भी मुक्कमल नहीं हुआ है. फिर भी मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से चिकित्सालय का उद्घाटन कराने की सियासी-प्रशासनिक कवायद तेज है.

तीन सौ शैय्याओं के लिए वर्ष 2010 में लगभग 4 करोड़ रुपये के यंत्र व विभिन्न सामान आज तक नहीं खरीदे गए, उसका हिसाब-किताब लेने वाला कोई नहीं है. कई उपकरण खरीदे भी गए, तो उन्हें कमरों में डम्प कर दिया गया. 11 प्रतिशत के हिसाब से बैंक के ब्याज दर की गणना करें, तो इन पांच साल में लाखों रुपये का तो ब्याज के ही मद में राज्य सरकार के राजस्व को घाटा लगा. बीते 26 साल में प्रदेश में कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं. हर नई सरकार के आते ही अस्पताल का नाम बदलने की सियासत तेज हुई. बसपा शासनकाल में इस चिकित्सालय का नाम डॉ. अम्बेडकर चिकित्सालय करने की मांग उठी, तो सपा सरकार के आते ही इस चिकित्सालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड राजबली यादव के नाम करने की मांग की जाने लगी. फिलहाल 300 शैय्याओं वाले चिकित्सालय को केवल मंडल चिकित्सालय के नाम की पहचान दी गई है. फैजाबाद मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकारी खेमे में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन कराने की चर्चा सपा विधायकों द्वारा की जा रही है. हालत यह है कि डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति ने मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि नहीं देने का ऐलान कर रखा है. अब प्रदेश शासन से यह बात कही जा रही है कि दर्शननगर स्थित मंडल चिकित्सालय और फैजाबाद स्थित जिला चिकित्सालय को मिलाकर 500 शैय्याओं वाले चिकित्सालय की उपलब्धता प्रदान कर दी जाए. इसके बावजूद कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, प्रशासनिक भवन आदि की व्यवस्था कैसे की जाएगी, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है. शासन प्रशासन इस सम्बन्ध में चुप्पी साधे बैठा है.

मंडल चिकित्सालय दर्शननगर यदि आरम्भ भी किया गया, तो इसके लिए 55 चिकित्सक, 8 बेड पर एक नर्स, 4 ओटी में प्रत्येक के लिए 6 नर्स, 10 वार्ड ब्वाय, 3 स्टरलाइजन कर्मी, 4 फार्मासिस्ट, 8 लैब टेक्नीशियन, 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 8 चौकीदार/गार्ड, एक शिफ्ट में 30 स्वीपर और इतने ही सफाई कर्मी, प्रत्येक ओपीडी में एक-एक वार्ड ब्वाय, कार्यालय के लिए एक प्रधान लिपिक, दो वरिष्ठ सहायक और तीन कनिष्ठ सहायकों की आवश्यकता होगी. हालत यह है कि पूरे जिले में जितने भी चिकित्सालय हैं, वहां मानक से आधा भी डाक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट व अन्य कर्मचारी सुलभ नहीं हैं. ऐसे में मंडल चिकित्सालय के लिए इतने कर्मचारियों की व्यवस्था शासन प्रशासन कहां से करेगा इसका जबाव देने वाला कोई नहीं है.

फैजाबाद मंडल चिकित्सालय के निर्माण में बीते 26 साल के भीतर लगभग 80 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, ऐसा बताया जाता है. कार्यदायी संस्था अस्पताल का निर्माण कछुए की गति से भी धीमी गति से करा रही है. हर साल बजट एस्टीमेट में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है. मौजूदा समय में मंडल चिकित्सालय में केवल आकस्मिक सेवा कक्ष और आवासों का निर्माण ही हो पाया है. आन्तरिक विभाग का निर्माण अधर में लटका है. मंडल चिकित्सालय की भूमि का क्रय जिलाधिकारी के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति अधिकारी के माध्यम से किसानों की खतौनी के मुताबिक भुगतान देकर अधिग्रहित किया गया था. बीच में दो युवकों ने उच्च न्यायालय से स्टे लेकर आन्तरिक विभाग का कार्य बाधित करा दिया. उन युवकों का कहना था कि जहां आन्तरिक विभाग का निर्माण कराया जाना है वह भूमि मुस्लिम कब्रिस्तान की है. जबकि असलियत यह है कि चिकित्सालय परिसर के गेट के बगल में कब्रिस्तान है और जानबूझकर निर्माण बाधित करने के उद्देश्य से स्टे लिया गया.

यही हाल निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर का भी है. वर्ष 2008 में ट्रॉमा सेंटर निर्माण की स्वीकृति केन्द्र सरकार ने दी और 11 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया. सात वर्षों से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण ही हो रहा है, लेकिन अभी भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है. ट्रॉमा सेंटर में तीन वार्ड ऑर्थो, जनरल सर्जिकल, विशेष सर्जिकल और एक वातानुकूलित सघन केन्द्र का निर्माण कराया जाना है. ट्रॉमा सेंटर के लिए चिकित्सक और अन्य स्टाफ की व्यवस्था सरकार कहां से करेगी, क्योंकि नियमित चिकित्सक, नर्स व अन्य कर्मचारी की भर्ती पर रोक लगी हुई है. भर्ती पर रोक लगने के कारण ही सरकारी चिकित्सालयों में कर्मचारियों व चिकित्सकों का टोटा है और संविदा पर नियुक्ति करके किसी तरह चिकित्सा सेवा का कार्य कराया जा रहा है. जनपद में बनने वाले कई चिकित्सालय भी आधे अधूरे निर्मित हैं. मिल्कीपुर में 100 शैय्याओं वाला चिकित्सालय 2007 से ही निर्माणाधीन है. इसी विकास खंड के देवगांव में 50 शैय्याओं वाले चिकित्सालय के शिलान्यास की चर्चा है, जिसके लिए सरकार ने 13 करोड़ रुपये का धन आवंटित भी कर दिया है. इस चिकित्सालय के निर्माण के लिए ढाई करोड़ रुपये निर्माण निगम को मिल भी चुके हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा.

मेडिकल कॉलेज को लेकर जो योजना डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो. वीके गुप्ता ने 9 मई 2013 को पदभार ग्रहण करते ही बनानी शुरू की थी उसपर भी पानी फिर गया है. कुलपति वित्तीय अनियमितता के मकड़जाल ऐसे जकड़ते चले गये कि उन्हें मात्र चार महीने के कार्यकाल में ही त्यागपत्र सौंपना पड़ा. उसके बाद आये विश्वविद्यालय के नये कुलपति प्रो. प्रवीण चन्द्र त्रिवेदी के पदभार संभालने के बाद मेडिकल कालेज को लेकर उहापोह की स्थित बनी रही. बताते चलें कि डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में अर्से से प्रतीक्षारत एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज को फैजाबाद में स्थापित करने की मुहिम तेज कर दी गई थी. विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो. वीके गुप्ता ने क्षेत्रीय विधायक व मनोरंजन कर राज्यमंत्री तेजनारायण पांडेय पवन के साथ मिलकर परियोजना को साझा करते हुए फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा था. प्रस्ताव के अनुसार दर्शननगर में निर्माणाधीन 300 शैय्याओं वाले चिकित्सालय को उच्चीकृत कर 500 शैय्याओं में तब्दील करने का प्रस्ताव था जो विश्वविद्यालय को हस्तगत कराया जाएगा. अस्पताल मिल जाने से विश्वविद्यालय को लेक्चर थियेटर, लैब, ऑफिस ब्लॉक का ही निर्माण कराना होता, जिसके लिए इंजीनियरिंग कालेज के पार्श्व की भूमि का चयन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर देने की बात कही थी. मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर लगभग 365 करोड़ रुपये का व्यय आता, जिसका प्रस्ताव 29 जुलाई 2013 को भेजा गया था. पूर्व कुलपति का कहना था कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध है और सरकार ने 210 करोड़ रुपये देने की सहमति दे दी है. तत्कालीन कुलपति प्रो. वीके गुप्ता का दावा था कि सरकार का रुख यदि इसी तरह सकारात्मक रहा तो मेडिकल कालेज का निर्माण सितम्बर 2014 के अन्त तक आरम्भ करा दिया जायेगा. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आवेदन करने के बाद शिलान्यास करा दिया जायेगा. इस सन्दर्भ में पूर्व मनोरंजन कर राज्य मंत्री व क्षेत्रीय विधायक तेजनारायण पांडेय पवन का कहना है कि विश्वविद्यालय व स्वास्थ्य विभाग के पास मेडिकल कॉलेज के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है. पिछली सरकार की उदासीनता व सम्बन्धित संस्थानों से तालमेल के अभाव में फैजाबाद का मेडिकल कॉलेज वजूद में नहीं आ सका था.

असलियत यह है कि हवाईअड्डे के समीप स्थित विश्वविद्यालय की जिस 14 हेक्टेयर भूमि पर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है, वह मेडिकल कॉलेज के लिए अपर्याप्त और अनुपयुक्त है. इस भूमि के ठीक बगल में राजकीय हवाई अड्डा विस्तार की कवायद भी चल रही है. एयरोड्रोम पर फ्लाइंग क्लब चलाने के लिए एक कम्पनी को बसपा शासनकाल में अनुमति दी जा चुकी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

गाजियाबाद

सपा नेत्री ने नगर निगम में मचाया तांडव

चौथी दुनिया ब्यूरो

पति की फर्म के कार्यों की गुणवत्ता के विपरीत रिपोर्ट प्रशासन को देने से खफा एक सपा नेत्री ने अपने साथियों के साथ ग़ाजियाबाद नगर निगम कार्यालय में जमकर तांडव किया. इस मौके पर उनके साथ उनका सरकारी गनर भी मौजूद था. दरअसल विजय नगर के शांति नगर मोहल्ले में समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव ज्योति तिवारी के पति की फर्म गाजियाबाद डिस्टिक अरबन डेवलपमेंट एजेंसी(डूडा) की योजना के तहत निर्माण कार्य कर रही है. इन कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गत 29 मई को नगर निगम के अधिशासी अभियंता ए के सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता

व अन्य एक्सपर्ट स्टाफ शांति नगर गया. मौके पर पर्यवेक्षक दल ने पाया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के विपरीत सामग्री का प्रयोग किया गया है. इस अनियमितता की रिपोर्ट न केवल नगर निगम प्रशासन को भेजी गई, बल्कि इस संबंध में अनियमितता बरतने वाली फर्म को भी नोटिस भेजा गया. अधिशासी अभियंता ए के सिंह की इस कार्यवाही से खफा सपा नेत्री ज्योति तिवारी ने पहले तो उन्हें फोन पर धमकाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी, तो वह अपने कुछ सहयोगियों को साथ लेकर नगर निगम में अधिशासी अभियंता के चेंबर में घुस गईं, और पति की फर्म के खिलाफ भेजी गयी निगेटिव रिपोर्ट वापस लेने के लिए उनपर दबाव डालने लगीं. इस पर अधिशासी अभियंता ने कहा कि पर्यवेक्षक रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, मौके पर जो पाया गया है रिपोर्ट में वही लिखा गया है. इस पर सत्ता के नशे में चूर सपा नेत्री ने अधिशासी अभियंता को धमकाते हुए कहा कि वह नगर विकास मंत्री से उनका तबादला गाजियाबाद से बाहर करवा देंगी. शोर शराबा सुनकर नगर निगम में अफरा-तफरी मच गई. पड़ताल के बाद यह भी पता चला है कि सपा नेत्री अपने इलाके में नगर निगम में बिना टेंडरों की स्वीकृति के काम कराना चाहती थी. सपा नेत्री की इस मांग को जब अधिशासी अभियंता ने खारिज कर दिया, तो वह और खफा हो गईं.

अधिशासी अभियंता बोले-

इस संबंध में नगर निगम के अधिशासी अभियंता एके सिंह से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि मौके पर गुणवत्ता के विपरीत कार्य पाया गया, जो तय मानक के विपरीत थे. सपा नेत्री ज्योति तिवारी अधिशासी अभियंता द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बदलाव चाहती थी, जब मैने इनके इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, तो हंगामा पर उतर आयी. इसके अलावा निविदाओं के सापेक्ष स्वीकृति विचाराधीन है, इसके बावजूद वह अपने इलाके में कायदे कानून को ताक पर रखकर निर्माण आदि का कार्य कराना चाहती थी. श्री सिंह ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने शासन को लिखित में भी शिकायत भेज दी है.

सपा नेत्री ने आरोपों को नकारा-

इस संबंध में सपा नेत्री ज्योति तिवारी से बातचीत की गयी, तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया.

आर्या ने कार्यकर्ताओं का दर्द बयां किया

-राजकुमार शर्मा

हरीष सरकार के वरिष्ठ सहयोगी, कांग्रेस हाई कमान के जमाने तक पहली पंसन्द रहे यशपाल आर्या ने हरिद्वार से वापस आ कर निष्ठावान कार्यकर्ताओं का दर्द प्रकट किया. आर्या ने राज्य में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने का दर्द बयां कर सूबे में हरीश-किशोर जुगलबन्दी को आइना दिखाते हुए मिशन 2017 के लिए खतरे की घंटी बताया है. जब लोग किशोर के एक वर्ष पुरा होने पर गुलदस्ते भेंट कर रहे थे, तभी आर्या ने एक सच बताकर कर उन्हें धरातल पर ला दिया. हरीश रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री की कमान सम्भालते ही अपने राजनीतिक चातुर्य के चलते संगठन पर कब्जा करने के अभियान के तहत अपने लिए शुभ माने जाने वाले किशोर उपाध्याय की प्रदेष अध्यक्ष के पद पर तैनाती कराली. अर्से तक तिवारी खेमा के लिए चर्चित दलित नेता आर्या को गुडबुक में लेकर एक व्यक्ति एक पद फार्मूले की बात करके आर्या को प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिला कर उपाध्याय की तैनाती कराई गई. जमीन के कार्यकर्ताओं से गहरी पकड़ के चलते आर्या ने कांग्रेस को फर्स से अर्स तक पहुंचाया. आर्या के जमाने में संगठन में किसी की आवाज अनसुनी नही की गई. अब जब आर्या प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, उन्हे चारों ओर पार्टी को बुलन्दी देने वाले कार्यकर्ता केवल एक ही शिकायत कर रहे हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है. राज्य की कमान सम्भालने के बाद कई माह तक उपाध्यय ने अपनी कमेटी का ही गठन नहीं किया था, बाद में जब कमेटी बनी तो जम्बोजेट कमेटी बनी जिसमें गणेश परिक्रमा करने वालों को स्थान दिया गया. पदों का बंटवारा गुट की निष्ठा के आधार पर किया गया. आर्या का मानना है कि नेता ने अपने लोगों को पदों पर बैठाया, कांग्रेस के लोगों को पद देते समय कोई फिक्र ही नहीं किया. उनको राहुल, सोनिया में निष्ठा रखने वालों की फिक्र भी करनी चाहिए थी. किशोर उपाध्याय ने अपनी ताजपोषी का जश्न भी मनाया, मुख्यमंत्री रावत ने उन्हें चवलाई का लड्डू खिलाकर उनका मुख भी मिठा कराया. आर्या ने इन दोनों दिग्गजों के समक्ष कार्यकर्ता का सच बताकर कर उनका तो मजा ही किरकिरा कर दिया. आर्या ने कार्यकर्ताओं की आवाज बनने की जो साहस की उसे जमीन का कार्यकर्ता शुभ मान रहा है. आर्या ने जो बात अपनी जबान से निकाली है. इस पर कार्यकर्ताओं में विश्वास बढ़ेगा. प्रदेश के मुखियाओं को यह समझना चाहिए कि बात निकली है, तो दूर तक जाएगी. उत्तराखंड की जनता के दिल में आज भी कांग्रेस बसती है, इसका मूल कारण पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता की मेहनत है. ■

आनन्द साझा मंच बनाने में जुटे हैं

-रेनू शर्मा

कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है. यह कहावत साकेत बहुगुणा की हरकतों से आपदा के दौरान भारी बदनामी झेल चुके कांग्रेस के दिग्गज विजय बहुगुणा से सीख लेकर हरीश रावत ने जिस तरह अपने युवा पुत्रों को राजकाज से अलग कर दिया है. मुख्यमंत्री पिता की कार्यवाही से पूरी तरह बेरोजगारी झेल रहे हरीश के पुत्र इन दिनों समाज सेवा के लिए नेता पुत्रों का फोरम बनाने में जुटे हैं. युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रदेश कांग्रेस महासचिव आनंद रावत ने इसी अपने अभियान के तहत कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता पुत्रों से अपने रसूख का इस्तेमाल कर युवाओं में नशे की प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए आगे आने को कहा है. साथ ही सूबे की सरकार से ड्रग्स प्रिवेंशन बोर्ड बनाने में मदद का आह्वान किया है. ड्रग्स प्रिवेंशन बोर्ड के लिए अपनी ही सरकार पर दबाव बना रहे आनंद रावत इस मुहिम में प्रभावशाली नेता पुत्रों को साथ लेने में जुटे हैं. नेता पुत्र साथियों के नाम अपील में उन्होंने कहा कि ड्रग्स की समस्या उत्तराखंड के सामने चुनौती है. युवा थिनर एवं अन्य नशीले पदार्थ सूंघते हुए दिखाई देते हैं. कालेज के युवाओं में ड्रग्स का चलन चिंतनीय है. इसमें पुलिस और होमगार्ड के सिपाहियों की संलिप्तता चिंता को और बढ़ा देती है. इनसे राजनीतिक रसूख का प्रयोग करते हुए ड्रग्स प्रिवेंशन बोर्ड बनाने में मदद मांगी गई है. उन्होंने कहा कि बोर्ड का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उसके समकक्ष अधिकारी होना चाहिए और उसे जिले के कप्तान को समन करने का अधिकार हो. बोर्ड के माध्यम से ड्रग्स के खिलाफ अभियान और जिलों में डी-एडिक्शन सेंटर बनाए जाएं. बोर्ड का हेल्पलाइन नंबर आम जनमानस को ड्रग्स की समस्या निपटाने में सहायक बने. आनंद रावत की इस मुहिम में फिलहाल एक नेता पुत्र जुड़ गए हैं. इनकी अपील के समर्थन में विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता हरबंस कपूर के पुत्र और भाजयुमो के पदाधिकारी अमित कपूर ने हस्ताक्षर किए हैं. हिमालयी राज्य उत्तराखंड में सूर्यास्त पहाड़ मस्त की कहावत आज भी बहुत चर्चित है. जनता की सेहत को बर्बाद करने वाला नशा राजनीतिज्ञों के लिए कितना लाभप्रद है, इसका एक उदाहरण भाजपा के दिग्गज नेता जनरल भूवन चन्द्र खण्डूरी को मिली कोटद्वार सीट की हार से समझा जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी ने जब जनरल खण्डूरी है जरूरी का नारा दिया, इस चुनाव को वही खुद हार गए. इस हार के लिए जब जनरल से चौथी दुनिया ब्यूरों ने सच्चाई को जानना चाहा, तो जो सच सामने आया वह यह था कि नशा न मिलने के कारण जनता ने बाजी पलट दी. सर्द मौसम ने भाजपा की राजनीति को ही ठंडा करके रख दिया. नेता पुत्र इस बर्बादी के उन्मूलन के लिए एक मंच पर अपनी राजनीतिक क्षमता का प्रयोग कर स्वस्थ्य समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए यह एक अभिनन्दनीय कदम होगा. इस कड़वी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता की वे लोग अपनों के ही आंख कि किरकिरी बन जाएंगे. ■

भूल सुधार

चौथी दुनिया के 29 जून से 05 जुलाई के अंक में पृष्ठ-18 पर धार्मिक क्षेत्र की उपेक्षा पर बढ़ रहा रोष शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में लेखक का नाम भूलवश गलत प्रकाशित हो गया. इस रिपोर्ट के लेखक पाटेश्वरी प्रसाद हैं. इस भूल के लिए हम खेद प्रकट करते हैं.